

ज्वलंत मुद्दा
ईंधन की कीमत

राज्य की दशा-दिशा
उभरता असम

रोहिणी आयोग
कोटे में कोटा!

10 मार्च, 2021

40 रुपए



इंडिया टुडे

कौन है राजद्रोही?

केंद्र और राज्य सरकारें असंतोष को दबाने
के लिए किस तरह राजद्रोह समेत बेहद
सख्त कानूनों को लागू कर रही हैं



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

INDIA
TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY



DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON



प्रधान संपादक की कलम से

कहावत है न कि आपके पास बस हथौड़ा ही हो तो हर चीज कील नजर आने लगती है। सबसे ज्यादा यह उन क्रूर कानूनों के मामले में सच है जिनका इस्तेमाल सरकार असहमति को कुचलने के लिए कर रही है। इन कानूनों में प्रमुख है भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, जो राजद्रोह को सख्ती से दबाने के लिए तैयार की गई थी। इस कानून के तहत ऐसे 'संकेत, दृश्य निरूपण, बोले या लिखे शब्द, जो घृणा या मानहानि उत्पन्न कर सकते हों या सरकार के प्रति अलगाव को उकसाते या उकसाने का प्रयत्न करते हों', राजद्रोह के बराबर हैं।

धारा 124ए सरकार के टूलकिट में सबसे कठोर कानूनों में से है। यह तथाकथित तौर पर 'राज्यसत्ता के खिलाफ अपराधों' की उस तिकड़ी का हिस्सा है जो उसे विश्वासघात, राजद्रोह और विद्रोह से बचाने के लिए तैयार की गई है। भारत के तत्कालीन औपनिवेशिक आकाओं ने इसे अंतिम और निर्णायक हथियार के तौर पर गढ़ा था और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के लिए उदारता के साथ इसका इस्तेमाल किया था। हाल के सालों में यह कानून, अकेले अपने दम पर या दूसरे कानूनों के साथ मिलकर, डर और उन्माद से भरी राज्यसत्ता के हाथों में असहमति को दबाने के लिए पहला और अव्वल हथियार बन गया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम)

कानून (यूपीए), 1967; राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए), 1980; जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून (पीएसए), 1978; और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए), 2002, इन सभी का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये सरकार को मुकदमा चलाए बगैर हिरासत में रखने का अधिकार देते हैं।

सरकार की तरफ से लोगों के खिलाफ दाखिल राजद्रोह के मामलों की संख्या में हाल के सालों में उछाल आया है और ये 2016 में 35 से बढ़कर 2019 में 93 हो गए, 2015 में पाटीदार आंदोलन के नेताओं, 2017 में जाट अशांति से जुड़े लोगों, 2017 में ही गुर्मीत राम रहीम सिंह को सजा का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों, 2018 में झारखंड के पत्थलगढ़ी आंदोलन के आदिवासियों और 2019 में नागरिकता (संशोधन) कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकारों ने सतही आधारों पर राजद्रोह कानून का सहारा लिया है और देखिए किन लोगों पर लगाया गया है—53 साल का एक शख्स जिसने एक वीडियो बनाकर इनवर्टर बनाने वाली कंपनियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया, बेंगलूरु की एक लड़की जिसने राजनैतिक रैली में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया, या कर्नाटक के उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका जिसने सीए-एनआरसी के खिलाफ नाटक का मंचन किया। इस कानून का दुरुपयोग मालूम देने वाला सबसे हाल का उदाहरण 14 फरवरी को तथाकथित 'टूलकिट' मामले में बेंगलूरु की 21 वर्षीया जलवायु ऐक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस ने दिशा और दो अन्य व्यक्तियों पर खालिस्तान-समर्थक धड़े—पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन—के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया और उन्हें दिल्ली में किसानों की रैली के दौरान 26 जनवरी की हिंसा से जोड़ने की कोशिश की। जमानत मंजूर करते हुए एडिशनल सेशन जज धर्मेन्द्र राणा ने कहा, "सरकारों के आहत अभिमान की देखभाल के लिए राजद्रोह के अपराध का सहारा नहीं लिया जा सकता।"

राजद्रोह से जुड़े ज्यादातर मामलों की यही परिणति हुई है। मामलों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन दोष सिद्ध होने की दर में तेज

कमी आई है और यह 2016 से 2019 के बीच 33.3 फीसद से गिरकर 3.3 फीसद पर आ गई। ऐसा भी लगता है कि ज्यादातर मामले वैध आधार के बगैर, या तो कानूनी निरक्षरता या जाने-बूझे दुरुपयोग की वजह से दाखिल किए जाते हैं। चूंकि राजद्रोह संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है, इसलिए किसी भी शख्स को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है। सजा में तीन साल से लेकर ताउम्र कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। इतना ही नहीं, धारा 124ए से आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित हो जाता है और उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ता है। हकीकत में दोष सिद्ध होने की कम दर को देखते हुए प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।

परेशानी पैदा करने वाले आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए तमाम सरकारें क्रूर कानूनों का इस्तेमाल करने की दोषी रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने राजद्रोह के मामलों का डेटा 2014 के बाद ही प्रकाशित करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के विषय में दो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं: 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य। पहले फैसले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार की तस्दीक की थी कि सरकार या उसके उपायों की आलोचना राजद्रोह के दायरे से बाहर है, लेकिन उसने यह भी कहा था कि हिंसा उकसाने का रुझान राजद्रोह है। अब रुझान ढीला-ढाला शब्द है और सयाने वकील इसकी कई तरह से व्याख्या कर सकते हैं। बलवंत सिंह मामले में अदालत ने उन सभी लोगों को बरी कर दिया जिन पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थक नारे लगाने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। यही अस्पष्टता दुरुपयोग की गुंजाइश देती है। साफ है कि राजनीतियों और सरकार की आलोचना करना या नारे लगाना गंभीर संकट को दावत देना नहीं होना चाहिए, जैसा कि हाल में हुआ है।

बेशक राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता सर्वोपरि है और इनकी रक्षा के लिए कानूनों की जरूरत है। चूंकि ऐसा करने के लिए बहुत-से कानून हैं, इसलिए शायद अब वक्त आ गया है जब राजद्रोह से जुड़ी आइपीसी की धारा 124ए को संशोधित करके इसे हमारे लोकतंत्र के ज्यादा अनुरूप बनाना चाहिए।

हमारी आवरण कथा "कौन है राजद्रोही?", जो डिप्टी एडिटर कौशिक डेका ने लिखी है, असहमति पर राज्यसत्ता के कड़े प्रहार के बढ़ते और चिंताजनक रुझान की पड़ताल करती है। आलोचना, असहमति और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किसी भी धड़कते हुए लोकतंत्र की बानगी और कसौटी हैं। भारत को अपनी लोकतांत्रिक साख पर गर्व है और ठीक ही है। हम मजबूत और आत्मविश्वास से भरे देश हैं जिसे बीते सात दशकों से ज्यादा वक्त से अपनी सरकारों को चुनने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है। इस पर सरकार के किसी भी गैरवाजिब काम का दाग नहीं लगना चाहिए। आखिरकार नागरिकों को भी उतनी ही रक्षा की जरूरत है जितनी सरकार को है।

अरुण पुरी
(अरुण पुरी)



9 मार्च, 2016 का आवरण

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वकास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना),
रोहित पारेहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा
(भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित राय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदिप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत,
चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपेक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ),
उषेंद्र सिंह (बेंगलुरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंदनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशन)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)



वर्क: 35; अंक: 15; 4-10 मार्च, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय: लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- ग्राहकी चंदा भेजें: इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- ग्राहक सेवा: कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं.: 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइन से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900.
- (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- सर्कुलेशन कार्यालय: लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- इंपेक्ट कार्यालय: 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेले (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय: ए1-ए2, एनके सेंटर, विनूज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-22183335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमित्त प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निवारण दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और यमसोन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा



आवरण कथा

राजद्रोही कौन?

राजद्रोह कानूनों का दुरुपयोग किस तरह से असहमति व्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी गला घोट रहा

14

पेट्रोल के दाम

36 जेब से जुड़ा ज्वलंत मसला

ईंधन की आसमान छूती कीमतें महंगाई में आग लगा सकती हैं, और उपभोक्ता खर्च में कटौती को मजबूर हो सकते हैं

कोविड टीकाकरण

28 उम्मीद के साथ अंधेरी भी

वितरण और टेक्नॉलोजी को लेकर समन्वय और संवाद की कमी के चलते कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा

रोहिणी कमिशन

30 आरक्षण की चुनावी बिसात

ओबीसी को कई उपश्रेणियों में बांट 27 फीसद आरक्षण में वंचित अति पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने को रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना

राज्य की दशा-दिशा: असम

39 भविष्य की राह का महा सेतु

असम में विकास विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग क्षेत्र में तेजी से दिखाई देने लगा है



सुर्खियां: गोडावण

12 परिदों की हिफाजत

दुर्लभ प्रजाति के गोडावण पक्षियों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए राजस्थान सरकार खास उपाय कर रही

आवरण फोटो: राजवंत रावत

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवोकेटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.



पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वजनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशकों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

सुर्खियां



बंगाल की
जंग

श्रद्धा का सबब

अमित शाह 18 फरवरी
को भारत सेवाश्रम संघ में
आरती करते हुए

मंदिरों की दौड़

रोमिता दत्ता

भाजपा नेताओं के लिए किसी भी राज्य में मंदिरों और आश्रमों में हाजिरी लगाना, बेशक एक आम प्रथा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव अभियान में इस व्यग्रता और प्रतिबद्धता ने नए स्तर को छुआ है। और सिर्फ राम और हनुमान (या पार्टी के अधिक कट्टर समर्थक उन्हें बजरंग बली कहना ज्यादा पसंद करते हैं) के मंदिरों में नहीं बल्कि नेता, खासकर भाजपा और संघ के वीवीआइपी नेता, अब अपने मार्ग में पड़ने वाले काली और दुर्गा के मंदिरों में भी रुककर मत्था टेक रहे हैं।

‘उत्तर भारतीय’ ‘जय श्री राम’ नारे के जवाब में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से ‘जय मां काली’ और

‘जय मां दुर्गा’ के नारे लगाने के बाद माता के मंदिरों में हाजिरी लगाने की भाजपा नेताओं की होड़ ज्यादा शुरू हुई है। दुर्गा और काली, बंगाल में घरेलू देवता हैं और एक भक्त बंगाली हिंदू के लिए रोजमर्रा की पूजा और शब्दावली से कहीं बढ़कर हैं। यह ममता की रणनीति भी थी— भाजपा को एक ऐसे बाहरी आक्रमणकारी के रूप में पेश करना जो राज्य की सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रही है।

भाजपा ने जल्द ही दीदी की योजना भांप ली और उसकी काट के लिए जोर-शोर से दुर्गा पूजा मनाना शुरू किया। कोलकाता में अक्टूबर 2020 में भाजपा-आयोजित पहली समुदायिक दुर्गा पूजा हुई, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कोई

भी कोई मंदिर नहीं छोड़ा है—दक्षिणेश्वर, तारापीठ, कंकालीताल—हर प्रमुख/छोटे मंदिरों ने भाजपा के बीआइपी नेताओं की मेजबानी है (आश्रमों की यात्राएं भी नहीं भूलनी चाहिए, जिसमें रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, सागर द्वीप स्थित कपिल मुनि का आश्रम शामिल हैं और यह सूची लंबी है)। सूत्रों का कहना है कि यह महज कोई संयोग नहीं है कि जब मोदी ने 10 दिसंबर को उज्ज्वेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ अपने आभासी शिखर सम्मेलन के लिए लॉग ऑन किया, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर की एक तस्वीर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से लगी थी।

22 फरवरी को रेल मंत्री पीयूष गोयल कोलकाता आए और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के लिए नए मेट्रो मार्ग, जिसमें कालीघाट भी एक स्टेशन है, को प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की। भाजपा दो अहम काली मंदिरों को जोड़ने वाली 62 मिनट की मेट्रो की सवारी को बंगाल के लिए ‘पीएम मोदी के उपहार’ के रूप में प्रचारित कर रही है।

पार्टी ने बंगाल के 23 जिलों के 100 से अधिक मंदिरों, मठों और आश्रमों की सूची तैयार की है, जो चुनाव अभियान के दौरान फोकस में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा क्रमशः दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में दर्शन के बाद अपने अभियान शुरू कर चुके हैं। पिछले तीन महीनों में, वे लगभग एक दर्जन बार बंगाल के एक छोर से दूसरे छोर को नाप चुके हैं, और हर दौरे में मंदिरों की प्रमुखता से यात्राएं हुई हैं। पूर्वी मिदनापुर निवासी अमित बारिक राणा कहते हैं, “भाजपा ने मंदिरों पर अपना होमवर्क किया है। जिलों में, उन्होंने उन मंदिरों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनका ऐतिहासिक महत्व है पर वे ज्यादातर उपेक्षित ही रहे। पश्चिम मिदनापुर में महामाया मंदिर 17वीं शताब्दी का है और सिद्धेश्वरी मंदिर नौवीं शताब्दी का है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री की यात्रा से पहले ज्यादातर लोगों ने इन मंदिरों के बारे में शायद ही सुन रखा हो।”

राणा जैसे लोग, जो महामाया (काली) की पूजा करते हैं, वे अब ‘जय श्री राम’ को लेकर भी समान रूप से सहज हैं। राणा पूछते हैं, “वास्तव में, पूर्वी मिदनापुर में जय श्री राम अभिवादन का एक तरीका बन गया है। अगर शाह और नड्डा बंगाल में आकर ‘जय मां काली, जय मां दुर्गा’ कह सकते हैं, तो उनके नारे लगाने में क्या हर्ज है?” यहां तक कि पूर्वी मिदनापुर के शीर्ष टीएमसी नेता अखिल गिरि, भी इस आशंका में कहीं भाजपा को इसका फायदा न मिल जाए, ‘हरि नाम’ संकीर्तन (भगवान विष्णु की प्रार्थना करने वाली धार्मिक सभाएं) प्रायोजित/आयोजित कर रहे हैं।

पूर्वी मिदनापुर के एक अन्य निवासी अमिया जना कहते हैं, “टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने पूर्वी मिदनापुर में महर्षि नरेंद्र विद्या मंदिर के लिए 6 लाख रुपए का दान दिया। इन स्कूलों की लोगों के बीच एक मजबूत पैठ है।”

बर्धमान, हुगली, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में भी ऐसी ही भावनाएं महसूस की जा सकती हैं, जहां लोगों की पूजा और अनुष्ठानों में भागीदारी कई गुना बढ़ गई है। लोग इस धार्मिक उत्साह का असल कारण नहीं बता पाते हैं, लेकिन वे इससे सहमत हैं कि दो प्रमुख दल हिंदुओं को लुभाने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी चुनौती देने वाली भाजपा ने टीएमसी के 40 फीसद हिंदू वोटों की तुलना में 57 फीसद हिंदू वोट हासिल किए।



एएनआइ

“

पहले उन्हें (अमित शाह) सरस्वती श्लोक सीखने के लिए कहो. उन्हें यह भी नहीं मालूम कि मां दुर्गा कौन हैं और वे बंगाल की राजनीति करने का ख्वाब देख रहे हैं”

ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

शुरुआत

भाजपा के सूत्रों का कहना है कि आंतरिक सर्वेक्षण बताते हैं कि पार्टी सही रास्ते पर है—राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष है और यह भावना भी है कि उसका झुकाव मुसलमानों के प्रति बहुत अधिक है और हिंदुओं को प्रति पक्षपाती है। शाह अपनी रैलियों में इस बात पर जोर देते रहते हैं कि “राज्य में तीन तरह का कानून चलता है—भतीजे के लिए (ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी) एक कानून है, वोट बैंक (मुस्लिम) के लिए कुछ और कानून है, और शेष के लिए कुछ और।” उनकी इस बात की उन लोगों के बीच थोड़ी चर्चा है जो यह महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है।

कोलकाता के गोलपार्क के निवासी और पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट के.डी. मुखर्जी कहते हैं, “हम धर्मनिरपेक्ष होने का कितना भी दावा करते हों, पर यह अखरता है जब हम सरकार को किसी विशेष समुदाय को विशेष लाड़-दुलार करते देखते हैं। एनआरएस मेडिकल कॉलेज में

जूनियर डॉक्टरों पर हमला हुआ था और ममता उल्टे विरोध कर रहे हड़ताली डॉक्टरों पर ही बरस पड़ीं जबकि हड़दंगियों (कथित रूप से मुस्लिम) को गिरफ्तार करने में हिचक दिखाई दी...यह घटना उन कई मामलों में से एक है जहां सरकार के पूर्वाग्रह स्पष्ट नजर आते हैं."

प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि टीएमसी की तुष्टिकरण की राजनीति राज्य के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है. उन्होंने तीन साल पुरानी घटना याद दिलाई जब 2016-17 में बंगाली हिंदुओं को दुर्गा पूजा विसर्जन की अनुमति के लिए अदालत के दरवाजे तक खटखटाने पड़े. (टीएमसी ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति को एक दिन के लिए रोक दिया था क्योंकि उस साल मुहर्रम के ताजिए जुलूस भी उसी दिन निकलने थे. हिंसक झड़प की आशंकाओं को रोकने के लिए उस दिन मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई). प्रधानमंत्री ने कहा, "इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, और वह राजनीति वोट बैंक की है...यह सबका साथ, सब का विकास नहीं, तुष्टिकरण का प्रयास है." कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो. शोभनलाल दत्ता गुप्ता कहते हैं, "चुनावी अभियान आगे किधर जाएगा इसे समझना मुश्किल नहीं है. इस जंग में ध्रुवीकरण चरम पर होगा."

जमीनी तैयारी

इन मुद्दों के लिए आधार तैयार करने में आरएसएस की बड़ी भूमिका है. मिसाल के तौर पर, उत्तर बंगाल में भाजपा और संघ परिवार संगठन 1998 से ही करीबी के साथ काम कर रहे हैं. वे एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम और क्रीड़ा भारती जैसे संघ संचालित प्रतिष्ठानों के छात्रों के जरिए ग्रामीणों में मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं. कूचबिहार में चाय बागान के श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट राजेन अधिकारी कहते हैं, "संघ ने कूचबिहार और अलीपुरद्वार के आदिवासियों के बीच दशकों काम किया है. अलीपुरद्वार में रवा (आदिवासी समुदाय) अब हिंदू त्योहार मनाते हैं, महिलाएं शादीशुदा हिंदू महिलाओं की तरह सिंदूर लगाती हैं और शन्खा (शंख की चूड़ियां) पहनती हैं. चाय बागान श्रमिकों की घोर गरीबी का लाभ उठाते हुए, आरएसएस अपनी सामाजिक गतिविधियों के जरिए मूलनिवासी जनजातियों का विश्वास जीतने में सफल रही है."

'निशब्दे जगाओ' भाजपा के नए कार्यक्रमों में से एक है, जिसे संघ के नेता 'मौन क्रांति' कहते हैं. आरएसएस के एक नेता कहते हैं, "हम मतदाताओं को गेहूं को भूसे से अलग करने में मदद करेंगे. चुनावी अभियान भ्रामक हो सकते हैं इसलिए हम लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करेंगे." इस बीच, भाजपा ने बंगाल में अयोध्या के राम मंदिर के लिए चंदा लेना शुरू कर दिया है. पचास लाख घरों को पहले ही कवर किया जा चुका है. संघ के वही नेता कहते हैं, "राशि उतनी अहम नहीं है, पर हम इस मौके का उपयोग लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं कि मंदिर हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक क्यों है. हम उन्हें पीएम मोदी की भूमि पूजन और हमारे कुछ नेताओं के दान की तस्वीरें भी भेज रहे हैं."

चरम ध्रुवीकरण

पिच तैयार है. 22 फरवरी को प्रधानमंत्री के भाषण और तुष्टिकरण की राजनीति के संदर्भों ने इस मुद्दे को हवा दे दी है. ध्रुवीकरण को गति देने के लिए भाजपा की योजना अब सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए

“

तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ जय श्री राम लोगों का गुस्सा है. सरस्वती पूजा करते हुए एक शिक्षक की हत्या हो गई... बंगाल को उन्होंने कैसा राज्य बना दिया है?"

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

किसी प्रमुख मंदिर, आश्रम या धार्मिक स्थान के उपयोग करने की है. तो यह परिवर्तन जात्रा हो या आर नोई अन्याय जैसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, उन्हें अनिवार्य रूप से किसी धार्मिक मैदान या मंदिर से हरी झंडी दिखाकर खाना किया जाता है.

भाजपा उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार कहते हैं, "हम रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और गौड़ीय मठ जैसे 200 धार्मिक और परोपकारी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके 1.7 करोड़ अनुयायियों से जुड़ सकें. उनके परिवार के सदस्यों को भी जोड़ लें तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है. रामकृष्ण मिशन के पास 40 लाख समर्थन आधार है. चुनाव अभियान शुरू होने के बाद, हमारे राष्ट्रीय नेता और मंत्री बंगाल आएंगे और मंदिरों-आश्रमों का दौरा करेंगे."

यह एक खतरनाक बवंडर है, जिसने यहां तक कि अब ममता को भी इसमें खींच लिया है. वह पूजा-अनुष्ठानों में भाग ले रही हैं, अपनी रैलियों में मंत्रों का जाप कर रही हैं और यहां तक कि भाजपा नेताओं को श्लोक-जाप प्रतियोगिताओं की चुनौती दे रही हैं. कोलकाता दक्षिण के पैलान की एक रैली में ममता ने रैली में कहा कि जो हिंदू हैं वे हाथ ऊपर करें और बताएं कि वे श्लोकों का सही उच्चारण कर रही हैं. टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंद्रु शेखर रे ममता के बचाव में कहते हैं, "उनकी धर्म की अवधारणा दया और मानवता पर आधारित है. यह सब कुछ समावेशी है जैसा श्री रामकृष्ण का हिंदू धर्म हमें सिखाता है—जोतो मोत, तोतो पोथ (जितने मार्ग उतने ही विचार)."

जादवपुर विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर इमान कल्याण लाहिड़ी कहते हैं कि वर्तमान स्थिति इस बात का सच्चा प्रतिबिंब है कि कैसे 'व्यक्तियों, उनकी चेतना और तर्क क्षमता पर हावी होने के लिए राजनीति धर्म का उपयोग कर रही है. वंचित तबका इस ध्रुवीकरण कथा का सबसे आसान शिकार है. गांवों और छोटे शहरों में जीवन, संघर्ष और परेशानियों से भरा है और उन्हें एक ऐसे सहारे की तलाश होती है जो कुछ वक्त के लिए उनका ध्यान इन चिंताओं से दूर कहीं ले जा सके. अपने वादों और उपहारों के टोकनों के साथ वहां पहुंच रहे राजनेता उनके लिए मानव रूप में देवता जैसे हैं. और अगर वे धर्म को बेचने उतरे हैं, तो लोग उसे भी खरीदने को तैयार हैं."

चुनावी रणभूमि इतनी ध्रुवीकृत है कि भाजपा अब उन 220 सीटों (विधानसभा की कुल सीटें 294 हैं) के लिए बूथ-स्तर के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां उसे उम्मीद है कि धार्मिक ध्रुवीकरण उसे फायदा पहुंचाएगा. 25 से 60 फीसद मुस्लिम आबादी वाली करीब 70 सीटें पार्टी के रडार पर नहीं हैं. नड्डा के 'एक मुट्ठी चावल' और 'कृषक अविज्ञान' कार्यक्रमों से भी करीब 8,000 मुस्लिम बहुल गांवों को बाहर रखा गया है. ■

पुदुच्चेरी

गफलत में गई सरकार

अमरनाथ के. मेनन

विधानसभा चुनावों से बमुश्किल दो महीना पहले पुदुच्चेरी में कांग्रेस की सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 22 फरवरी को मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने 30 सदस्यों वाली विधानसभा में विश्वास मत गंवा दिया. सत्ताधारी कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के कुछ विधायकों के साथ छोड़ देने और भाजपा समर्थक तीन नामांकित विधायकों के कारण किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया. 2016 में कांग्रेस ने 15 सीटें और डीएमके ने तीन सीटें जीतकर साझा सरकार बनाई थी. उन्हें तीन निर्दलीयों का भी समर्थन मिल गया था. 18 सीटों पर लड़ी भाजपा एक भी सीट न जीत सकी थी. लेकिन विधानसभा के लिए तीन मनोनीत सदस्यों के नामों की सिफारिश में देरी नारायणसामी सरकार को महंगी पड़ गई. केंद्रशासित राज्यों पर नियंत्रण रखने वाली केंद्र सरकार ने नारायणसामी को अंधेरे में रखते हुए उन तीनों पर तीन भाजपा समर्थकों को मनोनीत कर दिया. कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी पर कोई फायदा नहीं हुआ. नारायणसामी के साथ लगातार टकराव को देखते हुए केंद्र ने 17 फरवरी को उप-राज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया ताकि वह विधानसभा चुनाव में भाजपा पर कांग्रेस के हमलों को

भोथरा कर सके. इससे पहले दो मंत्रियों समेत कांग्रेस के पांच विधायकों और डीएमके के एक विधायक ने महीने भर के भीतर इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया था. विश्वास मत को “लोकतंत्र की हत्या” बताते हुए नारायणसामी ने कहा, “तीन मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है. सरकार के सचेतक ने इस मुद्दे को उठाया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए. इसलिए हम सदन से बाहर चले गए और अपना इस्तीफा भेज दिया. विधानसभा अध्यक्ष को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराना चाहिए था. लेकिन इसकी जगह उन्होंने फैसला सुना दिया कि सरकार बहुमत खो चुकी है.” कांग्रेस के इस 75 वर्षीय नेता ने तय किया है कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. वे कहते हैं, “भाजपा ने एक चुनी हुई सरकार को गिराया है क्योंकि वह आगामी चुनाव में धांधली करने के लिए सरकारी मशीनरी, पैसों और बाहुबल का इस्तेमाल करना चाहती थी. पर वे इसे कामयाब

नहीं होंगे क्योंकि जनता ने देखा है कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने किस तरह हमारी सरकार को परेशान कर रखा था.” नारायणसामी के एक करीबी सूत्र के मुताबिक, “उनकी सरकार के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी अब उनके प्रति सहानुभूति में बदल जाएगी. यह कदम भाजपा के लिए उलटा पड़ेगा.”

नारायणसामी को ताकत पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति उनकी वफादारी से मिलती है. लेकिन विडंबना ही है कि लुंजपुंज कांग्रेस और उसके नेतृत्व की ओर से उन्हें

पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया. नारायणसामी और बेदी के बीच खींचतान जब चरम पर थी तो राहुल गांधी पुदुच्चेरी में जगह-जगह व्याख्यान देने में लगे थे.

बेदी और नारायणसामी के हट जाने के बाद वहां एक नई संभावना का जन्म हो सकता है. मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर. मणिवन्नन कहते हैं,

नारायणसामी की विदाई को देखते हुए आगामी चुनावों में सहयोगी डीएमके मुख्यमंत्री पद पर दांव लगा सकता है

“भाजपा जिस तरह किसी जनसमर्थन के बिना जबरन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उसे देखते हुए काफी संभावना है कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण जो जगह खाली हो रही है, उसे भरने के लिए द्रविड़ पार्टियां आगे आ जाएं. नारायणसामी सहानुभूति बटोर सकते हैं पर वोट न बटोर पाएंगे.”

दरअसल, इस मौके का फायदा अब डीएमके उठा सकती है और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अरक्कोणम के सांसद एस. जगतरक्षकन का नाम पेश कर सकती है. उनकी वन्नियार जाति की पहचान भी डीएमके के लिए मददगार साबित हो सकती है और वे इस प्रभावशाली जाति के वोट पार्टी को दिला सकते हैं. विपक्षी पार्टियों ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (एआइएनआरसी), एआइएडीएमके और भाजपा का एक असरदार गठबंधन बन सकता है पर एआइएनआरसी के चतुर प्रमुख एन.आर. रंगासामी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में किसी को आगे न आने देंगे.

पुदुच्चेरी के 1962 में भारतीय संघ में शामिल होने के बाद से 10 में से छह सरकारें कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं. ओरोविल फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रो. सच्चिदानंद मोहंती कहते हैं, “पुदुच्चेरी राजनैतिक पक्षपात और दुस्साहसिक कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकता. ऐसे काम केंद्रशासित राज्यों की परंपरा के अनुरूप नहीं.” ■

✓ **इवी नाथ** इस्तीफे के बाद नारायणसामी



एएनआइ



देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है



वॉल्टर बर्नाडची/बायोजफोटो

✓ **खुला विवरण**
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़
राष्ट्रीय पार्क में बाघ



मध्य प्रदेश

खदबदाती खदाने

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में एक संशोधन को अधिसूचित कर दिया. इस संशोधन के जरिए राज्य के इस्पात तथा अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले डोलोमाइट सरीखे 'गौण खनिजों' की खुदाई के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया में फेरबदल कर दिया गया. मंडला की जिला मजिस्ट्रेट हर्शिका सिंह ने 30 जनवरी को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिला पंचायतों के सीईओ और जिले के डिविजनल वन अधिकारियों को पत्र लिखकर कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कुछ निश्चित इलाकों में डोलोमाइट की खुदाई के परमिट देने के प्रस्ताव पर स्थानीय ग्राम सभाओं की राय और आपत्तियां मांगीं.

इस कदम का स्थानीय लोगों और पर्यावरणवादियों ने तीखा विरोध किया. यह विरोध न केवल खुदाई के पारिस्थितिकीय प्रभाव को लेकर था, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों के 'निस्तार' अधिकारों पर पड़ने वाले खुदाई की लीज के नतीजों को लेकर भी था. उनका कहना था कि यह ताजातरीन संशोधन पहले के कानूनों की भावना के खिलाफ है.

राज्य सरकार का यह संशोधन केंद्र सरकार के 2015 के उस फैसले के बाद आया जिसमें केंद्र ने 31 'बड़े खनिजों' (डोलोमाइट सहित) को 'गौण खनिजों' के तौर पर नए सिरे

से वर्गीकृत कर दिया था। यह फैसला एक तकनीकी बदलाव था जो राज्यों के लिए खुदाई की लीज की अनुमति देना कहीं ज्यादा आसान बना देता है। मध्य प्रदेश सरकार के 22 जनवरी के संशोधन में खुदाई के ऐसे अधिकार के लिए ई-निविदा का प्रावधान भी शामिल है।

इस संशोधन के विरोधियों का कहना है कि इसका सबसे विवादास्पद प्रावधान धारा 18 ए(2) है, जिसका एक हिस्सा कहता है, “(ऐसे खुदाई के प्रस्तावों) के संबंध में राय (या आपत्तियाँ) प्रस्तुत करने की सूचना... अधिसूचित क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्रामसभा को और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत को दी जाएगी। अगर संबंधित ग्रामसभा या ग्राम पंचायत से आपत्तियाँ 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हो जाती हैं, तो आपत्तियों का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा... अगर निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि ग्रामसभा/ग्राम पंचायत को (प्रस्ताव पर) कोई आपत्ति नहीं है।”

विभिन्न पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन मौजूदा केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। वरिष्ठ वकील और ऐक्टिविस्ट विभूति झा कहते हैं, “पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए या पेसा कानून) ऐसे मुद्दों पर निर्णय का अधिकार ग्रामसभाओं को देता है। यह कहकर कि खुदाई के प्रस्तावों पर ग्रामसभाओं की आपत्तियों का ‘निराकरण गुण-दोष के आधार पर’ किया जाएगा, सरकार का संशोधन साफ तौर पर उनके अधिकार को कमजोर कर रहा है।”

मुद्दा तब और पेचीदा हो जाता है जब केंद्र की तरफ से करीब तीन दशक पहले पारित किया गया पेसा कानून इस संबंध में ग्रामसभाओं को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश करता है, वहीं राज्य सरकारें इसके अमल के लिए नियम बनाने में हीला-हवाला करती रही हैं। अभी तक केवल पांच राज्यों—आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान—ने ये नियम बनाए हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने इसकी प्रक्रिया अभी पिछले हफ्ते ही शुरू की है।

विभूति झा यह भी कहते हैं, “राज्य में ग्रामसभाओं की भूमिका मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज कानून 1993 में परिभाषित की गई है और नियम भले न बनाए

गए हों लेकिन पेसा कानून राज्य में लागू है। सरकार का संशोधन इसके खिलाफ जाता है।” इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 251 और 254 कहते हैं कि अगर राज्य और केंद्र के कानूनों के बीच कोई ‘असंगति’ पैदा होती है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। इस मामले में केंद्रीय कानून पेसा कानून ही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के भूविज्ञान और खनन के डायरेक्टर विनीत कुमार ऑस्टिन जोर देकर कहते हैं कि इनमें आपस में कोई अंतर्विरोध नहीं है और “गौण खनिजों से जुड़े नियम

राजस्व बनाम अधिकार

15 दिन

का वक्त दिया गया है नए संशोधन कानून में ग्रामसभाओं/ग्राम पंचायतों को खनन प्रस्तावों के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए

27%

हिस्सा भारत के डोलोमाइट भंडार का मध्य प्रदेश में है, इंडियन माइंस ब्यूरो की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक

6.4 करोड़ रु.

का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ डोलोमाइट खनन (5,43,000 टन) से साल 2014-15 में

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं के अधिकारों को कमजोर नहीं करते हैं।”

इस 22 जनवरी के संशोधन में आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए जो वक्त दिया गया है, वह भी विवादास्पद मुद्दा है। विभूति झा का कहना है, “ऐसे प्रस्तावों पर राय और आपत्तियाँ पेश करने के लिए ग्राम सभाओं को दिया गया 15 दिन का वक्त बहुत ही कम है। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो (राय और आपत्तियाँ मांगने वाले) नोटिस के

ग्रामसभाओं को समय से मिलने तक की कोई संभावना नहीं है।”

एक और परेशानी यह है कि डोलोमाइट की खुदाई के लिए जिन क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से कुछ कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले पारिस्थितिकी गलियारे में आते हैं, जो संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत हैं। इसकी वजह से राज्य सरकार के संशोधन का एक और मौजूदा कानून के साथ टकराव पैदा हो रहा है और वह है वन्यजीव (संरक्षण) कानून, 1972 का एक सांविधिक प्रावधान। इस कानून की धारा 38-ओ(जी) कहती है कि ‘एक संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व को दूसरे संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ने वाले इलाकों को पारिस्थितिकीय रूप से अरक्षणीय इस्तेमालों के लिए बदला (नहीं) जाएगा, केवल जन हित में और टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति से ही ऐसा किया जा सकेगा’। खुदाई की कुछ जगहें इस प्रावधान का उल्लंघन करती हैं, वहीं राज्य सरकार के प्रस्तावित नए नियमों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की स्वीकृति लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

अभी तक मंडला जिले की एक ग्रामसभा—भंवर्ताला—ने अपने पास-पड़ोस के इलाके में डोलोमाइट की खुदाई के संभावित स्थलों के रूप में पहचाने गए जमीन के सात टुकड़ों को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इस ग्रामसभा ने अपनी आपत्ति में कहा है कि अगर इन इलाकों में डोलोमाइट की खुदाई होने दी जाती है, तो इसके नतीजतन यहां रहने वाले लोगों के लिए कोई साझा जमीन नहीं बचेगी, इस इलाके के संरक्षित वनों को हानि होगी और स्थानीय वन्यजीवन को भी नुकसान पहुंचेगा।

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के मुताबिक, भारत में डोलोमाइट के करीब एक-तिहाई (27 फीसद) भंडार मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार मंडला, बालाघाट, छतरपुर, सागर, जबलपुर, कटनी, सीधी, नरसिंहपुर, सिवनी, झाबुआ, खंडवा और देवास जिलों में पाए गए हैं। डोलोमाइट राज्य सरकार के राजस्व में दूसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला गौण खनिज है। ■

परिंदों की हिफाजत

रोहित परिहार



कितने कारगर?
बिजली के तारों पर लगे
पक्षी डायवर्टर

दे श में पहली बार पक्षियों को उच्च क्षमता वाले बिजली के तारों से बचाकर सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ऐसे तारों को भूमिगत बनाने की योजना बना रही है. उसकी कोशिश होगी कि दुर्लभ प्रजाति के पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के प्राकृतिक आवास को किसी तरह का नुकसान नहीं हो. सरकार ने लुप्तप्राय गोडावण को बचाने के उपायों का पता लगाना शुरू कर दिया है. पश्चिमी राजस्थान में उच्च क्षमता वाले बिजली के तारों से टकराने और करंट लगने से इनकी मौत हो जाती है. राज्य के इस इलाके में इन पक्षियों का प्राकृतिक वास है. लेकिन यहां बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइनें भी ज्यादा हैं जिनमें हरित ऊर्जा वाली सौर और पवन ऊर्जा की लाइनें भी शामिल हैं. भारत में इन दुर्लभ पक्षियों की संख्या मात्र 150 रह गई है. भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, बहुत ज्यादा वोल्टेज वाले बिजली के तारों से करंट लगने के कारण इन पक्षियों की मृत्यु दर 15 फीसद हो चुकी है.

दिसंबर, 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिछले सप्ताह पक्षियों के उड़ान की दिशा बदलने वाले उपकरणों (डाइवर्टर) को लगाने के कुछ खास निर्देश जारी किए हैं. इनको बिजली की तीनों लाइनों पर लगाया जाएगा. पांच से छह मीटर की दूरी पर दो डाइवर्टर लगाने होंगे. दो तरह के डाइवर्टर उपलब्ध हैं—एक, सभी तरह के मौसम के अनुकूल होते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो रात में चमकते हैं या ऐसी रोशनी छोड़ते हैं जो सिर्फ पक्षियों को नजर आती है. इनकी कीमत एक हजार रु. से पांच हजार रु. तक हो सकती है.

वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के अंतरिम कंट्री प्रोग्राम मैनेजर परमेश्वर वेणु ने इंडिया टुडे को बताया कि उनकी सोसाइटी

गोडावण अगल-बगल ज्यादा चौड़ाई में देख पाते हैं. पर वे सामने की ओर ज्यादा चौड़ाई में नहीं देख पाते. इसके चलते वे कुछ दूर से सामने की ओर बिजली तार नहीं देख पाते हैं

ने राज्य के वन विभाग की मदद से दिसंबर में पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्वीडन से फायरफ्लाई प्रकार के 1,813 डाइवर्टर आयात किए जिन्हें पोकरण में 6.4 किमी तक बिजली के तारों के क्षेत्र में लगाया गया है. पर जैसलमेर से मिली रिपोर्टों के अनुसार, पिछले हफ्ते डाइवर्टर वाले इस क्षेत्र में करंट लगने के कारण दो सफेद गिद्धों की मौत हो गई. इंटरनेशनल यूनिशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ काम करने वाले बीकानेर के दाऊ लाल बोहरा कहते हैं, “अब तक जो फायरफ्लाई डाइवर्टर लगाए गए हैं, वे दूर भगाने वाले उपकरण हैं, न कि सही मायने में डाइवर्टर. ये बड़ी संख्या में पूरे झुंड के प्रवास के वक्त काम आते हैं, इक्का-दुक्का उड़ने वाले पक्षियों के वक्त नहीं जैसा कि गोडावण मामले में देखा जाता है. ये पक्षी रेगिस्तान के एक प्रतिकूल क्षेत्र से उड़कर पोकरण की ओर जाते हैं जहां उन्हें सुरक्षित

प्राकृतिक वास मिलता है पर इसके लिए इन्हें हाइड्रेशन तारों को पार करना पड़ता है.”

केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने भी ऊर्जा पैदा करने वाले डेवलपमेंट से कहा है कि वे राजस्थान, गुजरात एवं पश्चिमी घाटों में ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे पक्षियों के लिए खतरों को कम किया जा सके.

बिजली के तारों को भूमिगत बना देने से पक्षियों की मृत्यु रोकी जा सकती है, वहीं बिजली की लाइनों की मार्किंग करने से पक्षियों की मृत्यु दर में 10 फीसद की कमी लाई जा सकती है. राजस्थान सरकार में बिजली विभाग के सचिव दिनेश कुमार के मुताबिक, बिजली विभाग ने 60 करोड़ रु. की लागत से 104 किमी लंबा बिजली का केबल भूमिगत बिछाने की योजना बनाई है. विशेषज्ञों का कहना है कि गोडावण 33 केवी की लाइनों की ऊंचाई से ऊपर शायद ही कभी उड़ते हैं और तकनीकी रूप से 33 केवी की क्षमता वाले बिजली के केबलों को भूमिगत करना सुरक्षित है.

एक बेहतर विकल्प यह है कि गोडावण के प्राकृतिक वास में सुधार किया जाए ताकि इन्हें बिजली के तारों से होकर प्रवास न करना पड़े. यह भूमिगत केबल बिछाने और डाइवर्टर लगाने से अच्छा और सस्ता है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहले ही गोडावण के प्रजनन संरक्षण के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ मिलकर ‘हैबीटाट इंप्रूवमेंट ऐंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड-एन इंटीग्रेटेड एप्रोच’ नामक पहल शुरू कर चुका है. मंत्रालय ने पांच वर्षों (2016-2021) में इसके लिए 33.85 करोड़ रु. मंजूर किए हैं. इससे गोडावण वाले राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक को वित्तीय मदद भी दी जा रही है. गुजरात के वन विभाग ने 8,511.66 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके गोडावण के प्राकृतिक वास को विकसित किया है. ■



अर्थात्

... मगर हकीकत है

अंशुमान तिवारी

जी

जीपी की संख्या देखकर, एक आंकड़ेबाज अर्थव्यवस्था में 'वी' (V) वाली रिकवरी पर व्यापारी से भिड़ गया जो मंदी से बुरी तरह त्रस्त था। व्यापारी बोला, 2020 जनवरी में मेरी कमाई सौ रु. थी, लॉकडाउन के बाद 20 रु. रह गई। आपके हिसाब से यह अगले साल 40 रु. हो जाएगी यानी दोगुनी बढ़त! लेकिन मेरा 60 रु. का नुकसान कहाँ गया? इस तरह तो 100 रु. की कमाई पर पहुँचने में मुझे पाँच साल लगेंगे।

मंदी में आर्थिक उत्पादन सिकुड़ जाने से आंकड़ों की समझ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए प्रतिशत ग्रोथ के बजाए वास्तविक आंकड़े यानी उत्पादन की ठोस कीमत को पढ़ना चाहिए। अगले दो साल तक भारत में जीडीपी को लेकर खासा भ्रम रहेगा। इसलिए सच समझना जरूरी है।

● कोविड से पहले 2019-20 में अर्थव्यवस्था मंदी में थी। कुल उत्पादन का वास्तविक मूल्य (महंगाई हटाकर) 146 लाख करोड़ रु. था, जो 2020 में टूटकर 134 लाख करोड़ रु. रह गया। यह 2021-22 में बमुश्किल 149 लाख करोड़ रु. होगा।

● अगर कोविड न हुआ होता और अर्थव्यवस्था केवल पाँच फीसद की दर से बढ़ रही होती तो वित्त वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था का आकार 160.59 लाख करोड़ रु. होता। अब इसे हासिल करने के लिए 2022 में करीब 20 फीसद की विकास दर चाहिए।

● आइएमएफ के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति आय को 2020 के स्तर पर लौटने में 2024 आ जाएगा।

मंदी से निकलने के जट्टोजहद के बीच जीडीपी को लेकर जब कई भ्रम टूट ही रहे हैं तो भारत में इसकी पैमाइश के तौर तरीकों पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

डेविड रोजलिंग, अपनी दिलचस्प किताब, *द ग्रोथ डिप्ल्यूजन* में जीडीपी को कुजनेट्स का राक्षस कहते हैं।

जीडीपी के जनक सिमोन कुजनेट्स, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। 1933 में राष्ट्रपति फ्रेड्रिक रूजवेल्ट ने, उन्हें नेशनल एकाउंट का बनाने का काम सौंपा। कुजनेट्स ने सभी गतिविधियों को एक आंकड़े में समेट दिया। यही मायावी फॉर्मूला भारत के कुल उत्पादन के मूल्य को आबादी से बांट कर मुकेश अंबानी और दिहाड़ी मजदूर की कमाई बराबर कर देता है।

भारत में ग्रोथ की पैमाइश उत्पादन के आधार पर होती है, लोगों की कमाई में बढ़त से नहीं। 2015 में नेशनल एकाउंट्स में नया फॉर्मूला (ग्रॉस वैल्यू एडेड-कच्चे माल और दूसरे इनपुट निकालने के बाद उत्पादन का मूल्य) फॉर्मूला जोड़ा गया तो वह भी सफ़लाइ या आपूर्ति की तरफ से था, मांग या खपत की तरफ से नहीं। अरविंद सुब्रह्मण्यम (2018 तक

सरकार के आर्थिक सलाहकार) ने जून 2019 में अपने एक अध्ययन में साबित किया कि यह नया पैमाना ग्रोथ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।

भारत को मंदी के बीच आर्थिक प्रगति को नापने का तरीका बदलना चाहिए, मसलन,

■ राष्ट्रीय जीडीपी को उत्पादन या आपूर्ति की तरफ से मापा जा सकता है। लेकिन राज्य (एसडीपी) और जिला विकास दर (डीडीपी) की नापजोख मांग और आय के आधार पर होनी चाहिए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास की सही तस्वीर मिलेगी।

■ राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर मीडियन इनकम यानी मध्यवर्ती आय (सर्वोच्च और न्यूनतम के बीच) का आकलन जरूरी है। इससे गरीबी में कमी और मध्य वर्ग के विस्तार को मापा जाना सकता है।

■ जेनुइन प्रोग्रेस, हैपीनेस, वेल बीइंग इंडेक्स जैसे पैमानों से जिला स्तर पर सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव को मापा जा सकता है।

भारत को लंबे वक्त तक धीमी ग्रोथ के साथ जीना होगा। फिर भी प्रमुख जिले अगर दहाई के अंकों और राज्य 7-8 फीसद की औसत विकास दर हासिल कर पाते हैं तो 6-7 फीसद की स्थायी राष्ट्रीय जीडीपी दर के जरिए बड़ी आबादी की जिंदगी में क्रमशः बेहतर कर सकती है।

दरअसल, कमाई, रोजगार, जीवन स्तर और संपत्ति सही पैमाइश के बिना जीडीपी से कुछ समझ नहीं आता। आर्थिक असमानता सूझ देने वाले इतालवी सांख्यिकीविद कोलाराडो गिनी का फॉर्मूला (गिनी कोइफिशिएंट) बताता है कि भारत की दस फीसद आबादी के पास 77 फीसद संपत्ति, यूं ही नहीं है।

कोविड के बीच बीती मई में चीन ने जीडीपी को नापने का पैमाना बदल दिया। अब वह तरक्की की पैमाइश उत्पादन में बढ़ोतरी (मूल्य

के आधार पर) नहीं बल्कि रोजगार से करेगा। चीन की सरकार छह फीसद ग्रोथ नहीं बल्कि जनता के लिए (रोजगार, बुनियादी जीविका, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार, भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति, स्थानीय सरकारों को ज्यादा ताकत) जैसी गारंटियां सुनिश्चित करने वाली है।

मंदी जाने तक जीडीपी के आंकड़े हमें हैरान रखेंगे। इनमें एक तरफ कंपनियों के मुनाफे बढ़ते नजर आएंगे और दूसरी तरफ बेकारी और गरीबी। जब भारत में तेज ग्रोथ वाले वर्षों (2012 से 2018) में भी बेकारी बढ़ी और ग्रामीण व नगरीय कमाई कम हुई तो अब तो घोर मंदी है। इसलिए जीडीपी के आंकड़ों को अपनी कमाई, खपत और बचत से नापना बेहतर है ताकि खुशफहमी में जोखिम लेने से बचा जा सके।

@anshuman1tiwari



इस महामंदी के बीच भारत में जीडीपी की पैमाइश को लेकर कई भ्रम टूटने वाले हैं



आवरण कथा
राजघ्रोह

इरावने कानूनों का फंदा

असहमति को
दबाने के लिए
धड़ल्ले से किया
जा रहा है बेहद
सख्त कानूनों का
इस्तेमाल

कौशिक डेका



...ताकि डर बना रहे
दिल्ली की अदालत में पेशी के
लिए ले जाई जाती पर्यावरण
कार्यकर्ता दिशा रवि

प

र्यावरण कार्यकर्ता 21 वर्षीया जलवायु ऐक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलूरु से गिरफ्तार किया और उस पर राजद्रोह का आरोप थोप दिया, तो मीडिया में दो बिल्कुल अलग बोलियां उभरीं. एक में दिशा को राज्यसत्ता का दुश्मन करार दिया गया, जिस पर कथित तौर पर देश को बदनाम करने के लिए विवादास्पद ऑनलाइन 'टूलकिट' को संपादित करने का आरोप है. दूसरे में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को असहमति का गला

घोंटने के लिए राजद्रोह कानून के घनघोर दुरुपयोग की एक और मिसाल बताया गया. बात सिर्फ दिशा की नहीं है. इसी साल जनवरी में तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई सहित छह पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के बारे में एक "अपुष्ट" खबर ट्वीट करने के लिए राजद्रोह के तीन मामले दर्ज कर लिए गए. पिछले साल जनवरी-फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे करीब दो दर्जन लोगों के खिलाफ राजद्रोह से जुड़ी आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 124ए लगाई गई. थोड़ा और पीछे जाएं तो फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र कन्हैया कुमार और उमर खालिद को भी दिल्ली कैंपस में अफजल गुरु की मौत की बरसी के मौके पर कथित तौर पर राजद्रोही नारे लगाने के लिए इन्हीं आरोपों में हिरासत में लिया गया था.

तो, क्या सत्ताधारी राजद्रोह के दायरे की गलत व्याख्या कर रहे हैं? वकीलों, अध्येताओं और पत्रकारों के समूह की स्वतंत्र शोध पहल 'आर्टिकल 14' के मुताबिक, 2010 और 2020 के बीच देश भर में राजद्रोह के 816 मामलों में 10,938 लोग गिरफ्तार किए गए. लोकप्रिय विमर्श में केंद्र सरकार को ही दोषी माना जा रहा है, जिसके तहत सिर्फ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां

चंद्रदीप कुमार

**किले पर**

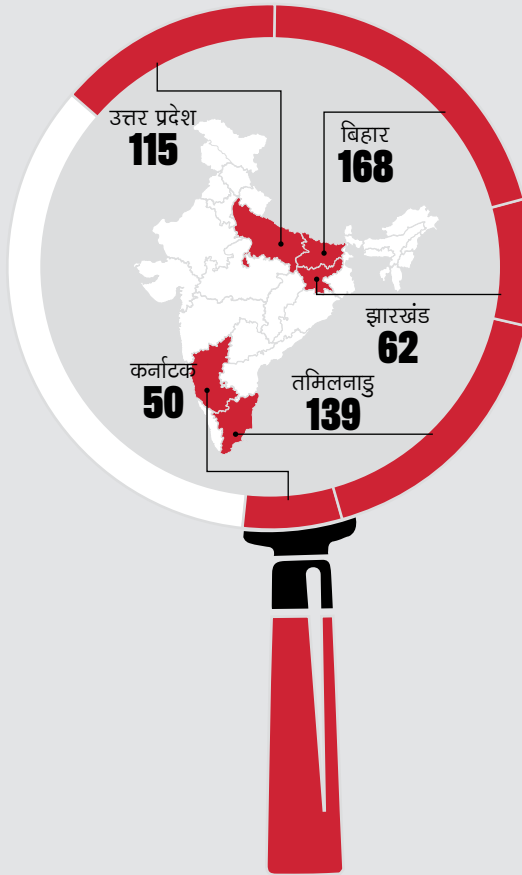
26 जनवरी को किसान रैली के दौरान उपद्रवी तत्वों ने लाल किले पर निशान साहब फहराया

आंकड़ों में राजद्रोह

2010 से 2020 के बीच दर्ज राजद्रोह के 816 मामलों में 534 बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में

10,938

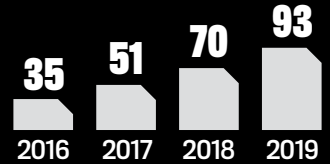
लोग 2010 से 2020 के बीच दर्ज राजद्रोह के 816 मामलों में गिरफ्तार किए गए



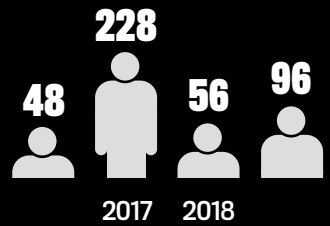
इनमें दिल्ली में जारी **किसान आंदोलन** के दौरान छह, दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक चले **सीएए विरोधी आंदोलन** के दौरान 25, सितंबर 2020 में **हाथरस गैंगरेप** की घटना के बाद 22 मामले दर्ज हुए. तमिलनाडु में **कुडनकुलम** परमाणु बिजली संयंत्र के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2010-11 में करीब 3,500 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज किए गए

बढ़ते मामले, सजा की दर थोड़ी

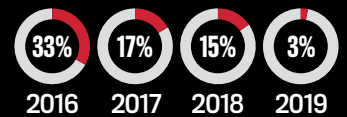
कुल मामले



लोग गिरफ्तार



सजा की दर



स्रोत: आर्टिकल 14, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

ही हैं, लेकिन राज्य सरकारें इसका लगातार इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है. राजद्रोह के तकरीबन 65 फीसद मामले पांच राज्यों—बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक—में ही दर्ज हुए हैं.

युवा, बुजुर्ग, अमीर या गरीब, सेलेब्रिटी या आम लोग, छात्र या पेशेवर, राजद्रोह के आरोप के लंबे साए से कोई भी दूर दिखाई नहीं देता. राष्ट्रगीत के लिए खड़े न होने, आलोचना करती ट्वीट करने, 'कश्मीर को आजाद करो' सरीखा पोस्टर थामने और यहां तक कि 'आजादी' का नारा लगाने पर भी धारा 124ए लगाई जाती रही है. बीते दशक में 1,310 लोगों पर महज नारे लगाने की वजह से राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं. वह भी तब जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने *बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य सरकार* मुकदमे में अपने ऐतिहासिक फैसले में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान-समर्थक नारे लगाने के लिए राजद्रोह के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने फैसले में कहा था कि हिंसा भड़काने की किसी कोशिश के बगैर महज नारे लगाने का मतलब राजद्रोह नहीं है और जांच अधिकारियों को ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां करने से पहले बेहद सतर्क होना चाहिए.

राजद्रोह क्या है?

आइपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह में ऐसे संकेत, दृश्यांकन या बोले या लिखे गए शब्द शामिल हैं जिनसे सरकार के प्रति 'घृणा या मानहानि' उत्पन्न हो सकती हो या जो सरकार के प्रति 'अलगाव उकसाते या उकसाने का प्रयत्न' करते हों. अलगाव या वैमनस्य को खासकर राज्यसत्ता के प्रति शत्रुता के रूप में परिभाषित किया गया है.

ब्रिटिश इतिहासकार-राजनीतिक थॉमस मैकॉले ने पहले 1837 में इस कानून को सूत्रबद्ध किया था, लेकिन 1860 में आइपीसी बनाने और लागू करते वक्त उसमें इसे शामिल नहीं किया गया. दस साल बाद सर जेम्स स्टीफन ने एक संशोधन के जरिए आइपीसी के अध्याय VI में धारा 124ए जोड़ी, जो राज्यसत्ता के विरुद्ध अपराधों के लिए है. यह वहाबी आंदोलन में आ रही तेजी और भारतीय नागरिकों की तरफ से ज्यादा स्वायत्तता की उठ रही मांगों के संदर्भ में किया गया था. आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए.

आजाद हिंदुस्तान में राजद्रोह का सबसे चर्चित मामला बिहार में

साझा असहिष्णुता

बीते दो दशकों में तमाम राजनैतिक रंग-रूप की सरकारों ने असहमति जताने वालों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए



भाजपा, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ पुलिस ने माओवादी विद्रोहियों के साथ संबंध का आरोप लगाकर ऐक्टिविस्ट और डॉक्टर **विनायक सेन** को राजद्रोह की धारा में गिरफ्तार किया। अदालत ने 2010 में सेन को दोषी करार दिया। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने फैसले को सही ठहराया। अप्रैल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और राजद्रोह का आरोप हटा दिया

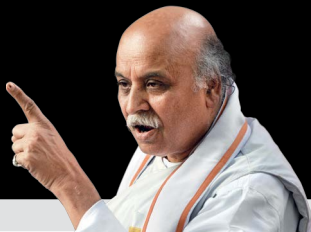
कांग्रेस, दिल्ली पुलिस

प्रख्यात लेखिका **अरुंधती राय** पर एक सेमिनार में 'देश विरोधी' भाषण देने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया

अप्रैल 2003

कांग्रेस, राजस्थान

तेज धार वाले हथियार (त्रिशूल) रखने पर पाबंदी का उल्लंघन करने के लिए विहिप नेता **प्रवीण तोगड़िया** पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया



जून 2005

कांग्रेस, पंजाब

शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष **सिमरनजीत सिंह मान** को राजद्रोह के चार अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। मान पर आरोप था कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 21वीं सालगिरह पर स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए

मई 2007



नवंबर 2010

सितंबर-दिसंबर 2011

अन्नाद्रमुक, तमिलनाडु
कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए **तमिलनाडु के इंदिराकरै और आस-पास के गांवों के 3,500 लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया**

अनुष्का सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप, डॉ. बी.आर. आंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली



“ 2014 से मामलों में उछाल दिखने की एक वजह यह है कि सरकारी आंकड़े सिर्फ उसी साल से उपलब्ध हैं। इसलिए पहले की सरकारों के दौर से तुलना मुश्किल है ”

फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह का था। 26 मई 1953 को बेगुसराय में एक जोशीले भाषण में उन्होंने अपराध जांच महकमे और कांग्रेस पार्टी की खूब खिल्ली उड़ाई। कांग्रेस को भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और निरंकुशता का दोषी ठहराते हुए उन्होंने ऐसी क्रांति का आह्वान किया, जो पूंजीपतियों, जमींदारों और कांग्रेस नेताओं के उखाड़ फेंके। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उन्हें दोषी ठहराने वाले हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन उसने राजद्रोह के दायरे को परिभाषित करने की भी कोशिश की। उसने कहा कि राजद्रोह के तहत ऐसे अपराध आते हैं, जो हिंसा के जरिए 'सरकार को उलटने का असर' पैदा करने की मंशा से किए गए हों।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “लोगों को सरकार के बारे में, या उसके कदमों के बारे में, आलोचना या टिप्पणी के रूप में जो भी चाहे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हिंसा के लिए या अराजकता पैदा करने की मंशा से लोगों को उकसाता न हो।” संक्षेप में, शीर्ष अदालत ने सरकार या नेताओं की आलोचना को, 'फिर चाहे वह कितने भी कटोरे शब्दों में' क्यों न की गई हो, राजद्रोह के दायरे से बाहर निकाल दिया। फिर भी नेताओं की आलोचना पर बार-बार राजद्रोह के आरोप मढ़े जाते रहे हैं।

कई लोगों का मानना है कि भाजपा सरकार के इन छह साल में राजद्रोह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जो साबित करे कि पिछली सरकारों का रिकॉर्ड बेहतर था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2014

कांग्रेस, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने राष्ट्रीय प्रतीक और संसद को अपमानजनक ढंग से चित्रित करने वाली झड़प प्रकाशित करने के लिए कार्टूनकार **असीम त्रिवेदी** को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया

कांग्रेस, आंध्र प्रदेश धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के कथित उद्देश्य से भड़काऊ भाषण देने के लिए एआइएमआइएम के विधायक **अकबरुद्दीन ओवैसी** के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया



भाजपा, गुजरात अहमदाबाद की अपराध शाखा ने ऐक्टिविस्ट **हार्दिक पटेल** के खिलाफ अपने समुदाय के सदस्यों के कथित तौर पर यह कहने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि 'आत्महत्या करने के बजाए पुलिसवालों को मार डालो'

सितंबर 2012

जनवरी 2013

अक्टूबर 2015

अक्टूबर 2015

फरवरी 2016



विजयानंद गुप्ता/गेट्टी इमेजेज

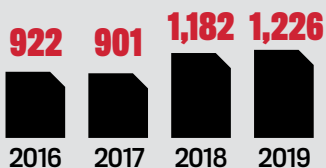
एआइएडीएमके, तमिलनाडु तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की 'मानहानि करने वाली सामग्री' के लिए लोकगायक और शराब-विरोधी आंदोलनकारी **शिवा राज उर्फ कॉमरेड कोवन** को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया

भाजपा, दिल्ली पुलिस संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में 'राजद्रोही नारों' का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए जेएनयू छात्र यूनियन के पूर्व अध्यक्ष **कन्हैया कुमार** और दो अन्य-**उमर खालिद** और **अनिर्वाण भट्टाचार्य** के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया

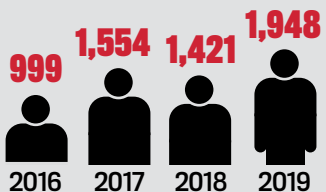
यूपीए के पंजे

गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूपीए) के तहत दर्ज मामलों की संख्या उछाल लेने लगी है, खासकर छह राज्यों मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरल इसमें सबसे आगे

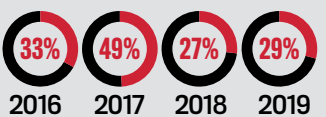
मामले दर्ज



लोग गिरफ्तार



सजा की दर



सिर्फ **132** को ही सजा यूपीए के तहत 2016 से 2019 के बीच हो पाई, जबकि

5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी सजा की दर 2.2 फीसद रही

से ही राज्यसत्ता के विरुद्ध अपराधों का डेटा प्रकाशित करना शुरू किया है, जिनमें 124ए सरीखे प्रावधानों और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून 1967 के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। इसी वजह से स्वतंत्र जानकार राजद्रोह के कानूनों के उपयोग या दुरुपयोग के बारे में विभिन्न सरकारों की तुलना करने में सावधानी बरतते हैं। *सेडिशन इन लिबरल डेमोक्रेसीज* (उदार लोकतंत्रों में राजद्रोह) की लेखिका, दिल्ली स्थित डॉ बी.आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस और सिटिजनशिप में असिस्टेंट प्रोफेसर अनुष्का सिंह कहती हैं, "2014 से मामलों में उछाल दिखने की एक वजह यह है कि सरकारी डेटा केवल 2014 के बाद का ही मौजूद है और इसलिए तुलना कर पाना मुश्किल है."

आइपीसी की इस धारा का दुरुपयोग करने के लिए बेशक सिर्फ भाजपा ही दोषी नहीं है। जून 2019 में छत्तीसगढ़ के एक 53 वर्षीय शख्स के ऊपर राजद्रोह का नोटिस थमा दिया गया था। वजह यह थी कि एक फेसबुक वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस सरकार और इनवर्टर कंपनियों की मिलीभगत से राज्य में बिजली की कमी पैदा हुई है।

लेकिन सबसे चिंताजनक यह है कि राजद्रोह के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और हेरतअंगेज आधारों पर लगाए जा रहे हैं। पिछले साल जनवरी में कर्नाटक पुलिस ने सीएए-एनआरसी को लेकर मंचित नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खराब ढंग से पेश करने के आरोप



टीआरएस, तेलंगाना

एआइएमआइएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद **असदुद्दीन ओवैसी** के खिलाफ उनके इस बयान के बाद राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया कि एक कथित आइएस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप में एनआइए द्वारा गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के लोगों को वे कानूनी मदद मुहैया करेंगे

भाजपा, झारखंड

झारखंड पुलिस ने पादरी और ऐक्टिविस्ट **रहेन स्वामी** तथा 19 अन्य लोगों के खिलाफ पत्थलगड़ी का आयोजन कर रहे गांवों में सरकार की ज्यादतियों पर सवाल उठाने वाली फेसबुक पोस्ट के लिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। पत्थलगड़ी वहां इसका प्रतीक है कि गांव की सवायत्ता संप्रभु है

एएनआइ



मंदार देवधर

जुलाई 2016

जून 2018

जुलाई 2018

जून 2019

अक्टूबर 2019

जद(यू)-भाजपा, बिहार

बिहार पुलिस ने पांच नाबालिगों सहित **आठ लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने एक** ऐसे गाने पर नाचा था जिसमें 'मुजाहिदों' का वर्णन था जिन्होंने 'भारत को धमकाया था'

कांग्रेस, छत्तीसगढ़

एक 53 साल के शख्स पर उस वीडियो के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में बिजली की कमी सरकार और इनवर्टर कंपनियों के बीच मिलीभगत का नतीजा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हस्तक्षेप के बाद राजद्रोह का आरोप हटा दिया गया

जद(यू)-भाजपा, बिहार

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मॉब लिंगिंग की बढ़ती घटनाओं के मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग करने वाली **49 जानी-मानी शख्सियतों के** खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। उन्हें सांप्रदायिक फूट पैदा करने और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का आरोपी बनाया गया। एक हफ्ते बाद मामला खत्म कर दिया गया

में एक प्राथमिक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद प्रधानाध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया। एक छात्र की मां को भी इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने नाटक में ऐसा संवाद लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री को चांटा मारने का जिक्र था।

अनुष्का 2014 के पहले और बाद के राजद्रोह के विमर्श में आए अहम बदलाव की तरफ भी इशारा करती हैं। कई सरकारों ने लोगों के आंदोलनों को दबाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज तमाम आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों पर 'राष्ट्र विरोधी' होने का ही आरोप चर्चा कर दिया जाता है। 2010-11 में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों के विरुद्ध राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन तब प्रदर्शनकारियों को परमाणु बिजली के विरोधियों के तौर पर देखा गया, न कि राष्ट्र विरोधी।

अनुष्का कहती हैं, "किसी भी किस्म के मतभेद को, चाहे वह अभिव्यक्ति, प्रदर्शन या संगठन किसी रूप में हो, राष्ट्र विरोधी करार देना आज की रवायत बन गई है। इससे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कानूनों का इस्तेमाल सामान्य बन गया है। इससे मामलों की संख्या बढ़ गई है, और यह इन विरोध प्रदर्शनों की वैधता को चुनौती देने में सरकार की मदद भी करता है। आम धारणा में वे लोगों के आंदोलन नहीं रह जाते, बल्कि उन्हें राष्ट्र विरोधी के रूप में समझा जाने लगता है।"

ऐक्टिविस्टों को खलनायक के तौर पर पेश करने और गिरफ्तारियों

एहतियातन हिरासत

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या

501
2017

697
2018

489
2019

स्रोत: एनसीआरबी और संसद

को जायज ठहराने में सोशल मीडिया, और कई बार पारंपरिक मीडिया भी, अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ, इस अफसाने की स्वीकृति भी बढ़ती गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा राजद्रोह कानून के प्रावधानों को और ज्यादा कठोर बनाएगी, तब सभा में जोरदार स्वागत हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को सही ठहराने के लिए उन तत्वों के कथित खतरे की दुहाई देते हैं जो चुनी हुई सरकार पर हमले करने के लिए विदेशी संगठनों और यहां तक कि संदिग्ध ताकतों की भी मदद लेने को तैयार हैं। वे कहते हैं, "भारतीय लोकतंत्र अपने



भाजपा, कर्नाटक

कर्नाटक पुलिस ने सीए और एनआरसी के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को खराब ढंग से दिखाने वाले एक नाटक के लिए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के बाद **स्कूल की प्रधानाध्यापिका** को गिरफ्तार कर लिया। पीएम को चांटा मारने का जिक्र करने वाले संवाद के लिए एक छात्र की मां को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में राजद्रोह हटा लिया गया

भाजपा, उत्ता प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 'राष्ट्र विरोधी नारे' लगाने और दंगा करने के लिए 16 साल के एक लड़के सहित **19 लोगों को राजद्रोह** के आरोप में गिरफ्तार किया गया

जनवरी 2020

भाजपा, असम

साहित्यकार **हीरेन गोहेन** और आरटीआइ ऐक्टिविस्ट **अखिल गोर्गोई** के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने एक जनसभा में कथित तौर पर कहा था कि केंद्र सीए 2019 के खिलाफ असमिया लोगों की आवाज को अनसुना करता है तो संप्रभुता की मांग उठ सकती है

जनवरी 2020



बंदीप सिंह

फरवरी 2020

भाजपा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा

दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को 'अपुष्ट खबर साझा करने' के लिए कांग्रेस सांसद **शशि थरूर** और कई पत्रकारों के खिलाफ तीन भाजपा शासित राज्यों में राजद्रोह के मुकदमे किए गए। उनके विरुद्ध दुर्घटना में मारे गए एक प्रदर्शनकारी के बारे में दृवीट करने के लिए मुकदमे किए गए कि वह रैली के दौरान दिल्ली पुलिस की गोली से मारा गया

जनवरी 2021

फरवरी 2021

भाजपा, दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन साझा किए गए एक डिजिटल 'टूल किट' का कथित तौर पर संपादन करने के लिए 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता **दिशा रवि** को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा में कथित भूमिका के लिए इस टूलकिट की जांच की जा रही है

नागरिकों को संवैधानिक तौर पर स्वीकृत चुनाव प्रक्रिया के जरिए सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने का विकल्प मुहैया करता है। क्या कोई सत्तारूढ़ सरकार से खुश नहीं है तो क्या विदेशी ताकतों की मदद लेने को जायज ठहराया जा सकता है?"

लेकिन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा कहते हैं, "सरकार की सभी और किसी भी आलोचना को राष्ट्र विरोधी और राजद्रोही मान लिया जाता है। राजद्रोह का कानून हालांकि औपनिवेशिक काल में बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसे काफी नरम बनाया है। अलबत्ता आज जिस तरह इसे लागू किया जा रहा है, वह बताता है कि इसका औपनिवेशिक चरित्र बनाए रखा गया है।" सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर, 2016 को एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है।

मगर कोहली इसे इसलिए पूरी तरह जायज मानते हैं, क्योंकि मौजूदा निजाम को बदनाम करने के व्यापक अभियान छेड़ दिया गया है। वे कहते हैं, "किसी भी ईमानदार और निष्पक्ष रिसर्च से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी हमले देश में किसी भी प्रधानमंत्री पर इस कदर नहीं हुए। पिछले छह साल में उन्हें देश की किसी भी और हेक अप्रिय घटना के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मोदी के खिलाफ ज्यादातर निजी निंदा-तिरस्कार तथ्यों से प्रमाणित नहीं बल्कि दुर्भावना से प्रेरित एजेंडों का नतीजा है।" उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई, निवेश और निर्यात, कपड़ा, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री तथा राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह उनसे सहमत हैं। वे कहते हैं,



न्यायमूर्ति बी.एन.

श्रीकृष्णा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

“किसी भी वैध विरोध प्रदर्शन में उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं तो कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। यह पहले भी हो चुका है। यह सत्तारूढ़ सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा संदेश दे कि उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा”



विक्रम शर्मा

दमन के औजार

देश की संप्रभुता की रक्षा और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए बनाए गए कानूनों का विरोधियों को खामोश करने के औजार के तौर पर इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है

राजद्रोह

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए राजद्रोह को ऐसे बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्यांकन या अन्य अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिनसे 'घृणा पैदा हो या मानहानि' हो, या जो सरकार के प्रति 'अलगाव को उकसाते या उकसाने का प्रयत्न' करते हैं. (अलगाव या वैमनस्य को द्रोह या शत्रुता की भावना के रूप में परिभाषित किया गया है.) हालांकि सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के प्रति अस्वीकृति दर्शाने वाले उन कथनों या टिप्पणियों को, जो सरकार से उन कदमों को बदलवाने की मंशा से किए गए हैं, तब तक राजद्रोह नहीं माना जाता जब तक कि वे सरकार के प्रति घृणा, अवमानना

या अलगाव नहीं उकसाते या उकसाने का प्रयत्न नहीं करते.

कठोर प्रावधान

राजद्रोह संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस इस अपराध के आरोपी को वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है. यह गैर-जमानती और गैर-समाधेय अपराध है (गैर-समाधेय का अर्थ यह है कि आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते के जरिए इसका समाधान नहीं किया जा सकता). 124ए के तहत आरोपित व्यक्ति सरकारी पद धारण नहीं कर सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ता है. सजा में कैद (तीन साल से ताउम्र तक), जुर्माना, या दोनों शामिल हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980

(एनएसए) 'कुछ निश्चित मामलों और उनके साथ जुड़े विषयों में एहतियातन हिरासत' का प्रावधान करता है. यह केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि वे ऐसे लोगों को हिरासत में रखें, जो 'देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों के प्रति पूर्वाग्रह' से संबंधित हरकत कर सकते हैं, या 'सार्वजनिक व्यवस्था या अनिवार्य आपूर्तियों और सेवाओं में खलल' डालने की मंशा रखते हैं.

कठोर प्रावधान

एनएसए के तहत लोगों को बगैर किसी आरोप-पत्र के 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है. लोगों को उन्हें हिरासत में लेने का कारण बताए बगैर 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति हाइकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकते हैं, लेकिन

सुनवाई के दौरान उन्हें वकील रखने की इजाजत नहीं है.

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून 1967

इस कानून का उद्देश्य देश की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार देना है.

कठोर प्रावधान

यूएपीए आरोप लगाए बगैर 180 दिनों तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है. 2019 में किए गए संशोधन केंद्र सरकार को मुकदमा चलाए बगैर किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार देते हैं. हिरासत 30 दिन बढ़ाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2021 को निर्णय दिया कि अगर त्वरित मुकदमा चलाने के अधिकार का को जमानत दी जा सकती है

फैजान मुस्तफा

कुलपति, एनएएलएसएआर
यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ,
हैदराबाद



“ लोगों की स्वतंत्रता की रक्षक होने के नाते न्यायपालिका को निजी आजादी की रक्षा पुरजोर ढंग से करनी चाहिए. हाल के दौर में ऐसी प्रतिबद्धता के दर्शन कम हुए हैं. कई अलोचक हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका की ओर झुका पाते हैं ”

सिद्धार्थनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता
तथा एमएसएमई, निवेश और
निर्यात, टेक्सटाइल, खादी और
ग्रामोद्योग मंत्री



“ हर किसी को बोली और अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर किसी को गलत तथ्य पेश करके सरकार को बदनाम करने की इजाजत नहीं है. इसके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी ”

“सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को भी गलत तथ्य पेश करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की इजाजत नहीं है. ऐसा करने के वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है.”

जवाब में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर कहते हैं, “सत्ताधारी चुनिंदा ढंग से असहिष्णुता का इजहार कर रहे हैं. विरोधी विचार रखने वाले लोगों को मनमाने ढंग से चुना जाता है लेकिन असामाजिक तत्वों के खिलाफ नरमी बरतते हैं.” दिशा को जमानत की मंजूर करने के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने अपने आदेश में बेहद कटु टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “लोगों

सरकार की अंतरात्मा के रखवाले हैं. उन्हें केवल इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उन्होंने राज्यसत्ता की नीतियों से असहमत होना चुना है. सरकार के आहत अभिमान की देखभाल के लिए राजद्रोह का सहारा नहीं लिया जा सकता.”

प्रक्रिया ही सजा

राजद्रोह का आरोप असहमति को कुचलने के असरदार औजार के तौर पर इसलिए भी उभरकर आया है क्योंकि इसमें मुकदमे से पहले ही खासा परेशान करने की गुंजाइश होती है. इसमें वह समानांतर अभियान भी शामिल है जो खास तौर पर सोशल मीडिया में चलता है. संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होने की वजह से राजद्रोह के आरोपी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है. सजा में तीन साल से ताउम्र तक कारावास, जुर्माना, या दोनों शामिल हैं. इतना ही नहीं, 124ए के तहत आरोपी व्यक्ति की सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लग जाता है और उसे अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ता है.

इन कानूनों के साथ मुकदमे से पहले के चरण में जटिल और दुरुह कानूनी प्रक्रिया जुड़ी है और इसलिए इसके पीछे मंशा अक्सर अपराधी को कानून के कठघरे में लाने के बजाए असहमत आवाजों को परेशान करने की होती है. अनुष्का ने अपने शोध में पाया कि लोगों ने महज जमानत हासिल करने के लिए 90,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक खर्च किए. बेंगलूरू स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एसिस्टेंट प्रोफेसर कुणाल अंबष्ठ कहते हैं, “अगर किसी को मुकदमे के बगैर हफ्तों या महीनों तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है तो मुकदमे के अंतिम निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता. लिहाजा, इन कानूनों में ऐसा है जिसमें प्रक्रिया ही सजा बन जाती है.”

राजद्रोह के ज्यादातर मामले वाजिब वजहों के बगैर दर्ज किए जाते हैं, यह साल-दर-साल सजा होने की दर बेहद कम होने से भी जाहिर है. राजद्रोह के मामलों की तादाद जहां 2016 में 35 से बढ़कर 2019 में 93 हो गई, वहीं सजा की दर इसी अवधि में 33.3 फीसद से घटकर 3.3 फीसद पर आ गई. अनुष्का इसके लिए पुलिस बलों में कानूनी निरक्षरता के साथ-साथ राजनैतिक प्रतिष्ठान के दबाव में इसके दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराती हैं.

यहां तक कि पूर्व पुलिस अफसर भी स्वीकार करते हैं कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपने राजनैतिक आकाओं के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इन कानूनों का अक्सर दुरुपयोग करती हैं. बीएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस और असम पुलिस के पूर्व डायरेक्टर-जनरल प्रकाश सिंह कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि पुलिस इन कानूनों की बारीकियां नहीं समझती है, लेकिन ऐसे भी मौके आते हैं जब कार्यपालिका की तरफ से किसी खास व्यक्ति या समूह के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ जाने के अलिखित निर्देश होते हैं.”

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां 124ए सरीखे प्रावधानों की लचीली रूपरेखा का फायदा उठाती हैं. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने भी—केदारनाथ सिंह और बलवंत सिंह के मामलों में—पुलिस और राजनैतिक प्रतिष्ठान के हाथों गलत व्याख्या और दुरुपयोग की गुंजाइश छोड़ दी. अनुष्का कहती हैं, “असल में हमारे देश ऐसे न्याय-सिद्धांतों की बहुतायत नहीं है जो बोली की आजादी को व्यापक दायरे में ले जाता है और लोगों की स्वतंत्रता की हर कीमत पर रक्षा करता है. सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह मामले में फैसला दिया था कि हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति राजद्रोह है. अब प्रवृत्ति इतना व्यापक और अस्पष्ट शब्द है कि किसी भी चीज की हिंसा की ओर प्रवृत्त चीज के तौर पर व्याख्या की जा सकती है.” यही लचीला

असहमति का उसका अधिकार

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिशा रवि को जमानत देकर दिल्ली की एक अदालत ने सरकार से असहमति रखने के अधिकार को जायज बताया

केपीएन फोटो



कुल जमा 22 बरस की दिशा रवि कुछ हफ्तों पहले तक महज एक और उत्साही पर्यावरण कार्यकर्ता थीं. मगर 14 फरवरी को जब दुनिया वेलेंटाइन दिवस मना रही थी, बेंगलूरु की इस लड़की को दिल्ली पुलिस ने केंद्र के खिलाफ 'अलगाव' पैदा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया. कानून की किताबों में भारतीय दंड संहिता की जिस धारा 124ए के तहत दिशा को गिरफ्तार किया गया, वह यही कहती हैं. पुलिस हिरासत में पांच दिन और न्यायिक हिरासत में चार दिन बिताने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. दिल्ली की एक अदालत ने कटु टिप्पणी की और कहा कि दिशा के काम को राजद्रोह नहीं माना जा सकता.

मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक के साथ दिशा पर आरोप लगाया गया कि उसने किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए एक ऑनलाइन 'दूलकिट' का संपादन किया था. 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में इस दूलकिट की अब जांच की जा रही है. दिशा ने अदालत में कहा कि उसने यह दूलकिट नहीं बनाया, पर स्वीकार किया कि उसने इसमें 'दो पंक्तियां संपादित' की थीं. बेंगलूरु के माउंट कारमेल कॉलेज से ग्रेजुएट दिशा जलवायु कार्रवाई समूह फ्राइडेज फॉर फ्यूचर (एफएफएफ) की भारत प्रमुख हैं. यह संगठन स्वीडन की जलवायु ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने 2018 में शुरू किया था. जैकब और मुलुक पर्यावरण से जुड़े वैश्विक आंदोलन एक्स्टिंक्शन रिबेलियन का हिस्सा हैं.

इस दूलकिट में कथित तौर पर "26 जनवरी को कार्रवाई के बिंदुओं, डिजिटल हमले और भौतिक कार्रवाई" का जिक्र किया गया है. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, 26 जनवरी की हिंसा उस 'कार्य योजना के हूबहू अमल' का पर्दाफाश करती है जिसके ब्योरे दूलकिट में दिए

गए हैं और जिसमें 'योग तथा चाय सहित देश की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने और विदेश स्थित विभिन्न राजधानियों में भारतीय दूतावासों को निशाना बनाने' का भी जिक्र है. तत्काल की जाने वाली कार्रवाइयों में 'ट्विटर स्टॉर्म' और दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं. फरवरी के पहले हफ्ते में कई वैश्विक शख्सियतों ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में दूवीट किए थे, जिनमें अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, वकील-ऐक्टिविस्ट मीना हैरिस (अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी) और पूर्व वयस्क मनोरंजनकर्ता मिया खलीफा शामिल थीं.

इस दूलकिट पर दुनिया की नजर तब पड़ी जब 2 फरवरी को थनबर्ग ने इसे दूवीट किया. बातचीत के जो लिखित ब्योरे लीक किए गए, वे

“ लोग सरकार के नैतिक
पहराए हैं...उन्हें सिर्फ इसलिए
जेल में नहीं डाला जा सकता
कि वे सरकार की नीतियों
से असहमत हैं...राजद्रोह का
अपराध बस सरकार के आहत
अभिमान को सहलाने के लिए
नहीं लगाया जा सकता ”



धर्मेन्द्र राणा
अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश

बताते हैं कि थनबर्ग के दूवीट के कुछ ही पल बाद दिशा ने उनसे कहा कि इस दस्तावेज को पोस्ट न करें क्योंकि उन दोनों के नाम इसमें हैं. उन्होंने थनबर्ग से यह भी कहा कि इस बारे में "कुछ वक्त के लिए बिल्कुल कुछ न बोलें" क्योंकि उन्हें गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून 1967 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

दिशा का डर 4 फरवरी को सच साबित हुआ जब दिल्ली पुलिस ने दूलकिट बनाने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली और उन पर, अन्य धाराओं के अलावा, राजद्रोह का आरोप लगाया. पुलिस ने दावा किया कि दूलकिट कनाडा स्थित और कथित खालिस्तान-समर्थक धड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) ने तैयार और दिशा ने संपादित किया था, जिसे बाद में थनबर्ग के साथ साझा किया गया. यह भी दावा है कि दिशा, जैकब और मुलुक ने पीजेएफ की एक जूम मीटिंग में हिस्सा लिया था. 21 और 27 जनवरी के बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में मुलुक की मौजूदगी का भी हवाला दिया गया.

दिशा की गिरफ्तारी के तीन दिनों के भीतर जैकब और मुलुक ने मुंबई हाइकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ अस्थायी राहत हासिल कर ली. मुलुक ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया. दिशा को जमानत की मंजूरी देते हुए 23 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद थोड़े-से और आधे-अधूरे सबूतों पर विचार करते हुए मुझे जमानत से इनकार करने का कोई साफ कारण नहीं मिला." उन्होंने दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणियां भी कीं और कहा कि "लोग सरकार के नैतिक पहराए हैं... उन्हें इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं."

ढांचा इसके दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा करता है.

दमन के अन्य कानून

केवल 124ए ही नहीं, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए, 1967; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या एनएसए, 1980; जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम या पीएसए, 1978; और धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए, 2002 जैसे अन्य कठोर कानूनों का भी दोषपूर्ण तरीके से दुरुपयोग किया जाता रहा है. ये सरकार के लिए बड़े उपयोगी होते हैं क्योंकि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी लंबी अवधि तक हिरासत में रखने का अधिकार देते हैं. मसलन, यूएपीए किसी को भी बिना किसी आरोप के 180 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है. 2019 में कानून में एक संशोधन से केंद्र को बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने की शक्ति मिल गई है. यूएपीए में आतंकवादी के रूप में घोषित व्यक्तियों या संगठनों को अदालत में चुनौती देने की व्यवस्था नहीं है. खुद को आतंकवादी की सूची से बाहर कराने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करना होता है.

यूएपीए के दुरुपयोग के दो शानदार उदाहरण सीपीआइ (माओवादी) के प्रवक्ता गौर चक्रवर्ती और ऐक्टिविस्ट अरुण फरेरा के खिलाफ मुकदमे हैं. जून 2009 में, केंद्र सरकार ने भाकपा (माओवादी) पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद, चक्रवर्ती पर यूएपीए चर्प्सां कर दिया था और 2016 में बरी होने से पहले उन्होंने सात साल जेल में बिताए. फरेरा को भी 2007 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और बरी होने से पहले उन्हें पांच साल तक जेल में रखा गया था. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह कहते हैं, "लचर जांच-पड़ताल और बदतर अभियोजन के कारण ज्यादातर

नलिन कोहली

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा तथा सुप्रीम कोर्ट के वकील



“ 2014 से लेकर 2021 की घटनाएं यही हवाला देती हैं कि हाल के दौर में किसी सरकार को अपने कामकाज में ऐसे तत्वों से संगठित और व्यापक अभियान का सामना नहीं करना पड़ा, जो विदेशी संगठनों और संदेहास्पद तत्वों से भी मदद में नहीं हिचकते ”

आरोपी बरी हो जाते हैं. बरी होने पर जिम्मेदारियां तय करना जरूरी है. इससे कानून के दुरुपयोग और खराब जांच और अभियोजन दोनों को रोका जा सकेगा. ”

फरेरा के अलावा वकील सुधा भारद्वाज और ऐक्टिविस्ट गौतम नवलखा और वर्नोन गोंजाल्विस सहित कई अन्य लोग फिलहाल 2018 में भीमा-कोरेगांव की हिंसा में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद हैं. उन सभी पर पुणे पुलिस ने यूएपीए चर्प्सां किए हैं. 80 साल के कवि और माओवादी विचारक वरवर राव को पिछले हफ्ते स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिल गई. 2020 में, जांच का जिम्मा एनआइए ने संभाल लिया, और उसने झारखंड स्थित ऐक्टिविस्ट स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर भी यूएपीए के तहत आरोप लगाए.

दरअसल, जमानत का यह लंबा इंतजार यूएपीए को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ सरकारी दमन का एक साधन बनाता है. 2016 और 2018 के बीच, 3,005 मामले इस आतंकवाद-रोधी कानून के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर केवल 821 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए थे. 2016 और 2019 के बीच, यूएपीए के तहत 5,922 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन केवल 132 को दोषी ठहराया जा सका. लंबे समय के लिए जेल में बंद रखने के इस चलन से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को फैसला सुनाया कि अगर किसी पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए जाते हैं, तो भी उसके पास त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का उल्लंघन होने पर वह जमानत का हकदार है.

हालांकि, यूएपीए से अधिक एनएसए का दुरुपयोग किया जाता है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी आदेशों और आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने सहित कुछ अन्य आधार पर लोगों को पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से काम करने से रोकना है. यह सरकार को बिना कारण बताए किसी को 10 दिनों के लिए हिरासत में रखने और बिना आरोप तय किए 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है.

फरवरी 2019 में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने गोहत्या और तस्करी के आरोपी पांच लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया. 3 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने संसद में स्पष्ट किया, "कृषि गतिविधियों और बूचड़खाने के लिए मवेशियों का परिवहन एनएसए के तहत दंडनीय अपराध नहीं है." इसके बावजूद यूपी पुलिस ने 19 अगस्त, 2020 तक गोहत्या के लिए 76 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत चालान किया था. एक संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा था, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ऐसे अपराधों के मामले में एनएसए लगाया जाना चाहिए, जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है ताकि अपराधियों में भय और जनता के बीच सुरक्षा की भावना पैदा हो."

डॉक्टर कफील खान को बिना मुकदमे के सात महीने तक हिरासत में रखने के लिए इसी कानून का इस्तेमाल किया गया था. 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ और उत्तेजक भाषण देने के आरोप में डॉ. खान को गिरफ्तार किया था. 10 फरवरी को अलीगढ़ की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन चार दिन बाद डॉ. खान के खिलाफ एनएसए के तहत आरोप लगा दिए गए. 1 सितंबर, 2020 को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत को अवैध माना

और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। हालांकि, मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहते हैं कि डॉ. खान के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। 2017 और 2018 के बीच एनएसए के तहत बंद किए गए 1,198 लोगों में से सबसे ज्यादा 795 लोगों को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश नंबर वन बना हुआ है।

2002 में बनने और 2019 में संशोधनों के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अत्यधिक जटिल और विवादास्पद बना हुआ है, विशेष रूप से अभियुक्त को गिरफ्तारी और जमानत देने के संबंध में। पीएमएल अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को कुछ मामलों में, बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार है। यही कारण है कि ईडी केंद्र के लिए सीबीआई से भी अधिक शक्तिशाली हथियारों में से एक बना दिया है।

कानून में किसी को गिरफ्तार करने से पहले, ऐसा “मानने का कारण” होना चाहिए कि अभियुक्त जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर धन शोधन के अपराध का दोषी है। गिरफ्तारी से पहले कारण को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए, एक तरह से, कानून केवल संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तारी से बचाता है।

फिर भी, व्यवहार में, ईडी के अधिकारी जांच नाम पर, या यहां तक कि जांच के दौरान ‘असहयोग’ के लिए गिरफ्तारी करते हैं। यही कारण है कि पीएमएलए के तहत सजा की दरें अचानक कम हो गई हैं। पीएमएलए के तहत, ईडी ने 1,569 विशिष्ट जांचों के सिलसिले में मार्च 2011 से जनवरी 2020 के बीच 1,700 से अधिक छापे मारे। हालांकि, यह केवल नौ में ही सजा दिलाने में कामयाब रहा। अप्रैल 2017 और फरवरी 2020 के बीच, पीएमएलए के तहत 578 मामले दर्ज किए गए हैं, और ईडी ने लगभग 25,000 व्यक्तियों या संस्थाओं को मनी-लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच के संबंध में बुलाया।

एक और कड़ा अधिनियम, जिसके इस्तेमाल पर प्रश्न उठते रहे हैं, वह जम्मू-कश्मीर में पीएसए है। यह एहतियातन गिरफ्तारी कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को ‘राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था’ के खिलाफ किसी भी तरह का कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने तक बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और ‘राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा’ होने की स्थिति में दो साल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

शेख अब्दुल्ला ने 1978 में विशेष रूप से लकड़ी के तस्करों को निशाना बनाने के लिए कानून बनाया था, लेकिन दशकों से इस कानून का इस्तेमाल राजनैतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता रहा है। 2015 में, एक आरटीआई के जवाब में, सरकार ने खुलासा किया कि 1988 से पीएसए के तहत 16,329 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 2007 और 2016 के बीच, पीएसए के तहत 2,400 से अधिक गिरफ्तारी आदेश पारित किए गए थे, जिनमें से 58 प्रतिशत अदालतों द्वारा रद्द कर दिए गए थे।

दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य के कुछ कानूनों में से एक



प्रतिरोध की आवाज

कन्हैया कुमार, जिन पर
2016 में राजद्रोह का आरोप
मढ़ा गया

को बरकरार रखा गया है। तब से, पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सहित बड़ी संख्या में नेताओं के खिलाफ पीएसए लागू किया गया है। जेएंडके कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऐंड एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसएब्लिटीडर्स पर्सन्स की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2019 में 662 व्यक्तियों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। इस कानून को लागू करने के कुछ कारणों की कड़ी आलोचना हुई है। महबूबा मुफ्ती के डोजियर में कहा गया कि उनकी पार्टी के झंडे का रंग हरा है, जो कट्टरपंथी इरादे को दर्शाता है।

लेकिन यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में एक गैर-मौजूद प्रावधान—धारा 66 ए—है जो कानून की निरंकुशता का प्रतीक है। धारा 66 ए ऑनलाइन संचार के माध्यम से “घृणास्पद संदेश” भेजने को लेकर दंडित करने का अधिकार देता है जो अधिकारियों को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। हालांकि, कानून ‘घृणास्पद’ की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। नेताओं ने अक्सर महत्वपूर्ण आवाजों को चुप कराने के लिए कानून के इस प्रावधान का उपयोग किया है। अप्रैल 2012 में, कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को 65 लोगों को एक ई-मेल भेजने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्टून था। उन्हें और उनके पड़ोसी सुब्रत सेनगुप्ता को धारा 66 ए का उल्लंघन करने के लिए जादवपुर थाने की हवालात में एक रात गुजरानी पड़ी। मार्च 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दिया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आइएफएफ) के ट्रैकर के अनुसार, अप्रैल 2015 से फरवरी 2020 के बीच, 1,297 मामले 10 राज्यों की अदालतों में चल रहे हैं।

आइएफएफ के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता पूछते हैं, “अगर यह असंवैधानिक है, तो इस विशेष धारा के तहत लोगों के खिलाफ ताजा और पुराने मुकदमे कैसे चल सकते हैं?” कुछ पुलिस अधिकारी उन कानूनी प्रावधानों के लचीलेपन की सराहना करते हैं जो शब्दों और दायरे में अस्पष्ट रहते हैं। इसलिए, वे इस असंवैधानिक प्रावधान का उपयोग करते रहते हैं क्योंकि इससे उन्हें



एम. झांजी

अपनी नजर में आने वाले ऑनलाइन अपराध को इसी प्रावधान के तहत असंवैधानिक घोषित करने में मदद मिलती है। गुप्ता ने दिल्ली हाइकोर्ट के वकील अभिनव सेखरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें इस कानून के दुरुपयोग के मामले अदालत के संज्ञान में लाए गए। शीर्ष अदालत ने फरवरी 2019 में निर्देश दिया कि सभी पुलिस स्टेशनों और जिला अदालतों को 2015 के फैसले की एक प्रति प्रदान की जाए। इस निर्देश के एक साल बाद भी, आइएफएफ ट्रैकर ने 10 राज्यों में विभिन्न अदालतों में धारा 66 ए के तहत 245 मामले पाए।

न्यायपालिका की भूमिका

न्यायिक आदेशों के प्रति कार्यपालिका के उदासीनता भरे रवैए ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आश्वस्त करने में न्यायपालिका की भूमिका को भी सार्वजनिक छानबीन के दायरे में ला दिया है। संविधान विशेषज्ञों और न्यायविदों का मानना है कि अदालतें नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में सही वक्त पर सक्रियता से अपनी भूमिका निभा देने में नाकाम रही हैं। एहतियातन हिरासत में रखने के प्रावधानों से जुड़े अधिकतर कानूनों के मामले में, राहत की एकमात्र गुंजाइश हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ही है।

बहरहाल, देश की घोंघाचाल चलने वाली न्यायपालिका, जो लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ तले दबी हुई है, कई मौकों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में चूक गई है। हैदराबाद के एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कहते हैं, “न्यायपालिका को बड़ी चौकसी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा

करनी चाहिए। हाल में, ऐसी प्रतिबद्धता में थोड़ी कमी रही है। महीनों तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को न सुनकर और वास्तविक मामलों में भी जमानत न देकर, न्यायपालिका ने आलोचनाओं को न्योता दिया है। अदालतों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी का जीवन या उसकी आजादी खतरे में पड़ी होती है।” जस्टिस लोकुर अधिक कटु हैं। वे पूछते हैं, “बदकिस्मती से न्यायपालिका थोड़ी बुजदिल रही है और अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया है, वरना लोगों को एहतियातन हिरासत में महीनों रखे जाने की व्याख्या आप कैसे करेंगे?”

मसलन, 6 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राजद्रोह के अपराधिक मामले दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश मांगे गए थे। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनिच्छा न्यायपालिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अत्यधिक सतर्क रवैया अपनाने से उपजी है। अनुष्का कहती हैं, “जब किसी चीज को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की तरह पेश किया जाता है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका के प्रति आदर भरा रवैया अपनाती है जैसा कि हमने टाढ़ा या पोटा की संवैधानिकता बरकरार रखने के मामले में देखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस अधिकारों के न्यायशास्त्र पर हावी हो जाती है।” जस्टिस श्रीकृष्ण इसमें जोड़ते हैं, “न्यायपालिका के कुछ अबूझ कामों ने इस धारणा को बल दिया है कि यह लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर काम करने में या तो अक्षम है या फिर अनिच्छुक। न्यायपालिका को आत्म-निरीक्षण करना चाहिए और ऐसी धारणा को तोड़ने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।”

अंबष्ठ कहते हैं, “राजद्रोह कानून का इतिहास है कि इसका इस्तेमाल औपनिवेशिक ताकतों ने मतभेद और असंतोष को दबाने के लिए किया है। लोकतंत्र में उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए।”

2018 में, विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि अब धारा 124ए पर पुनर्विचार करने या इसको खत्म करने का समय आ गया है। ब्रिटेन में, जहां इस राजद्रोह कानून की शुरुआत हुई, इसे 2009 में खत्म कर दिया गया।

बहरहाल, इस बात पर तकरीबन सर्वानुमति है कि जमीनी स्तर पर इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए, इसमें संशोधन की सख्त जरूरत है। जस्टिस लोकुर पूछते हैं, “अगर राजद्रोह कानूनों को उसी तरीके से लागू किया जाना है जैसे कि आज किए जाते हैं तो इसे कानून की किताबों से हटा दिया जाना चाहिए। अगर इसे कानून की किताबों में बनाए रखना है तो संसद को यह तय करना चाहिए कि इसे अपवाद मामलों में ही इस्तेमाल किया जाए।” पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का सुझाव है कि पुलिसकर्मियों, खासतौर पर जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जो देशभर के विभिन्न कानूनों के बारे में हो।

पिछले हफ्ते, दिल्ली की एक अदालत ने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस के बारे में कथित रूप से एक फेसबुक पोस्ट शेयर किए जाने पर राजद्रोह के आरोप के मामले में दो लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून, “राज्य के हाथ में एक मजबूत हथियार है” और “इसे उपद्रवियों को शांत करने के बहाने मुखर लोगों को खामोश करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।” हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता पर कोई समझौता नहीं हो सकता लेकिन संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ■

न्यायमूर्ति मदन बी.

लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व
न्यायाधीश



“कानूनों मानवीय बनाने और उन पर मानवीय तरीके से अमल की दरकार है। अनेक मामलों में पुलिस हर तरह के कानून का दुरुपयोग करती पाई गई है। राजद्रोह जैसे कानून को बेहद अपवाद के मामलों में ही इस्तेमाल होना चाहिए”

उम्मीद के साथ अंदेशे

भारत में कोविड टीकाकरण लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसमें निजी क्षेत्र को शामिल करने की तेज होती मांग के बीच मार्च से बुजुर्गों को भी टीका लगने जा रहा

सोनाली आचार्य

जब डॉ. दिनेश कपाड़िया ने नई दिल्ली में कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने का फैसला किया तो उनकी पत्नी और दो बच्चों ने इसका सख्त विरोध किया। इसकी वजह थी उनकी 72 साल की उम्र। परिजनों को लगता था कि इस उम्र में डॉ. कपाड़िया को टीके के संभावित दुष्प्रभावों (साइड इफेक्ट्स) का जोखिम नहीं लेना चाहिए। घरवालों को समझाने में असमर्थ डॉ. कपाड़िया ने बिना बताए टीका लगवा लिया। परिवार को इसकी जानकारी उन्होंने दो हफ्ते बाद दी।

डॉ. कपाड़िया कहते हैं, “मैं बिल्कुल ठीक था। टीकाकरण केंद्र में भीड़ के कारण इंतजार में जो परेशानी हुई उसके अलावा कोई परेशानी मैंने अनुभव नहीं की। टीका लगवाने के बाद कोई लक्षण नहीं उभरे, न ही जहां इंजेक्शन लगने वाली जगह पर कोई सूजन हुई।” उनका मानना है कि उम्र ऐसा कोई पहलू नहीं है जिससे आप बहुत घबराएं। वे कहते हैं, “उम्र एक गिनती भर है। टीका लगवाना है या नहीं, इसका फैसला उम्र से नहीं बल्कि एलर्जी, स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक स्थिति और एलर्जी के इतिहास के आधार पर करना चाहिए।”

मार्च की शुरुआत से भारत 50 साल से ऊपर के लोगों का कोविड के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारी कर रहा है—1.1 करोड़ स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स पहले चरण में टीका लगवा भी चुके हैं—फिर भी लोगों में डर और भ्रम बना हुआ है। अंदेशे या भ्रम केवल टीके के दुष्प्रभावों को लेकर नहीं, बल्कि इसे लगवाने की प्रक्रिया को लेकर भी पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पर, बेंगलूरू के कोरमंगला में रहने वाली 75 वर्षीया सेवानिवृत्त बैंकर आशा सिंह का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया में तैरती कम से कम 12 पोस्ट मिली हैं जिनमें बताया गया है कि टीके के लिए पंजीकरण कैसे किया जाता है और ये सभी भ्रामक हैं।

सिंह के पास तो एक कॉल भी आई जिसमें उनसे टीका लगवाने के लिए आवश्यक पंजीकरण के लिए उनका विवरण पूछा गया था लेकिन वह एक स्पैम था। उनकी शिकायत है कि सरकार का आधिकारिक वैक्सीन पंजीकरण पोर्टल कोविन, उनके आइफोन पर काम नहीं करता है। वे कहती हैं, “पहले मुझे यह समझना था कि क्या यह वैक्सीन लेने के लिए सुरक्षित है, फिर यह पता लगाना था कि दोनों में से कौन-सा टीका मुझे लगे, क्या मैं यह तय कर सकती हूँ? और अब, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जूझ रही हूँ।” सिंह कहती हैं कि वे टीका लगवाने



कोविड के टीके के बहुत ही कम गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं। यहाँ तक कि पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त लोग भी डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन ले सकते हैं”

डा. रणदीप गुलेरिया
निदेशक, एम्स, दिल्ली



महामारी से मुकाबला

नई दिल्ली में कोविड टीका लगवाता एक फ्रंटलाइन वर्कर

के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अगर यह अत्यधिक भ्रामक हो जाता है, तो फिर वे सामाजिक दूरी के जरिए ही कोविड को दूर रखना पसंद करेंगी।

मधुमेह पीड़ित दिल्ली की 55 वर्षीय पूनम खन्ना टीके के संभावित दुष्प्रभावों से अनजान हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि अगर उनके जैसे लोग जिनकी सेहत पहले से ही बहुत अच्छी न हो तो टीका लगवाने का उन पर क्या असर हो सकता है। भ्रम की ऐसी स्थितियों को दूर करके ही पर्याप्त संख्या में लोगों को कोविड टीकाकरण के अगले चरण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के चैयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन कहते हैं, “मेरे पास कई रोगी हैं जो लगातार इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि उनके लिए टीका कब उपलब्ध होगा। हालांकि कुछ को संदेह है और उनका यह संदेह तथ्य

बताकर और इससे जुड़े आंकड़े मुहैया कर मिटाया जा सकता है।” मार्च वाले चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि टीका पंजीकरण, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि में खामियों को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका निजी क्षेत्र को इस काम में लगाना होगा। दिल्ली के मैक्स हेल्थकेयर के चिकित्सा निदेशक डॉ. संदीप बुद्धिराजा कहते हैं, “महामारी में हमने देखा कि लोगों ने कैसे इलाज के लिए निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में भरोसा जताया। मैं इस कल्पना से ही सिहर उठता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर से मदद न मिली होती तो महामारी में क्या स्थिति हुई होती।”

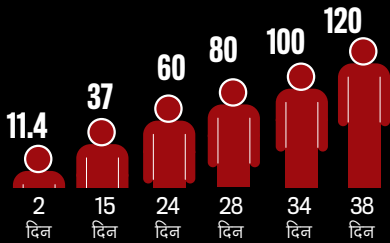
टीकाकरण के पहले दो चरणों में सरकार ने 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को

सुस्त-दुरुस्त

भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर एक नजर

चरण 1 और 2

16 जनवरी के बाद से टीका लगवा चुके लोगों की संख्या (लाख में)



3 करोड़

टीकाकरण का लक्ष्य है पहले 2 चरणों में

40%

लक्ष्य हासिल हुआ **(1.2 करोड़)** 24 फरवरी तक

तीसरा चरण

मार्च की शुरुआत में आरंभ होगा 50 साल से अधिक उम्र वालों के लिए

27 करोड़

की लगभग संख्या है जिन वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण होगा

30 महीने

लगेगे मौजूदा रफ्तार से लक्षित आबादी के टीकाकरण में

50 करोड़

लोगों को प्राइवेट सेक्टर में टीका लगाने का अनुमान लगाया गया है

50 लाख

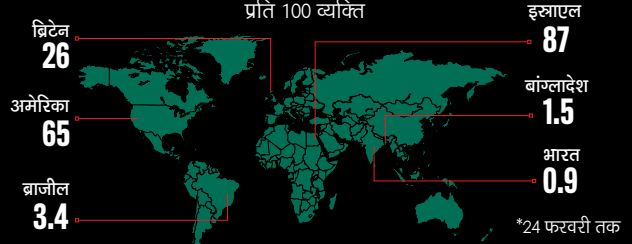
लोगों को रोज टीका लगाना होगा हर्ड इम्युनिटी के लिए, पिछले छह महीनों के एंटीबॉडीज के अनुमान पर

वैश्विक तुलना

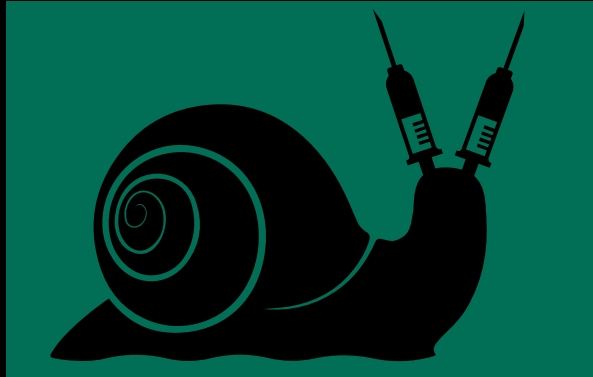
भारत ने हालांकि दुनिया में चौथी सबसे बड़ी संख्या में टीकाकरण किया लेकिन टीकाकरण की दर काफी कम है

टीकाकरण दर*

प्रति 100 व्यक्ति



*24 फरवरी तक



स्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और ourworldindata.org

ग्राफिक: असित राय; इलस्ट्रेशन: तन्मय चक्रवर्ती

लक्षित किया था. 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने में 34 दिन लगे. निजी क्षेत्र का मानना है कि वह इस काम को बहुत तेजी से कर सकता है. विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के अनुसार, 400 रुपये की प्रति खुराक की लागत से निजी क्षेत्र दो महीने में 50 करोड़ लोगों को टीका लगाने की क्षमता रखता है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर कहते हैं, “निजी क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत आबादी को कवर करता है. यह पोलियो समेत ज्यादातर टीकाकरण अभियानों में शामिल रहा है तो कोविड के खिलाफ आखिर क्यों नहीं?”

इस बात की संभावना कम ही है कि सरकार टीकों की खरीद और वितरण पर अपना नियंत्रण छोड़ेगी. ‘लागत’, शायद इसकी प्रमुख वजहों में से एक है. नाम न छापने की शर्त पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी कहते हैं, “क्या आप भूल गई कि महामारी के दौरान क्या हुआ था? कोविड मरीजों को निजी अस्पतालों में 11-15 लाख रुपये के बिल मिल रहे थे और कुछ ने कोविड परीक्षणों के निर्धारित मूल्य से भी अधिक वसूला था और मरीजों के अंतिम बिल में परिवहन और पीपीई लागत भी जोड़ दी थी.”

सरकार के लिए कुछ दूसरी चिंताओं में नकली टीके और दोषपूर्ण तरीके से टीकाकरण का जोखिम भी शामिल है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं, “रातोंरात रेमडेसिविर और अन्य कोविड दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई. हम नहीं चाहते कि वैक्सीन के साथ भी ऐसा हो.” स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं, “केंद्र निजी क्षेत्र की क्षमता वृद्धि भूमिका को पहचानता है और उसका उपयोग करता रहा है. अगले कुछ दिनों में टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज को बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों को बड़ी संख्या में उपयोग किया जाएगा.”

अब तक भारत में टीकों के कारण मौत की कोई सूचना नहीं मिली है और टीकाकरण के ‘प्रतिकूल प्रभाव’ मसलन, जीवन के लिए खतरा बन सकने वाले एलर्जिक रिएक्शन की दर 0.5 प्रतिशत से कम रही है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के कोचिंग विंग की ओर से 5,396 हेल्थकेयर वर्कर्स के एक ऑनलाइन ऑब्जर्वेशनल स्टडी से पता चलता है कि उम्र के साथ टीके के बाद के दुष्प्रभावों की संभावना कम हो गई. टीका लेने वालों में से लगभग 80 प्रतिशत ने कहा कि वे अगले दिन तक बिल्कुल ठीक थे; 66 प्रतिशत ने कम से कम एक साइड-इफेक्ट की सूचना दी जिनमें इंजेक्शन लेने वाली जगह पर सूजन, थकान के बाद बुखार, सिरदर्द सबसे आम शिकायत थी. डब्ल्यूएचओ 65 साल से ऊपर के लोगों को कोविशील्ड लगाने की सिफारिश करता है.

नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉ. वी.के. पॉल कहते हैं, “नए टीके विकसित किए जा रहे हैं. मौजूदा दो टीकों ने कोविड के प्रति प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने में मदद की है.” भले ही कोविशील्ड वैक्सीन, कोविड के दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट में कोविड के हल्के या मध्यम लक्षणों को रोकने में प्रभावी नहीं रहा है, लेकिन इसने गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई है. एम्स-दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, “किसी भी दवा या टीके से एलर्जी हो सकती है. लेकिन अब तक कोविड के टीके के बहुत ही कम गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं. यहां तक कि पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त लोग भी वैक्सीन ले सकते हैं. वास्तव में जो सबसे अधिक जोखिम में हैं उन्हें आगे आना चाहिए और इसे लेना चाहिए. लेकिन टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.” ■

आरक्षण की बढ़ती मांग

गुजरात के अहमदाबाद में पटेल
आरक्षण रैली



शैलेश रावल

राष्ट्र | रोहिणी कमिशन

आरक्षण की चुनावी बिसात

ओबीसी को कई उपश्रेणियों में बांटकर 27 फीसद आरक्षण में वंचित अति पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले आने की संभावना

सुजीत ठाकुर

पचास और साठ के दशक में सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का नारा “पिछड़ा पाए सौ में साठ” सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नए फलक पर पहुंचा रहा था. लेकिन आज पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग के सियासी फलक से गुजरते हुए शायद चुनावी सरगर्मी का मुद्दा ज्यादा बनकर रह गया है. इसीलिए, लोहियावादी राजनीति से निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 फीसद ओबीसी आरक्षण में अति पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए बिहार आरक्षण फॉर्मूले की तर्ज पर केंद्रीय आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग करते हैं, तो फौरी सियासी गणित का एहसास दे जाते हैं. लेकिन उनके फौरन बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य तथा पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान नई सियासी दांव का संकेत देता है.

दरअसल, नीतीश ने यह राग तब छोड़ा है जब ओबीसी में

शामिल गैर-प्रभावशाली जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने की सिफारिश के लिए गठित रोहिणी आयोग का कार्यकाल दसवीं बार 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया. केंद्र ने 2 अक्टूबर 2017 को पिछड़ा समुदाय से आने वाली दिल्ली हाइकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी के नेतृत्व में चार सदस्यीय आयोग गठित किया. आयोग यह देखेगा कि ओबीसी की लिस्ट में शामिल कौन-सी जातियां आरक्षण का पूरा लाभ उठाने से वंचित रह गई हैं.

इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार के बयान के फौरन बाद सुशील मोदी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की आरक्षण नीति में पिछड़ा-अति-पिछड़ा वर्गीकरण लागू करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया. सभी दल इस वर्गीकरण के लिए मांग करते रहे, लेकिन आयोग बनाने की पहल पीएम मोदी ने ही की.” यह बयान महज नीतीश कुमार के आरक्षण के मुद्दे को छेड़ने का सियासी जवाब ही नहीं है, बल्कि उन दलों को भी संकेत है, जो आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे दिखते हैं. इसकी अहमियत इसलिए भी है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है.

हालांकि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जाटवों के अलावा अन्य दलित जातियों और कुछ अति पिछड़ी जातियों को साधकर बड़ी चुनावी सफलता हासिल की थी. लेकिन चुनाव के पहले रोहिणी आयोग की रपट आती है तो भाजपा को यादवों

आयोग के प्रमुख काम

- 1 केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी जातियों को मिले आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की समीक्षा
- 2 ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया, मानदंड और मानक तय करना
- 3 ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों की पहचान कर उन्हें उप-श्रेणियों में डालना



चंद्रिका कुमारी

आरक्षण का सफरनामा

1 महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्गों को राज्य प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण देना शुरू किया था. भारत में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला यह पहला सरकारी आदेश था

2 1901 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारी आदेश के तहत कमजोर वर्गों के लिए 44 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई

3 1942 में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सरकारी सेवा और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई. आजादी के बाद एससी और एसटी के लिए क्रमशः 15 और 7.5 फीसद आरक्षण लागू

4 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, जिसने पिछड़ी जातियों का चार मानकों (सामाजिक सोपान, शैक्षणिक आधार, सरकारी नौकरियां और कारोबार) पर वर्गीकरण किया

5 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरिलाल आयोग का गठन किया. आयोग ने 1975 में रिपोर्ट दी, जिसमें पिछड़े वर्ग को दो भागों में बांटा गया. अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में 128 जातियां और अति पिछड़े वर्ग यानी एमबीसी में 93 जातियां रखी गईं. वे 1977 में जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री बने तो 1978 में इस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में 8 प्रतिशत ओबीसी, 12 प्रतिशत एमबीसी, 14 प्रतिशत एससी, 10 प्रतिशत एसटी, 3 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया

6 ओबीसी आरक्षण के लिए 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू की

के अलावा पिछड़ों की लामबंदी में मदद मिल सकती है. केंद्र सरकार मानकर चल रही है कि रोहिणी आयोग अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगा. उसके बाद सरकार आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार कानूनी प्रावधान कर उपश्रेणियों के लिए तय कोटे के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकती है. उत्तर प्रदेश में गैर-यादव ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ न मिलने की शिकायत करते आए हैं. भाजपा मीडिया विभाग के प्रमुख अनिल बलूनी कहते हैं, “यह मुद्दा दूसरे दलों के लिए सियासी है लेकिन भाजपा के लिए यह सबको न्याय दिलाने के लिए है. आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी.”

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारी अनौपचारिक रूप से कहते हैं कि, “इस समय देश में केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी)

के लिए 27 फीसदी कोटा आरक्षित है. लेकिन लंबे समय से देश के विभिन्न राज्यों से यह शिकायत होती रही है कि आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिल रहा है और लाभ का बड़ा हिस्सा ओबीसी के प्रभावशाली जातियों के खाते में ही चला जाता है.”

सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने एक फॉर्मला तैयार किया है, ताकि ओबीसी लिस्ट में शामिल जाति समूहों को चार-उपश्रेणियों और एक विशेष उपश्रेणी में डाला जा सके. आयोग मार्च महीने के पहले हफ्ते से अगले ओबीसी कोटे को चार उप-श्रेणियों और एक विशेष श्रेणी में विभाजित करने के तरीकों और वर्गीकरण को लेकर चर्चा करेगा. जद (यू) नेता के.सी. त्यागी कहते हैं, “मेरी जानकारी के मुताबिक आयोग केंद्रीय सूची में शामिल कुल 2,633 ओबीसी जातियों को चार उप-श्रेणियों में डालने पर विचार कर रहा है.” सूत्रों की मानें तो ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में श्रेणी एक की जातियों को 2 फीसद, श्रेणी दो की जातियों को 6 फीसद, श्रेणी तीन की जातियों को 9 फीसद और श्रेणी चार की जातियों को 10 फीसद आरक्षण देने पर राज्यों से सलाह और सहमति ली जाएगी.

अनौपचारिक जानकारी यह भी है कि पहली उप-श्रेणी में 1,674 जाति समूहों को रखने का विचार है. इस श्रेणी में वे जातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है. दूसरी उप-श्रेणी में 534 जाति समूहों को शामिल किया जा सकता है. तीसरी उपश्रेणी में 328 और चौथी में 97 जातियों को शामिल किया जा सकता है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में बताया, “एक आकलन के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ 10 पिछड़ी जातियां आरक्षण लाभ का एक-चौथाई हिस्सा ले जाती हैं. ओबीसी के 37 जाति समूह ऐसे हैं जो आरक्षण लाभ का दो-तिहाई फायदा ले जाते हैं. जबकि तीन-चौथाई आरक्षण का लाभ ओबीसी की 100 जाति समूहों को मिल पाता है. अर्थात् केंद्रीय सूची में शामिल कुल 2,633 जातियों में बाकी की 2,486 जातियों को 27 फीसद आरक्षण का सिर्फ पांचवां हिस्सा ही मिल पाता है.” हालांकि आयोग के सामने असली चुनौती यह है कि लगभग 1,000 ऐसी जातियों को आरक्षण लाभ के नेट में लाना है, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है. आयोग वर्गीकरण को लेकर मार्च महीने के पहले हफ्ते से राज्यों से विचार-विमर्श शुरू करने जा रहा है. राजद नेता मनोज झा कहते हैं, “यह मुद्दा संवेदनशील है. आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पहले रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तो आ जाए.” जद (यू) नेता के.सी. त्यागी कहते हैं, “आयोग का गठन अच्छी बात है लेकिन सभी को समुचित न्याय मिले इसके लिए जाति जनगणना भी जरूरी है और यह होनी ही चाहिए.”

बहरहाल, आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुच्चेरी, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पहले से ही उपश्रेणियां हैं इसलिए आयोग को राज्यों की उपश्रेणियों से अपनी श्रेणी का मिलान करना पड़ेगा. यह बेहद पेचीदा और लंबा समय लेने वाला काम है. किसी राज्य के किसी खास जाति समूह को उपश्रेणियों में शामिल करने में कोई तकनीकी दिक्कत होगी तो उसे विशेष उपश्रेणी में लाने का विचार किया जा सकता है. फिलहाल, रोहिणी आयोग सियासी उबाल भले न पैदा कर रहा हो, रिपोर्ट आने के बाद जातियों का सियासी समीकरण फिर करवट ले सकता है, जिसकी दस्तक 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल सकती है. भले सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हों पर चुनावी बिसात तो तैयार हो ही सकती है. ■

सियासी राह साधने का बजट

चुनाव के तैयारी वर्ष में योगी सरकार ने विभिन्न तबकों की नाराजगी का ध्यान रखते हुए सबके लिए खोली थैली. लेकिन अब क्या यह कारगर होगा?

आशीष मिश्र

ल

सुनहरे ख्वाब

बजट पेश करने जाते वित्त
मंत्री सुरेश खन्ना के साथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ



खनऊ में कृषि विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रमेश विश्वकर्मा 40,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं. कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी खजाने पर पड़े वित्तीय भार के कारण पिछले साल प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) फ्रीज कर दिए थे. जब यह रोक लगी उस समय कर्मचारी 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता पा रहे थे. इस हिसाब से रमेश को पिछले वर्ष जुलाई के महीने में करीब 7,000 रुपए डीए के रूप में मिलने थे. रमेश कहते हैं, “अपेक्षाकृत कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बहुत काम आता है. इससे कई सारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं. वह न मिलने से घर के बजट पर फर्क पड़ा है.”

यूपी के करीब 18 लाख कर्मचारी और 10 लाख पेंशनर रमेश जैसी ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2020-21 में महंगाई भत्ते के लिए बजट में 12.9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत फ्रीज होने से सरकार का खर्च 7,200 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है. इस तरह एक वित्तीय वर्ष में करीब 5,600 करोड़ रुपए की बचत हुई. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को पेश किए गए बजट में महंगाई भत्ते के मद में करीब 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 23.85 प्रतिशत ज्यादा

है. अनुमान है कि यह प्रावधान महंगाई भत्ते की दो किस्त के भुगतान के लिए है. ऐसा होने पर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे. “यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन” के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा कहते हैं, “कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से शुरू होने पर यूपी में भाजपा की सरकार को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है.”

योगी आदित्यनाथ यूपी में भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार ने लगातार पांच साल बजट पेश किया है. वित्त मंत्री खन्ना ने 22 फरवरी को यूपी का अब तक का सबसे बड़ा 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जो पिछले बजट की तुलना में 7.30 प्रतिशत ज्यादा है. मेरठ कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मनोज सिवाच कहते हैं, “यह बजट ऐसे समय में आया है जब प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है. इस बजट के जरिए सरकार को अपने संसाधन जुटाकर चुनावी वर्ष में महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने की चुनौती भी है.”

महामारी का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ा है. अगले वित्त वर्ष में केंद्र से राज्य को मिलने वाले सहायता अनुदान में भी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी होने जा रही है. इसे पूरा करने को प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष के मुकाबले कर राजस्व में 20,000 करोड़ रुपए की वृद्धि का लक्ष्य तय कर रखा है. यूपी में वित्त विभाग के एक अधिकारी बताते हैं, “महामारी की कठिन परिस्थिति के बीच विकास

योजनाओं के लिए पैसे का बंदोबस्त करने को सरकार ने ज्यादा कर्ज लेने का फॉर्मूला अपनाया है. इसके जरिए सरकार पूंजीगत मद में एक लाख करोड़ रु. से ज्यादा का बंदोबस्त करेगी.”

पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन ने योगी आदित्यनाथ के सामने चुनावी वर्ष में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. किसान आंदोलन के जरिए गरमाई राजनीति को योगी सरकार ने “आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना” शुरू कर इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसके अलावा किसानों को लुभाने के लिए प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के वास्ते पहली बार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रोफेसर सिवाच कहते हैं, “फसलों की लागत कम करने के लिए मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने को 700 करोड़ रुपए का बंदोबस्त योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है.”

यूपी में वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को भी पूरा करने के लिए फोकस किया गया है. मध्य गंगा नहर, राजघाट नहर, सरयू नहर, पूर्वी गंगा नहर और केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 3,098 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है. यूपी के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कहते हैं, “पिछले तीन वर्षों में यूपी में 11 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं. इनसे न केवल 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई बल्कि ढाई लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित

सबके लिए खुला खजाना

किसान आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, फसली ऋण के अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए. नहरों और राजकीय नलकूपों से मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए. 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य.

महिला महिला सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए अलग-अलग 300 करोड़ रुपए का प्रावधान. पांच शहरों में सेफ सिटी योजना में 309.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था. कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए, परित्यक्त महिलाओं के अनुदान के लिए 10.04 करोड़ रुपए. निराश्रित विधवा महिलाओं के पेंशन के लिए 1,431.77 करोड़ रुपए का प्रावधान.

श्रमिक यूपी में विभिन्न प्रदेशों से लौटे श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए. असंगठित क्षेत्र के कामगारों, श्रमिक परिवारों और पल्लेदारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था.

युवा अभ्युदय योजना के छात्रों को मुफ्त टैबलेट. गांव में स्टेडियम, ओपन जिम और मंगल दलों के लिए 53.55 करोड़ रुपए. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए. 12 जिलों में मॉडल करियर सेंटर बनाने की घोषणा. मेरठ में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए. राज्य के 26 जिलों में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे.

एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1,107 करोड़ रुपए. गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7689 करोड़ रुपए का प्रावधान. यूपी में बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे समेत सभी चार एक्सप्रेसवे के लिए कुल 11,148 करोड़ रुपए का प्रावधान. विश्व बैंक की सहायता से यूपी कोर रोड परियोजना में मार्ग निर्माण के लिए 440 करोड़.

स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जांच के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,076 करोड़ रुपए. 13 जिलों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1,950 करोड़ रुपए. ब्लॉक स्तर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए 77 करोड़ रुपए. 12 जिलों में खाद्य और औषधि प्रयोगशाला के लिए 77 करोड़ रुपए. केजीएमयू, लखनऊ में वायरोलाजी इंस्टीट्यूट.

शिक्षा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान. समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए. 110 करोड़ रुपए निःशुल्क स्कूल बैग के लिए. निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए. हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने के लिए 90 करोड़ रुपए.

उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए 480 करोड़ रुपए. एक जनपद एक उत्पाद के लिए 250 करोड़ रुपए. 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए. परंपरागत कारीगरों के उत्थान और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए 30 करोड़ रुपए.

पर्यटन रामजन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक सड़क निर्माण के लिए, अयोध्या में पर्यटन और सर्वांगीण विकास के लिए 240 करोड़ रुपए. सीएम पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए. विंध्याचल, नैमिषारण्य और चित्रकूट में पर्यटन विकास को 50 करोड़ रुपए. अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए.

मेट्रो इसी वर्ष शुरू होने वाली कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 597 करोड़. आगरा के लिए 478 करोड़. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ में प्रस्तावित रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लिए 1,326 करोड़ रुपए. वाराणसी व गोरखपुर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड़ रुपए.

हुए हैं.” किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, पैदावार बढ़ाने के लिए नवीन तकनीक और निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, बिक्री के लिए बाजार तैयार करना और ब्लॉक स्तर पर “फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन” (एफपीओ) की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान” (कुसुम) के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने का निर्णय लिया गया है. किसान आंदोलन के बीच गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य न बढ़ाए जाने से पैदा हुई किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सहकारी चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. रुहेलखंड के किसान नेता रवि नागर कहते हैं, “बजट में किसान की आय बढ़ाने से ज्यादा फोकस कर्ज देने पर रखा गया है. कर्ज देकर किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है.” चुनावी वर्ष में सरकार ने पंचायतों के लिए भी खजाना खोला है. अगले वित्त वर्ष में “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” चलाने के लिए 653 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है.

म हमारी के दौरान यूपी में करीब 32 लाख श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लौटे थे. एक सरकारी अनुमान के मुताबिक, लॉकडाउन हटने के बाद इनमें से करीब आधे मजदूर दूसरे प्रदेशों को लौट चुके हैं. 15 लाख से अधिक मजदूर अभी भी यूपी के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं. ऐसे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बजट में “मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना” लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसी तरह पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए “मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

योगी सरकार ने युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए भी बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी है. (देखें ग्राफिक्स) अभ्युदय छात्रों को टैबलेट देने की योजना ने चर्चा बटोरी है. यूपी योजना आयोग के पूर्व सदस्य और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधीर पंवार कहते हैं, “लाकडाउन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहने से जो गरीब छात्र टैबलेट/लैपटॉप नहीं खरीद सकते उन्हें इससे लाभ होगा पर भाजपा को कोई चुनावी लाभ होगा इसमें अभी संशय है क्योंकि छात्र भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में शामिल टैबलेट और मुफ्त डेटा मिलने का चार साल से इंतजार कर रहे हैं.”

पहली बार पेपरलेस बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री खन्ना ने इस दौरान पांच शेर पढ़े. आखिरी शेर 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गौरतलब है: *प्यार का रास्ता ढूंढेगी यह पवित्र सभा, खूब बरसेगी इस जमीन पर रहमत की घटा, मोहतरिम सदर हों जिस बज्ज के खुद ‘योगी’, चारों तरफ फैलेगी विकास की सुहानी घटा.* ■

दीर्घकालिक योजनाएं

राज्य में बदले सत्ता समीकरण के बावजूद पहले बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन की छाप साफ दिखाई देती है

अमिताभ श्रीवास्तव



शुरुआत

उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी को बजट पेश किया

एनआर

म

हमारी के दौरान विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जद (यू) एनडीए सरकार की कनिष्ठ सहयोगी हो गई। इसके बावजूद भाजपा के वित्त मंत्री तारकिशोर कुमार ने 22 फरवरी को जो पूर्ण बजट पेश किया, उसमें नीतीश कुमार की छाप साफ दिखती है। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, युवाओं की कौशल वृद्धि और रोजगार सृजन के उपायों पर जोर दिया गया है। हालांकि कई योजनाओं के नतीजे दिखने में काफी वक्त लग सकता है।

कोविड महामारी की वजह से 2020-21 के बजट की कई प्राथमिकताएं और योजनाएं बदल गईं या फिर परवान नहीं चढ़ सकीं। बड़े पैमाने पर मजदूरों की वापसी से रोजगार की समस्या दिखाई देने लगी। स्वास्थ्य ढांचे के सामने चुनौतियां खड़ी हो गईं। इसी को ध्यान में रखकर बजट में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

प्रसाद का वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का 2.18 लाख करोड़ रु. का बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, यह पिछले साल तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पेश किए गए 2.11 लाख करोड़ रु. के बजट से 6,541.21 करोड़ रु. अधिक का है। इस बजट की एक विशेषता यह रही कि कोई नया कर नहीं लगाया गया।

सबसे अधिक आवंटन शिक्षा के लिए 38,035 करोड़ रु. रहा। उसके बाद ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ रु., सड़कों के लिए 15,227 करोड़ रु., स्वास्थ्य के लिए 13,264 करोड़ रु. और ऊर्जा के लिए 8,560 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। शिक्षा के बजट के तहत अन्य योजनाओं के अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए सभी जिलों में कौशल केंद्र खोले जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सके और राज्य

से बाहर उनके पलायन को कम किया जा सके। सरकार ने एक नया युवा कौशल और उद्यमिता विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशासनिक विंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक शामिल होंगे और पाठ्यक्रम में उद्यमिता भी शामिल होगी। महामारी के अनुभवों को देखते हुए स्वास्थ्य बजट को पिछले साल के मुकाबले बढ़ा दिया गया है और इसके तहत न केवल

बजट में युवाओं के लिए क्या है

- इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स के लिए तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे
- 28 जिलों में 12 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
- 5 जिलों में फार्मसी कॉलेज खोले जाएंगे
- युवाओं के कौशल विकास के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे
- आइटीआई और पॉलिटेक्निक सेंटरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा
- उच्चस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र (हाइ लेवल सेंटर फॉर एक्सीलेंस) बनाए जाएंगे
- राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी
- 20 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे

महिलाओं के लिए

- महिलाओं को उद्यम के लिए पांच लाख रु. तक का अनुदान, बिना किसी ब्याज के पांच लाख तक का ऋण भी मिलेगा। इसके लिए 200 करोड़ रु. का प्रावधान
- सरकारी नौकरियों में 35 फीसद आरक्षण, पुलिस थानों समेत जिला कार्यालयों में आरक्षण के अनुपात में तैनाती होगी
- अविवाहित महिलाओं को इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने पर 25,000 रुपए, स्नातक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

- पीएम स्वच्छता अभियान पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सभी गांव स्वच्छ होंगे
- 450 करोड़ रुपए खर्च करके जल जमाव की परेशानी को दूर किया जाएगा
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे
- गांवों में बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे

सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएंगे और 14 नए मेडिकल खोले जाएंगे बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारी जाएगी।

प्रसाद ने अगले पांच वर्षों में हर खेत को पानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया और बजट में इसके लिए 550 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बजट में नीतीश के सात निश्चयों (भाग -2) के लिए अलग से 4,671 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। अगले पांच वर्षों में निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में 20 लाख नौकरियों के सृजन के बारे में बजट की घोषणा युवाओं की हताशा को दूर कर सकती है, तो उद्यमी बनने की इच्छुक महिलाओं को प्रस्तावित वित्तीय मदद (देखें बॉक्स) यहां महिला सशक्तिकरण को अगले स्तर तक ले जा सकती है।

लेकिन ऐसे बजट के सामने लक्ष्यों को पूरा करने की प्रशासनिक क्षमता चुनौती होती है। एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं, "सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपायों को फलीभूत करने के लिए समाज की पहल समेत कई कारक जिम्मेदार होंगे। मिसाल के तौर पर महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। इसके लिए महिलाओं और उनके परिवार वालों को आगे बढ़कर उद्यम शुरू करना होगा। फिर उसकी सफलता बाजार अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होगी। हालांकि इस पहल से महत्वाकांक्षी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन पांच लाख रु. का अनुदान हासिल करने के लिए फर्जी आवेदनों की बाढ़ आ सकती है।"

इस बजट की खास बात यह है कि सरकार ने पहले की तुलना में वेतन और पेंशन खर्च को घटाकर 70 हजार करोड़ रु. से 60 हजार करोड़ रु. कर दिया है। सरकार का खर्च कम होने से विकास कार्यों के लिए धन मिलेगा। ■

गहलोत की सौगात

रोहित परिहार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे में चार सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उप-चुनावों को जीतने की हर जुगत में लगे हैं। ये सीटें वहां के विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। इनमें से कांग्रेस के पास सहाड़ा, वल्लभनगर और सुजानगढ़ सीटें थीं और राजसमंद भाजपा के पास। इसलिए अधिक दबाव गहलोत और उनके खुद के चुने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा पर है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें और कम-से-कम अपनी तीनों सीटें बरकरार रखें। यही वजह है कि गहलोत ने 158 करोड़ रुपए की लागत की 178 योजनाओं की घोषणा इन चार विधानसभा सीटों के लिए की है।

पिछले साल जून में तब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद होने वाले ये पहले उप-चुनाव हैं। उसके पहले, 2019 में गहलोत ने मंडावा की एक सीट भाजपा से छीन ली थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो तब भाजपा की सहयोगी थी, को खींचकर में कड़ी टक्कर दी थी।

गहलोत इस जंग को पायलट के बगैर ही जीतना चाहते हैं और वह इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने पायलट की खुद को सामने रखने की उस कोशिश को भी तब खारिज कर दिया जब राहुल गांधी के हालिया दौर के वक्त

उनके समर्थक लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे थे और राहुल गांधी को असुविधा हुई थी। राहुल ने भी बगावत के बाद से पायलट से दूरी बना रखी है। पायलट किसानों की रैलियां आयोजित कर रहे हैं, जिनमें से कुछ में अच्छी-खासी भीड़ भी जुटी है। उनकी पूरी कोशिश गहलोत पर दबाव बनाने की है ताकि उनके समर्थकों को कुछ मलाईदार कुर्सीयां हासिल हो सकें। उनकी एक रणनीति यह हो सकती है कि उप-चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उनकी हार की दशा में, गहलोत रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएं और पायलट दावा कर सकें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव हार सकती है।

राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अजय माकन गहलोत तथा पायलट के बीच सुलह कराने में जुटे हैं। माकन ने गहलोत को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) वापस लेने के लिए मना लिया। पार्टी के मुख्य व्हिप महेश जोशी ने स्पीकर सी.पी. जोशी के पायलट और 17 बागी विधायकों को दिए नोटिस पर राजस्थान हाइकोर्ट के स्थान के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल किया है। नोटिस में स्पीकर ने इन लोगों से कारण पूछा है कि उन्हें क्यों न

निलंबित कर दिया जाए। अब कांग्रेस में कई लोग पूछ रहे हैं: क्या माकन पायलट के आगे झुक गए हैं। माकन कहते हैं कि वे एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करने पर काम कर रहे हैं और उन्होंने पायलट को भी इसके लिए राजी किया कि वे अपनी रैलियों में गहलोत की तस्वीर भी लगाएं। साफ है कि माकन असावधानी नहीं बरतना चाहते हैं। पर गहलोत जोखिम उठाना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन उप-चुनाव के सीटों वाले इलाके में पायलट का असर सीमित है।

अभी कांग्रेस के पास 103 विधायक हैं। इनमें से 6 बसपा के हैं जिनका कांग्रेस में विलय अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। विधानसभा की मौजूदा संख्या अभी 196 है। तीन सीटों पर जीत से गहलोत को 106 सीटें

गहलोत के पास अधिकतर निर्दलीय और अन्य का समर्थन है। वे उप-चुनाव की चार सीटें हार भी जाते हैं तो उनकी सरकार को अभी कोई खतरा नहीं

मिल जाएंगी और एक अतिरिक्त सीट बोनस सरीखी होगी। गहलोत के पास अधिकतर निर्दलीय और अन्य का समर्थन भी है और अगर वह सभी चार सीटें हार भी जाते हैं तो उनकी सरकार को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। कभी पायलट के पास 22 विधायक थे, पर अभी उनके पास 15 समर्थक विधायक हैं। वे अपना राग दोबारा छेड़ सकते हैं।

आंतरिक कलह के कारण, जिसे भाजपा ने पैदा किया, कांग्रेस ने पुटुच्चेरी की सत्ता खो दी है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि गहलोत कितने दिन टिकेंगे। राजस्थान भाजपा के पास अपनी समस्याएं हैं। भाजपा के 20 विधायकों का आरोप है कि राजे समर्थक होने के कारण मौजूदा प्रदेश नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में अगर भाजपा गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है तो उसके खुद के सत्ता संघर्ष में फंसने का खतरा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों ने कुछ फायदों के एवज में भाजपा को समर्थन का वादा किया है, इसलिए भाजपा यह जोखिम उठा सकती है। ऐसे में राजस्थान फिर से डगमग सियासत के दौर में लौट सकता है। ■



चुनावी तैयारी
उप-चुनावों से पहले गहलोत ने सौगातों की झाड़ी लगा दी है

जेब से जुड़ा ज्वालंत मुद्दा

पेट्रोल-डीजल की छलांग लगाती कीमतों से महंगाई बढ़ने और लोगों के खर्च में कटौती करने की आशंका है, लिहाजा, महामारी से देश की जर्जर अर्थव्यवस्था की बहाली होगी मुश्किल

एम.जी. अरुण और श्वेता पुंज

महामारी कोविड-19 पहले ही लाखों जिंदगियों और करोड़ों रोजगार को तबाह कर चुकी है, अब एक नई मुसीबत तेल की बढ़ती कीमतों की शक्ल में आ गई है. पिछले साल भर में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 24 फीसद और डीजल की कीमतें 23 फीसद बढ़ गई. 22 फरवरी को राजधानी में पेट्रोल 97 रु. लीटर और डीजल 88.06 रु. लीटर की अब तक की सबसे ऊंची कीमत जा बैठा. राजस्थान में गंगानगर मध्य प्रदेश में अनूपपुर जैसे कुछ शहरों में पेट्रोल 100 रु. के पार चला गया है. तेल की ये ऊंची कीमतें सिर्फ लोगों की जेब ही में छेद नहीं कर रही हैं, बल्कि ढुलाई का खर्च बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खतरा भी पैदा कर रही हैं. ये महंगाई को काबू में करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती से रोक सकती हैं, जिससे महामारी के बाद देश में अर्थव्यवस्था की बहाली की कोशिशों को धक्का लग सकता है. समुदाय आधारित सोशल मीडिया नेटवर्क लोकल सर्किल्स के देश भर में 291 जिलों में 22,000 लोगों के एक ताजा सर्वेक्षण में पता चला कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लोग फिर खर्चों में कटौती करने लगे हैं.

तेल की कीमतों के छलांग लगाने की दो वजहें हैं. एक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है. भारतीय रिफाइनरियों में आयात होने वाले कच्चे माल ब्रेंट क्रूड की कीमत 22 फरवरी को करीब 63 डॉलर प्रति बैरल (तकरीबन 4,560 रु.) थी. यह पिछले मार्च की क्रूड की कीमतों के मुकाबले काफी ऊंची थी, जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा. तब कच्चे तेल की कीमतें जनवरी 2020 में 70 डॉलर प्रति बैरल (5,065 रु.) से गिरकर 31 मार्च को 14 डॉलर प्रति बैरल (1,447 रु.) पर आ गई. मई में कीमतें 20 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ीं और तब से मोटे तौर

पर चढ़ती ही गई. कोविड-19 के वैक्सीन का आविष्कार और लॉकडाउन के बाद तेल की बढ़ती मांग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें चढ़ने लगीं. फिर, अमेरिका के बाद सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने मांग और आपूर्ति के असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए जनवरी और फरवरी में अपने तेल उत्पादन में हर रोज दस लाख बैरल की कटौती कर दी. आइसीआरए में कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सह-प्रमुख तथा वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ कहते हैं, “दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन के जारी रहने से सऊदी अरब को तेल की मांग पर बड़ा खतरा दिख रहा है.” ओपेक (पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन) देश जनवरी में आपूर्ति में कटौती करने को भी राजी हो गए.

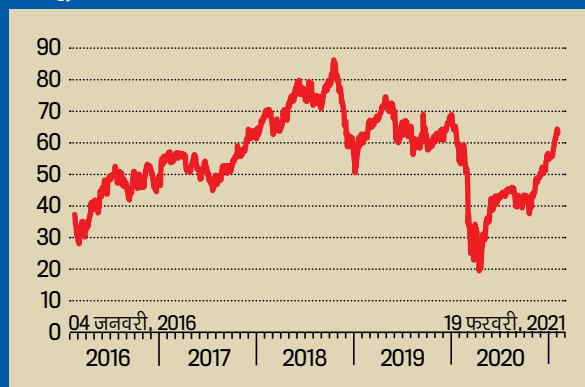
कच्चे तेल का फर्क

देश अपनी जरूरत का 80 फीसद से ज्यादा तेल का आयात करता है. इसलिए कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर देश में तेल की कीमतों पर पड़ता है. 2019-20 में देश में 27 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात 120 अरब डॉलर (8.76 लाख करोड़ रु.) में किया गया. लॉकडाउन से उभरती अर्थव्यवस्था में तेल की मांग बढ़ी तो आयात ज्यादा करना पड़ा. दिसंबर में तेल आयात पिछले महीने के मुकाबले 29 फीसद और साल भर पहले के मुकाबले करीब 11.6 फीसद ज्यादा किया गया.

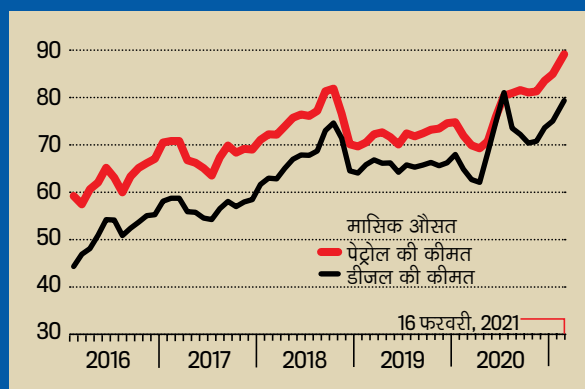
देश में 2010 में जब से पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया गया है, कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के हिसाब से ऊपर-नीचे होने लगीं (2014 में डीजल की कीमतों को भी नियंत्रण मुक्त करने का यही असर हुआ). देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अरब की खाड़ी में तेल की कीमतों के बेंचमार्क के 15 दिन के औसत पर तय होती हैं. पिछले साल 1 अप्रैल और 10 दिसंबर के बीच पेट्रोल की कीमतें 67 बार

चिंता का सबब

ब्रेंट क्रूड के दाम (डॉलर प्रति बैरल)



दिल्ली में ईंधन के दाम (रुपए प्रति लीटर)

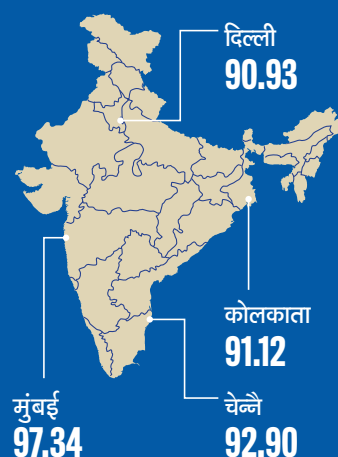


दिल्ली में दाम का गणित रुपए/लीटर

तारीख तक	पेट्रोल	डीजल
● मार्च 16, 2020	14.8	9.2
● फरवरी 16, 2021	20.6	11.7
वैट (*डीलर कमिशन पर वैट सहित)	3.5	2.5
औसत डीलर कमिशन	23	18.8
एक्साइज इयूटी	28.3	31.8
डीलर को इस मूल्य पर मिला (बेस प्राइस+दुलाई)	32.1	33.7
खुदरा कीमत	69.6	62.3
	89.3	79.7

भारतीय महानगरों में पेट्रोल की कीमत

(23 फरवरी 2021; रु/प्रति लीटर)



27

करोड़ टन

कच्चे तेल का आयात किया भारत ने 2019-20 के दौरान

120

अरब डॉलर

कीमत का कच्चा तेल आयात किया 2019-20 में

2.1 लाख करोड़ रु.

राजस्व अर्जित किया केंद्र और राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान अप्रैल से सितंबर के बीच पेट्रो पदार्थों पर एक्साइज इयूटी और वैट लगाकर

4.24 लाख करोड़ रु.

राजस्व अर्जित किया केंद्र और राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पेट्रो पदार्थों पर एक्साइज इयूटी और वैट लगाकर

बढ़ीं। इस बढ़ोतरी से तेल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं और सुर्खियां बनीं। 21 फरवरी को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, “तेल की कीमतों में वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल उत्पादन घटा दिया गया है—(तेल उत्पादक) देश अधिक मुनाफे के लिए तेल का उत्पादन कम कर रहे हैं। इससे खपत वाले देशों में मुसीबत आ रही है।”

लेकिन तेल की कीमतें चढ़ने के लिए सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें ही जिम्मेदार नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त कर और शुल्क भी उतने ही जिम्मेदार हैं। केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस बताते हैं, “कच्चे तेल की कीमतें तो 8 फरवरी, 2021 को 60 डॉलर प्रति बैरल के पार गईं।” यही नहीं, पिछले साल 20-24 जनवरी के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें 60-65 डॉलर प्रति बैरल के बीच थीं तो दिल्ली में पेट्रोल 73-74 रु. लीटर और डीजल 67-68 रु. लीटर ही था। इसलिए उनकी दलील है कि कर और शुल्क से बढ़ती कीमतों की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

टैक्स का मामला

पेट्रोल की कीमत में केंद्र का उत्पाद शुल्क सबसे बड़ा घटक है। इस साल 16 फरवरी को भारतीय तेल निगम के कीमत के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल के 89.29 रु. लीटर के दाम में उत्पाद शुल्क 32.90 रु. और राज्य का वैट (मूल्य वर्धित टैक्स) 20.61 रु. यानी कीमत का तकरीबन 60 फीसद था। दिल्ली में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पिछले साल 16 फरवरी को 20 रु. से उछल कर इस साल उसी दिन 32.10 रु. हो गई। वैट 15.30 रु. से बढ़कर 20.60 रु. हो गया।

देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट राजस्थान में और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगता है। पेट्रोल-डीजल से हुई कमाई सरकारों के लिए महामारी में कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिए जरूरी है। मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर की अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और वैट से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई 2.1 लाख करोड़ रु. हुई। 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकारों ने उत्पाद शुल्क और वैट के जरिए 4.24 लाख करोड़ रु. जुटाए। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा 2.23 लाख करोड़ रु. था। 20 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यह (तेल की कीमतों का मसला) काफी अफसोसनाक है...ऐसा मसला है, जिसमें कीमतें घटाए बिना किसी को यकीन नहीं दिलाया जा सकता।” सरकार से ऐसे कुछ संकेत हैं कि तेल को माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने से मदद मिल सकती है। फिर, केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो तेल की कीमतें विपक्ष को केंद्र पर निशाना साधने का औजार थाम देती हैं।

सरकार ऊहापोह में

भाजपा विपक्ष में थी तो वह यूपीए सरकार पर तेल की कीमतें काबू में रखने का दबाव बनाए हुई थी। मई 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो दिल्ली में पेट्रोल 70 रु. और डीजल 57 रु. लीटर था। पेट्रोलियम विश्लेषक तथा भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा बताते हैं कि जब यूपीए

सरकार के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की अंडर-रिकवरी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने रियायती दर पर बिक्री की और सरकार अपने वित्तीय उपायों से घाटे की भरपाई कर रही थी। तनेजा कहते हैं कि मोदी सरकार के तहत पेट्रोल की कीमतें तब भी बढ़ती रहीं, जब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर रही थीं, इससे ओएमसी की अंडर रिकवरी खत्म हो गई।

मौजूदा सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है लेकिन एक पूर्व अफसरशाह का कहना है कि अंडर रिकवरी घटने की बड़ी वजह कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें कम होना है। कच्चे तेल की कम कीमतों ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपने राजस्व की कमी को पूरा करने की गुंजाइश बना दी। उसने तेल की कीमतें घटाकर लोगों का इसका फायदा नहीं दिया।

फिलहाल तेल जीएसटी के दायरे से बाहर है, यह भी एक वजह है कि सरकारें कीमतों से छेड़छाड़ कर पाती हैं।

केंद्र सरकार को लॉकडाउन के दौरान राजस्व की कमी की भरपाई के लिए भी टैक्स बढ़ाना जरूरी था, जब शुरुआती महीनों में सारी आर्थिक गतिविधियां ठप थीं। इसी तरह कुछ राज्य सरकारों ने भी लॉकडाउन के दौरान वैट बढ़ाया क्योंकि तेल से आने वाला राजस्व भी घट गया और केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी भी कम मिली। राज्यों के राजस्व में 85 फीसद विभिन्न करों से जुटाता है, जिसमें जीएसटी सबसे अहम है।

सरकार के सामने अब मुश्किल स्थिति आन पड़ी है—ऊंची कीमतें और ऊंची उत्पाद शुल्क। पूर्व वित्त सचिव एस.सी. गर्ग कहते हैं, “सरकार दुविधा में है और शायद उत्पाद शुल्क घटा दे। अगर (उत्पाद शुल्क) पेट्रोल और डीजल पर 1 रु. भी घटाया जाता है तो राजस्व पर उसका सालाना भार करीब 12,000-13,000 करोड़ रु. है।” फिर, असर दिखने के लिए काफी घटाने की जरूरत है। तनेजा पूछते हैं, “सरकार को पैसे की जरूरत है। अगर अनाज और रसोई गैस (पहले ही सस्ती) है तो पैसा आएगा कहां से?”

जानकारों की सलाह है कि केंद्र उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 5 रु. घटाए और राज्य सरकारों को वैट भी 5 रु. तथा ओएमसी को 3 रु. घटाने को मनाए। गर्ग कहते हैं कि कई विधानसभा चुनाव सिर पर हैं तो केंद्र को एक या दूसरे तरीके से कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी।

भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कीमतों में कटौती से सरकार के हिचकने की कई वजहें हैं। कुछ के मुताबिक, उसका मानना है कि लोगों को कम कीमतों का आदी नहीं होना चाहिए—इससे खपत बढ़ सकती है, जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट राजस्व कमाई का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों से कर उगाही पारदर्शी, कारगर, भरोसेमंद और बिना किसी भ्रष्टाचार के है। मोटे तौर पर सरकारों को पेट्रोलियम पदार्थ, शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से आसानी से मनमाफिक कर मिलता है। सरकारों को इस समय खर्च चलाने और वादे पूरे करने के लिए धन की सख्त जरूरत है।

बहरहाल, तेल की कीमतों में उछाल से सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। लिहाजा, केंद्र और राज्य दोनों के करों में कटौती ही एकमात्र उपाय लगता है। ■

तेल के दाम उछलने का असर

➤ महंगाई बढ़ेगी। थोक मूल्य सूचकांक में पेट्रोल और डीजल का मिलाजुला भार 4.69 फीसद और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.34 फीसद है

➤ ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे फल-सब्जियों, अनाज आदि जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे। परिवहन भी महंगा होगा

➤ ब्याज दर घटाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले पर असर होगा। महंगाई बढ़ने का मतलब ब्याज दरों में कटौती पर एकाएक रोक लग जाएगा

इंडिया टुडे

राज्य की दशा-दिशा असम

राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास का बारीक विश्लेषण. किन मोर्चों पर
उसका उम्दा प्रदर्शन है और कहां पर बेहतरी की गुंजाइश है





राज्य की दशा-दिशा
रिपोर्ट 2021 असम

भविष्य की राह का महा सेतु

प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी राज्य होने के बावजूद सामाजिक-राजनैतिक अस्थिरता के चलते असम अपनी संभावनाओं का पूरा दोहन कर पाने में नाकाम रहा है. इसके बावजूद कई मानकों पर विकास की रफ्तार ने यहां ध्यान खींचा है, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के मोर्चे पर होने वाली तरक्की उल्लेखनीय है



✓ शानदार संपर्क
4.9 किमी लंबा वोणिबील ब्रिज एशिया का दूसरा
सबसे बड़ा रेल-सह-सड़क सेतु है। इसने असम
और अरुणाचल प्रदेश के बीच दूरी खासी कम कर
दी है और इससे भारत-चीन सीमा क्षेत्र में रक्षा
संबंधी साजोसामान ले जाने में भी आसानी होगी

कौशिक डेका

31

सम भारत के उत्तर-पूर्व अंचल का सबसे बड़ा राज्य है। यह 78,438 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला है जहां करीब 3.2 करोड़ लोग रहते हैं। इसे अक्सर लाल नदियों और नीली पहाड़ियों की धरती कहा जाता है, जिसका वास्ता महानद ब्रह्मपुत्र—जिसे असम में 'लोहित' (रक्त की तरह लाल) कहा जाता है—और उसके चारों तरफ नीले आसमान में विलीन होती पहाड़ियों से है। राज्य के वनों, चाय बागान और धान के खेतों की हरियाली मिलकर इसे ऐसी कुदरती खूबसूरती देते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित इस राज्य में दो नदियों, ब्रह्मपुत्र और बराक के चारों ओर फैली दो उर्वर घाटियां असम को जल संसाधन से समृद्ध बना देती हैं। दुनिया भर में यह न केवल एक सींग वाले गैंडे के घर के तौर पर जाना जाता

है बल्कि यूनेस्को के दो विश्व धरोहर स्थल—काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य—यहां हैं।

एक तरफ इतनी प्रचुर प्राकृतिक स्थिरता और शांति थी, तो दूसरी तरफ आजादी के बाद इस राज्य को सामाजिक और राजनैतिक उथल-पुथल से गुजरना पड़ा, जिसने इसकी आर्थिक वृद्धि को भी पटरी से उतार दिया। 1960 के दशक के भाषाई आंदोलन और 1980 के दशक के असम आंदोलन से लेकर 1990 के दशक में चरमपंथी धड़ों की उग्रवादी गतिविधियों तक राज्य का इतिहास हिंसा और खून-खराबे की घटनाओं से भरा पड़ा है। यह भी एक प्रमुख वजह रही कि असम भारत के दक्षिणपूर्व एशियाई दरवाजे के तौर पर अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के बावजूद राज्य में निहित पूर्ण क्षमता और संभावनाओं को साकार नहीं कर पाया। असम 1981 और 2000 के बीच महज 3.3 फीसद की सालाना आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ा, जबकि इस दौर में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 6 फीसद थी। हालांकि चाय और पेट्रोलियम के रूप में असम देश को दो ऐसी चीजें देता है जो तकरीबन हरेक घर की प्रमुख जरूरत हैं, फिर भी जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के लिहाज से असम भारत के राज्यों में 17वें पायदान पर खड़ा है।

बहरहाल, सदी के पलटा खाने के साथ राज्य में जो थोड़ी-बहुत शांति लौटी, उसकी बदौलत हालात बदले और राज्य आर्थिक वृद्धि और

सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के रास्ते पर वापस आया। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून 2019 सरीखे विवादास्पद मुद्दों को लेकर पैदा हुई सामाजिक-टूट-फूट जहां आज भी राज्य के सामाजिक-राजनैतिक माहौल में तारी है, वहीं हाल के वर्षों में असम ने आर्थिक वृद्धि पर बल देने वाले कई कार्यक्रम लागू किए, ताकि राज्य के बारे में अच्छी धारणा बनाकर भारत की मुख्यधारा से इसका भौगोलिक अलगाव कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर, सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने 2018 में विशाल व्यापार सम्मेलन—एडवांटेज असम: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट—का आयोजन किया, जिसमें मुकेश अंबानी सरीखे दिग्गज कारोबारियों ने हिस्सा लिया। राज्य ने उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति तथा असम की औद्योगिक नीति भी लॉन्च की और इसके जरिए निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन और बहुवर्षीय रियायतों की पेशकश की। साथ ही, राज्य की आइटी और पर्यटन नीतियों ने भी क्षेत्र विशेष के विकास पर खासा ध्यान दिया है।

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं, “लोगों के स्वतःस्फूर्त समर्थन की बदौलत और पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर हमारे अथक फोकस के बल पर हम कई सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को कामयाबी के साथ लागू कर पाए हैं।” असम को इस बात का भी बहुत फायदा मिला कि केंद्र सरकार ने राज्य पर बढ़-चढ़कर



“असम की प्रगति लोकतंत्र और सहकारी संघवाद के ढांचे में शासन में जन भागीदारी की बेजोड़ मिसाल है। **हम इस बात के प्रति आश्चर्य हैं कि असम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस तरह से आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहा है**”

सर्बानंद सोनोवाल
मुख्यमंत्री, असम

असम एक उड़ती नजर

क्षेत्रफल

78,438

वर्ग किलोमीटर

आबादी

3.2

करोड़

आबादी का घनत्व

398

व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

जिले

33

साक्षरता दर

73.18

फीसद

स्त्री-पुरुष अनुपात

958

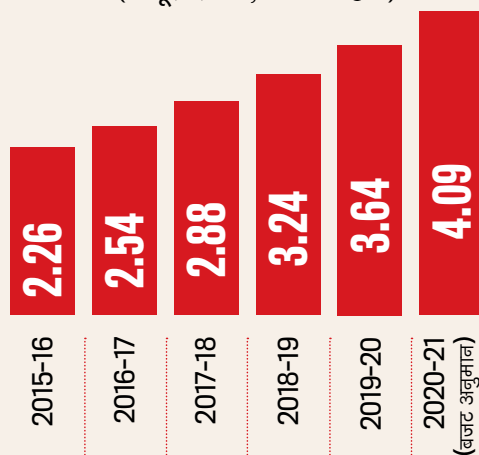
स्त्रियाँ प्रति 1,000
पुरुषों के मुकाबले

ध्यान दिया है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातहत, जिन्होंने उत्तरपूर्वी राज्यों को अक्सर भारत की वृद्धि के नए चालक बताया है। इन कोशिशों के नतीजे भी सामने आए हैं, जो इंडिया टुडे राज्यों की दशा-दिशा सर्वे की रैंकिंग में भी देखे गए, जब असम सबसे ज्यादा सुधरे हुए बड़े राज्यों की फेहरिस्त में पिछले तीन साल शीर्ष पर बना रहा है। सोनोवाल कहते हैं, “असम की तरक्की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजकाज में लोगों की भागीदारी और सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण है। हमें यकीन है कि असम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।”

मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब सड़कों से जोड़ने की बात आती है तो राज्य ने बीते पांच सालों में अहम तरक्की होती देखी है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर दो बड़े पुल शामिल हैं, जिनमें एक भारत का सबसे लंबा 9.15 किलोमीटर का धोला-सादिया पुल और दूसरा 4.9 किलोमीटर लंबा बोगीबील पुल है, जो रेल और सड़क दोनों के लिए एशिया का सबसे लंबा संयुक्त पुल है। इस साल प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और 19 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी है, जो भारत का सबसे लंबा पुल होगा और असम में धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री अब आधारभूत ढांचे की एक और बहुप्रतीक्षित परियोजना पर जोर दे रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली को बाकी असम से जोड़ने वाला दो लेन का पुल है (मुख्यमंत्री विधानसभा में माजुली की ही नुमाइंदगी करते हैं)। मुख्यमंत्री बताते हैं कि राज्य सरकार ने इन तीन बड़े पुलों के अलावा 1,000 से ज्यादा लकड़ी के पुलों को भी कंक्रीट के पुलों में बदला है। असम में अपने एक हालिया भाषण में मोदी ने आधारभूत ढांचे के

जीएसडीपी साल दर साल

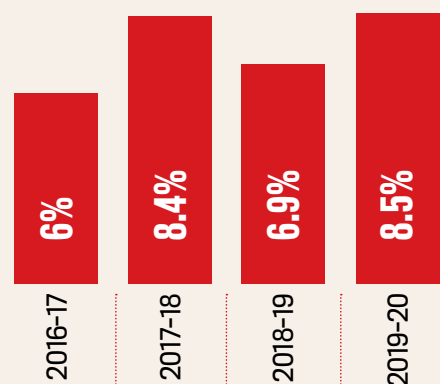
(मौजूदा दर पर; खरब रुपए में)



स्रोत: असम अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

विकास की थाह

जीएसडीपी की वार्षिक विकास दर
(स्थायी दरों पर)



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, असम आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20



आदिल हलीम/गेट्टी इमेजेज

विकास के मामले में राज्य की प्रगति को स्वीकार किया, “असम आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है, जहां 11,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है.”

असम की अर्थव्यवस्था

साल 2020-21 में असम का जीएसडीपी मौजूदा मूल्यों पर 4.09 लाख करोड़ रुपए यानी भारत की जीडीपी का करीब दो फीसद था। भाजपा की अगुआई वाली मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के बाद 2015-16 और 2020-21 के बीच असम का जीएसडीपी 12.58 फीसद की सीएजीआर (चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर) से बढ़ा। 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी मौजूदा मूल्यों पर 1,30,970 रुपए थी, जिसकी वजह से राज्य निचले पायदान के राज्यों में ही अपनी जगह बना पाया। राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वसरमा कहते हैं, “हम सामाजिक अशांति और असम की तरक्की में राजनैतिक दखलअंदाजी की विरासत में धंसे थे। लेकिन बीते पांच साल के कामों की रफतार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई ने पक्का कर दिया है कि असम जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में होगा.”

कृषि और रेशम उत्पादन

असम मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और लगभग 70 प्रतिशत लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है। हालांकि, राज्य की जीएसडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ 17 प्रतिशत है। चावल यहां का मुख्य भोजन है। असम मुख्य रूप से धान पैदा करता है लेकिन उत्पादकता दर खराब है। उदाहरण के लिए 2018 के आंकड़ों के अनुसार, असम 24.6 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती थी और 51.4 लाख टन चावल की पैदावार होती थी। भारत के चावल की खेती वाले राज्यों में असम नौवें स्थान पर है और देश की कुल चावल पैदावार के चार प्रतिशत से अधिक यह राज्य पैदा करता है। इसके विपरीत, चावल के चौथे सबसे बड़े उत्पादक राज्य तमिलनाडु ने केवल 20.4 लाख हेक्टेयर में धान की खेती करके 79.8 लाख टन चावल का उत्पादन किया, जो देश की कुल पैदावार का लगभग सात प्रतिशत है। राज्य में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में अनानास, केला, फूलगोभी, ब्रोकली, पपीता, गन्ना, हल्दी, जूट और आलू शामिल हैं। राज्य सरकार कृषि में सतत विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्र ने इसके लिए कई प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं। मिसाल के तौर पर, कामरूप (ग्रामीण) जिले के चायगांव में कुल 12 लाख डॉलर (8.7 करोड़ रुपए) की परियोजना लागत के साथ एक खाद्य प्रसंस्करण पार्क को मंजूरी दी है। ताजा और प्रसंस्कृत अदरक के लिए कृषि-निर्यात क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई है।

असम में लगभग 60,000 परिवार रेशम उद्योग पर निर्भर हैं। एरी और पाट के अलावा, असम मूंगा रेशम या ‘गोल्डन सिल्क’ का उत्पादन करता है। इसमें राज्य का एक और अनूठा योगदान है—दुनियाभर में होने वाले मूंगा के कुल उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत असम में होता है। हालांकि, बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण हाल के दिनों में मूंगा रेशम के उत्पादन को बड़ी चुनौतियों का सामना करना

पड़ा है। राज्य सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 2018 में 10 वर्षों की अवधि के लिए 460 करोड़ रुपए के साथ शुरू हुआ ‘मूंगा मिशन’ भी शामिल है। बाजार में नकली उत्पादों की बाढ़ भी आ गई है, जिससे रेशम उद्योग के लिए खतरा पैदा हो गया है—पावरलूम पर तैयार बनारसी रेशम उत्पादों को असमिया रेशम के रूप में बेचा जा रहा है। इसके कारण मार्च 2013 में राज्य के रेशम उत्पादक शहर सुआलकुची में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। 2016 में केंद्र ने सुआलकुची में बने रेशम उत्पादों के लिए एक आधिकारिक ट्रेडमार्क के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की। कुछ उत्साहजनक रुझान रहे हैं—2017-18 में 157 टन कच्चे मूंगा का उत्पादन किया गया था, जबकि उससे पहले के साल में यह 139 टन था।

उद्योग

हालांकि चाय, तेल और प्राकृतिक गैस राज्य के औद्योगिक परितृश्य पर हावी रहे लेकिन असम सरकार पर्यटन, दूरसंचार और फार्मास्युटिकल्स जैसे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मसलन, सन फार्मा ने उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए राज्य में लगभग 700 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

पिछले चार साल में असम में 20,971 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) और 105 बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं। राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे सार्क देशों के निकट हैं और सीमा-पार व्यापार की संभावनाओं के कारण निवेश की संभावना बढ़ जाती है।

इस समय राज्य में 20 औद्योगिक एस्टेट, तीन औद्योगिक विकास केंद्र, 11 एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास डिपो, 17 औद्योगिक क्षेत्र, 12 विकास केंद्र, आठ मिनी औद्योगिक एस्टेट, एक निर्यात प्रोत्साहन पार्क और एक खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क हैं। गुवाहाटी के पास अमीनगांव में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग 40 कंपनियां हैं, जो 4,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 12,000 को परोक्ष रोजगार मुहैया करती हैं। राज्य भर में 11 एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास केंद्र भी हैं, जिनमें से दो निर्माणाधीन हैं। केंद्र ने बारपेटा जिले के पथसला और डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में एमएसई-सीडीपी (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम) के तहत दो और परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया

की ओर से गुवाहाटी में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित किया गया है। सोनोवाल कहते हैं, “हम अपनी पारिस्थितिकी की कीमत पर अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं करना चाहते। अपने लगातार प्रयासों के कारण हम पिछले पांच वर्षों में 222 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ाने में सक्षम थे। गैंडे के अवैध शिकार के खतरे भी हमारे कार्यकाल के दौरान समाप्त हो गए हैं—हमने 240 से ज्यादा शिकारियों को गिरफ्तार किया और उनमें से 17 को फास्ट-ट्रैक अदालतों में दोषी ठहराया गया है।” जबकि 2012 और 2015 के बीच असम में शिकारियों ने 106 गैंडों को मार दिया था, वहीं जून 2016 से मई 2020 तक केवल 29 गैंडों का शिकार हुआ था।

चाय: असम में दुनिया का सबसे बड़ा चाय बागबानी क्षेत्र है। वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग सातवां हिस्सा और भारत के कुल चाय उत्पादन का 53 प्रतिशत हिस्सा असम में उत्पादित होता है। असम के लगभग 17 प्रतिशत श्रमिक इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य में 765 से अधिक चाय बागान हैं, साथ ही साथ 80,000 से अधिक पंजीकृत छोटे चाय उत्पादक हैं। वित्त वर्ष 20 में असम से 31.246 करोड़ डॉलर (लगभग 2,300 करोड़ रुपये) की कुल चाय का निर्यात हुआ।

तेल और प्राकृतिक गैस: असम भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्यों में से एक है। 2018-19 में असम ने 42 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, जो देश में तीसरा सबसे अधिक उत्पादन है और कुल उत्पादन का 13 प्रतिशत है। यह प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक था। 3,289 एमएमएससीएम (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) गैस का उत्पादन हुआ जो कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत था।

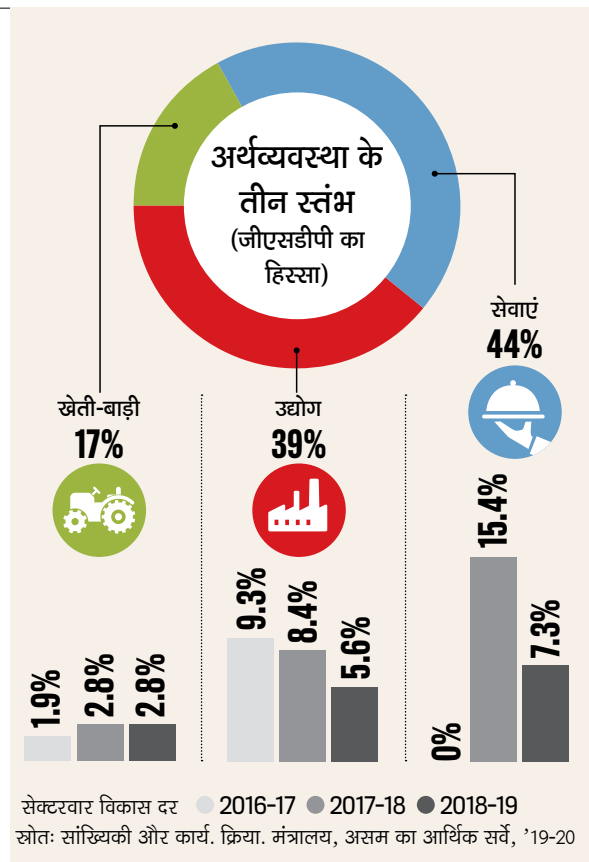
सेवाएं

राज्य के सेवा क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन इसके तेजी से बढ़ते योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है। राज्य की जीएसडीपी का 5.5 प्रतिशत और कुल रोजगार का लगभग 10.5 प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है। राज्य सरकार की कई पहलें, मसलन ‘ऑसम असम’ या अद्भुत असम प्रचार अभियान बहुत कारगर साबित हो रही हैं। इंडिया टुडे की राज्यों की रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार प्रदर्शन करने वाले राज्यों में असम 2018 के 20वें स्थान से सुधरकर 2020 में बारहवें स्थान पर पहुंच गया। असम में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, हालांकि 2020 में महामारी के कारण पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

सामाजिक क्षेत्र

राज्य में सामाजिक-राजनैतिक अस्थिरता का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्य की खराब बुनियादी ढांचे और मुख्य भूमि से इसकी भौगोलिक दूरी ने आर्थिक विकास और समावेशी विकास में असम के प्रदर्शन को बाधित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो प्रमुख सामाजिक सूचकांकों में असम का प्रदर्शन नीचे समझा जा सकता है।

शिक्षा: इंडिया टुडे के राज्यों की स्थिति के सर्वेक्षण में असम ने शिक्षा क्षेत्र में लगातार अपना प्रदर्शन सुधारा है। शिक्षा पर कुल व्यय, साक्षरता दर, प्राइमरी और मिडल स्कूलों में दाखिला लेने वाले लड़कों की



स्वास्थ्य तंत्र का बुनियादी ढांचा

37

जिला
अस्पताल

22

सब-डिविजनल
अस्पताल

1,661

प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र

321

सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र

5,845

उप केंद्र

शिक्षा तंत्र का बुनियादी ढांचा

उच्च शिक्षा के संस्थान

21

विश्वविद्यालय

512

कॉलेज

1

आइआइटी

30

औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान

स्कूल

56,520

(40,465 प्राइमरी स्कूल,
11,741 मिडल स्कूल और
4,314 हाइस्कूल)

“सामाजिक असंतोष और असम के विकास के प्रति एक राजनैतिक बेरुखी का भाव हमें विरासत में मिला था.

लेकिन पिछले पांच साल की गतिविधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने यह पक्का कर दिया है कि जल्दी ही असम देश के सबसे विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा”

हेमंत विस्वसरमा

वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण
विभाग मंत्री, असम

तुलना में लड़कियों का अनुपात, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, प्राथमिक और दसवीं तक की शिक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर और स्कूलों, कॉलेजों की संख्या जैसे मापदंडों से मापा जाता है. इसे तीन वर्षों में शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में और पिछले तीन वर्षों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में स्थान मिला है. हाल ही मंगलदोई में असम स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में पूर्वोत्तर में अपनी तरह के पहले संस्थान की नींव रखने वाले सोनोवाल कहते हैं, “हमने नौ इंजीनियरिंग कॉलेजों, 32 पॉलिटेक्निक संस्थानों और 400 से अधिक कौशल विकास केंद्रों को जोड़ा है. हमने जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, माजुली में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, चबुआ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लखीमपुर, बजाली, होजाई और नलबाड़ी में चार अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है. 2020 में राज्य सरकार ने धेमाजी जिले के गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया. राज्य में शिक्षा क्षेत्र में भी अब तक का सबसे बड़ा

भर्ती अभियान चला. राज्य के शिक्षा मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे सरमा कहते हैं, “पिछले पांच साल में हमने 71,000 शिक्षकों की भर्ती करके शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरा है.”

स्वास्थ्य: राज्य में संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के प्रतिशत में भी वृद्धि देखी गई है जो 2015-16 में 70.6 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 91 प्रतिशत हो गई है. परिणामस्वरूप यह बदलाव मातृ मृत्यु दर (23.67 प्रतिशत) और शिशु मृत्यु दर (6.38 प्रतिशत) में आने वाली गिरावट के लिए सहयोगी महत्वपूर्ण फैक्टरों में से एक रहा है. ऐसी उपलब्धियां वार्षिक इंडिया टुडे राज्यों की दशा-दिशा रैंकिंग में प्रतिबिंबित होती हैं कि यह राज्य पिछले तीन वर्षों में देश के शीर्ष पांच सबसे बेहतर राज्यों में से एक रहा है. नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के मुताबिक, असम को समग्र और वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में ‘अचीवर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था. मुख्यमंत्री सोनोवाल कहते हैं, “हमने राज्य में पिछले पांच वर्षों में आठ नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जिनमें एक एम्स और 18 कैंसर अस्पताल शामिल हैं.” स्वास्थ्य विभाग पर भी अपनी पकड़ रखने वाले सरमा कहते हैं कि “स्वास्थ्य पर निरंतर पैसा खर्च करके और केंद्र सरकार के सहयोग से हम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.”

कानून और व्यवस्था

एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि देश में आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत कुल संज्ञेय मामलों में असम की संख्या केवल 3.8 प्रतिशत है जो एक लाख लोगों पर 358.9 है और यहां की अपराध दर देश में तीसरे पायदान पर है. जैसा कि आपको विदित होगा कि राष्ट्रीय औसत अपराध दर 241.2 है. हत्याओं के मामले में असम की भारत में चौथी उच्चतम दर है और यहां अपहरण के कुल 56 मामले दर्ज किए गए जो देश में

मानस दास



✓ स्वास्थ्य पर ध्यान:
स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विस्वसरमा गुवाहाटी के एक कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए

आंकड़ों में असम

बुनियादी ढांचा



मार्च 2019 तक असम में 3,908.5 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो कि देश भर में फेले राजमार्गों के नेटवर्क का करीब तीन फीसदी हैं। **2016-17 और जनवरी 2020 के बीच 14,006 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ**



दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.94 किमी लंबे बोगीबिल सेतु के रूप में देश के सबसे लंबे रेल-सह-सड़क सेतु का लोकार्पण किया। **असम में 2,435.13 किमी लंबा रेल मार्ग है जो देश के कुल रेल नेटवर्क का करीब चार फीसदी है**



असम के मुख्य नदी जल मार्ग ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 891 किमी और 121 किमी है। **ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 2 के रूप में जाना जाता है।** राज्य में इस समय सात जलपत्तन हैं, जहां से कोलकाता और हल्दिया पत्तनों के लिए सामान भेजा और वहां से लाया जाता है



असम में आठ हवाई अड्डे हैं, **जिनमें गुवाहाटी का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है**

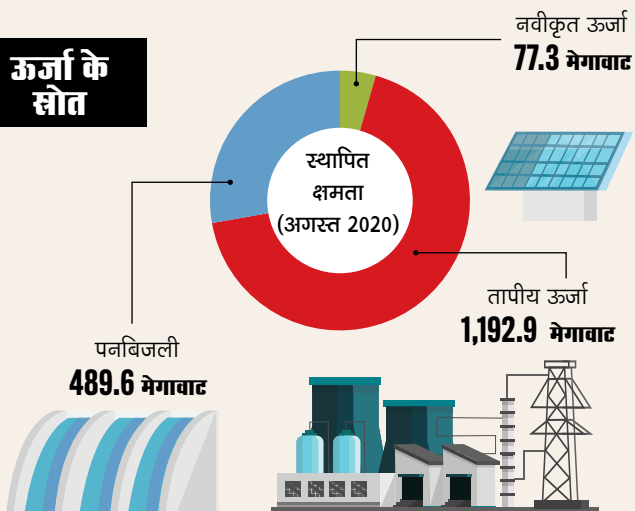


असम में **2.338 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता** और 1,11,505 लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ता हैं (मई 2020 तक)



अगस्त 2020 तक असम में **कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 1,759.84 मेगावाट थी, जिसमें से 1,253.64 मेगावाट** केंद्रीय उपयोग में, 71.83 मेगावाट निजी क्षेत्र के उपयोग में और 434.37 मेगावाट राज्य के उपयोग में आ रही थी। 2018-19 में राज्य अधिकतम उपयोग के समय 3.5 फीसदी बिजली की कमी झेल रहा था

ऊर्जा के स्रोत



राज्य की दशा-दिशा
रिपोर्ट 2021 असम

बीजू बोरो



▲ राष्ट्रीय पेय पदार्थ: राज्य में चाय के एक बागान का दृश्य

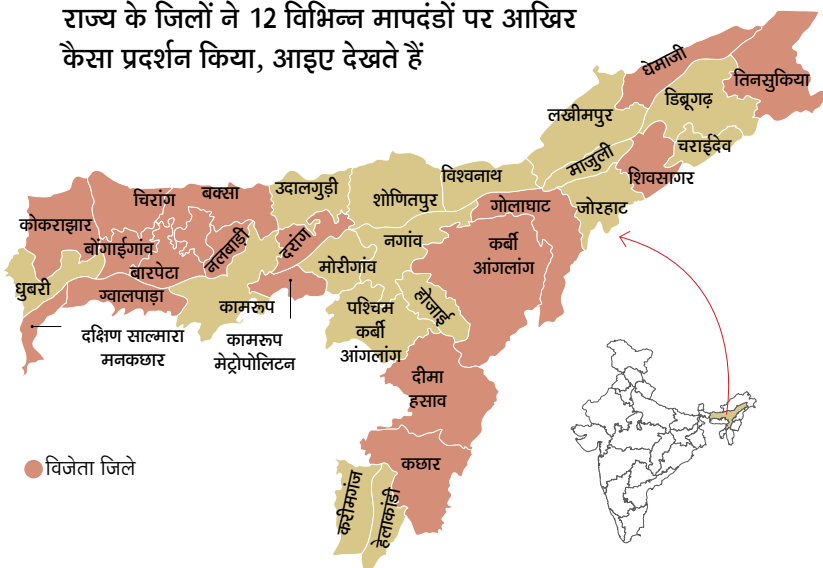
तीसरे उच्चतम स्थान पर हैं। हालांकि राज्य में होने वाले बलात्कार की उच्च दर की ओर सरकार का उतना ध्यान नहीं गया जितने की जरूरत थी, राज्य में प्रति 1,00,000 लोगों पर बलात्कार की 10.5 घटनाएं हुई हैं जो कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी दर है।

एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट में यह भी पता चला कि असम में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 397 मामले दर्ज किए गए, जो देखा जाए तो देश में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। राज्य पहले से ही पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहा है, यहां प्रति 1,00,000 लोगों पर 59 पुलिसकर्मी हैं जबकि लगभग समान आबादी वाले केरल में 99 और तेलंगाना में 90 हैं। फिर भी राज्य सरकार को इतना क्रेडिट तो जाना ही चाहिए कि असम में प्रति 1,000 लोगों पर लंबित मामलों की संख्या सिर्फ 9 है जो देश में सबसे कम है। इसके अलावा, राज्य ने आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने पर भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। जब भाजपा की अगुवाई वाली सरकार सत्ता में आई थी तब 2016 में 45 लोग मारे गए थे, जबकि 2020 में केवल सात लोग आतंकी हिंसा के शिकार हुए थे। जहां 2001 में 284 लोग आतंकवादी हिंसा की चपेट में आए थे वहीं 2019 में यह संख्या सिर्फ दो थी।

असम में जैसे-जैसे शांति बहाल होती जा रही है, राज्य धीरे-धीरे ही सही सामाजिक और आर्थिक प्रगति की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहा है। सरकार को विरासत में उग्रवाद और अशांति का माहौल मिलने के बावजूद, असम को देश में अग्रणी राज्यों के साथ-साथ चलने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, इसके लिए सरकार हरदम राज्य के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। सही मायने में असम मौजूदा समय में दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। ■

असम के सर्वश्रेष्ठ जिले

राज्य के जिलों ने 12 विभिन्न मापदंडों पर आखिर कैसा प्रदर्शन किया, आइए देखते हैं



ये रहे विजेता

श्रेणी	सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले	प्रदर्शन में सर्वाधिक सुधार करने वाले जिले
समग्र	कामरूप मेट्रो	दरांग
अर्थव्यवस्था	कामरूप मेट्रो	कछार
बुनियादी ढांचा	शिवसागर	धेमाजी
खेती-बाड़ी	कर्बी आंगलांग	नलबाड़ी
शिक्षा	धेमाजी	बक्स
स्वास्थ्य	नलबाड़ी	बारपेटा
कानून-व्यवस्था	कामरूप मेट्रो	बोंगाईगांव
राजकाज	बारपेटा	दक्षिण सालमारा मनकछार
सामाजिक सुरक्षा	गोलाघाट	दीमा हसाव
महिला सशक्तीकरण	बक्स	कोकराझार
कौशल विकास	ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा
स्वच्छता	तिनसुकिया	चिरांग

ऐसे की गई जिलों को रैंकिंग

‘इंडिया दुडे राज्य की दशा-दिशा-असम’ अध्ययन का काम दुनिया भर में प्रतिष्ठित मेजरमेंट और डेटा एनैलिटिक्स कंपनी नीलसन ने किया और राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और सबसे ज्यादा सुधार लाने वाले जिलों का पता लगाया. अध्ययन का यह काम नीचे लिखे चरणों में किया गया:

➤ **डेटा संग्रह:** डेटा संग्रह सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सरीखे कई द्वितीयक स्रोतों से किया गया

➤ **श्रेणियों और मानदंडों का निर्धारण:** जिलों को 12 श्रेणियों में रैंक देने का निर्णय किया गया. प्रत्येक श्रेणी में जिलों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा करके कई मानदंडों पर विचार किया गया

➤ **डेटा को सामान्य बनाना:** श्रेणियां तय होने के बाद डेटा को सामान्य बनाना था ताकि तमाम जिलों में सार्थक तुलना की जा सके. मापदंड को ध्यान में रखकर जनसंख्या/जीएसडीपी/अन्य कारकों के आधार पर डेटा को सामान्य बनाया गया

➤ **रैंकिंग:** प्रत्येक श्रेणी में हरेक मापदंड को बोर्ड पद्धति के अनुसार रैंक दी गई. रैंकिंग विचार किए जा रहे मापदंडों पर आधारित है—जहां बिजली वाले घर अधिक हैं उन्हें ज्यादा ऊंची रैंक दी गई, जबकि जहां अपराध की घटनाएं ज्यादा हैं उन्हें कम रैंक मिली

➤ **सूची बनाना:** मापदंडों पर प्राप्त रैंकिंग को जोड़कर श्रेणियों की सूची बनाई गई

➤ **शीर्ष जिलों की पहचान:** जिलों को रैंक दिए जाने के बाद शीर्ष जिलों की पहचान की गई. सर्वश्रेष्ठ जिले को रैंक देने के लिए सबसे हाल ही के साल का इस्तेमाल किया गया, जबकि सबसे सुधरे हुए जिले को रैंक देने के लिए सबसे हाल ही के मापदंड मूल्य और 10 वर्ष पहले के मानदंड मूल्य के बीच के अंतर का इस्तेमाल किया गया. हालांकि कुछ निश्चित मापदंडों में डेटा मौजूद नहीं होने की वजह से 10 साल की बजाय पांच या छह साल के अंतर के आधार पर सबसे सुधरे हुए जिले को रैंक दी गई. मसलन, कृषि में सर्वश्रेष्ठ जिले की रैंकिंग साल 2017-18 के आधार पर तय की गई, जबकि सबसे सुधरे हुए जिले की रैंकिंग 2011-12 और 2017-18 के बीच अंतर के आधार पर तय की गई.

*टिप्पणी: 33 जिलों का ही मूल्यांकन किया गया क्योंकि अध्ययन के समय तक बालाजी जिला नहीं बना था

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

कामरूप

मेट्रो

कामरूप मेट्रो असम का सर्वाधिक शहरीकृत जिला है और राज्य की राजधानी गुवाहाटी इसका मुख्य केंद्र है। जिले की आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा 82.7 फीसद है



- 1 कामरूप मेट्रो
- 2 जोरहाट
- 3 डिब्रूगढ़

यह क्यों जीता

जिस बात ने अंतिम नतीजा इस जिले के पक्ष में झुका दिया, वह थी दो बड़ी श्रेणियों अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था में इसका शीर्ष रैंक पर और साफ-सफाई में तीसरी रैंक पर आना। मानव विकास के लिहाज से यह शीर्ष 10 जिलों में था: स्वास्थ्य में नौवें पायदान पर और शिक्षा में दसवें पायदान पर

● सर्वाधिक सुधार वाला

दरांग

दरांग मध्य असम के बड़े जिलों में से एक है जिसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है



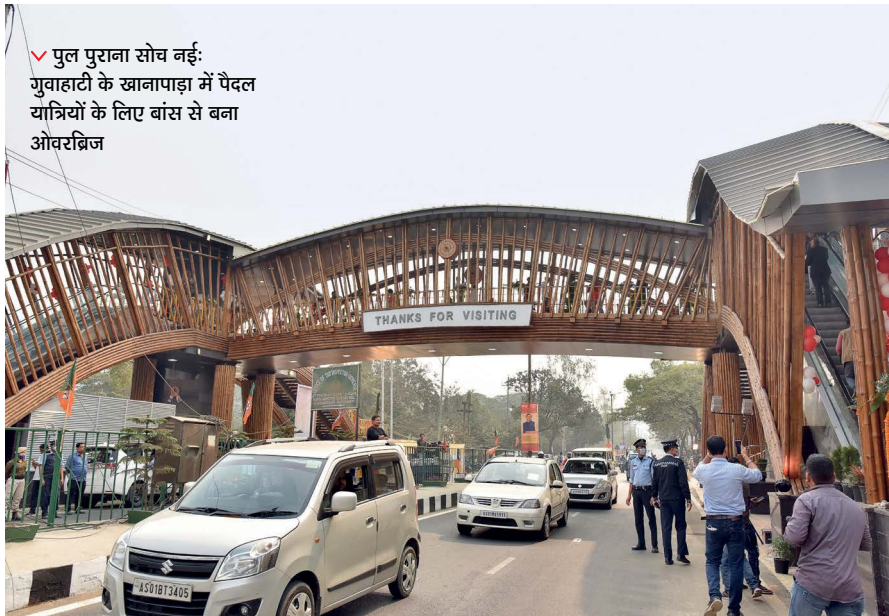
- 1 दरांग
- 2 कछार
- 3 कोकराझार

यह क्यों जीता

जिले ने सभी श्रेणियों में बराबर का सुधार दिखाया है। स्वास्थ्य में यह तीसरे पायदान पर तथा अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचे में पांचवें पायदान पर है

अर्थव्यवस्था

मानस दास



✓ पुल पुराना सोच नई:
गुवाहाटी के खानापाड़ा में पैदल यात्रियों के लिए बांस से बना ओवरब्रिज

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

कामरूप मेट्रो

इस श्रेणी में न केवल जिले की आर्थिक खुशहाली बल्कि इसका औद्योगिक ढांचा और सेवा क्षेत्र भी शामिल है

शीर्ष 3

- 1 कामरूप मेट्रो
- 2 डिब्रूगढ़
- 3 जोरहाट



यह क्यों जीता

यह जिला प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति बैंक कर्ज, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले परिवारों का प्रतिशत, बैंक शाखाओं की मौजूदगी, एटीएम की मौजूदगी और सेवा क्षेत्र में लगे कमियों सहित ज्यादातर मानदंडों पर नंबर 1 पायदान पर है

● सर्वाधिक सुधार वाला

कछार

कछार का जिला मुख्यालय सिल्वर असम की बराक घाटी का व्यावसायिक केंद्र है

शीर्ष 3

- 1 कछार
- 2 कामरूप मेट्रो
- 3 बक्स

यह क्यों जीता

साल 2011 और 2017 के बीच कछार की जीडीपी प्रति व्यक्ति 42,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए हो गई। जिले में सालाना 75,000 रुपए से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या दूसरे जिलों के मुकाबले कम है। जिले ने प्रति व्यक्ति बैंक कर्ज (नं. 8) और औद्योगिक क्षेत्र में श्रम बल की भागीदारी (नं. 8) सरीखे दूसरे मानदंडों पर भी शीर्ष 10 सुधरे हुए जिलों में स्थान हासिल किया है

मापदंड: प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति खर्च, रोजगार दर, प्रति व्यक्ति बैंक कर्ज, 75,000 रु. से कम कमाने वाले परिवारों का प्रतिशत, बैंकिंग सेवा का लाभ लेने वाले परिवारों का प्रतिशत, बैंक शाखाओं की उपलब्धता, एटीएम की उपलब्धता, औद्योगिक जीडीपी का जिले के कुल जीडीपी में योगदान, उद्योग क्षेत्र में रोजगार, प्रति व्यक्ति उद्योग, श्रमिकों की हिस्सेदारी, सेवाओं की जीडीपी का जिले के कुल जीडीपी में योगदान, सेवाओं में रोजगार, प्रति व्यक्ति सेवाओं का जीडीपी

बुनियादी ढांचा

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

शिवसागर

शिवसागर असम की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। यहां रंग घर, करेंग घर और तोलातोल घर सरीखे वास्तुकला के चमत्कार भी हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा दो अन्य बड़ी नदियां दिसांग और जांजी भी यहीं से बहती हैं

शीर्ष 3

- 1 शिवसागर
- 2 जोरहाट
- 3 चैरादेव

यह क्यों जीता

शिवसागर ने कई मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया। मसलन, प्रति 1,00,000 आबादी पर सड़कों की लंबाई और पीएमजीएसवाई के तहत जुड़े हुए गांवों की संख्या में नं. 4 पायदान पर और बिजली से जुड़े परिवारों के मामले में नं. 6 पायदान पर आया



● सर्वाधिक सुधार वाला

धेमाजी

धेमाजी कृषि प्रधान जिला है। यहां की 85 फीसद से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है

शीर्ष 3

- 1 धेमाजी
- 2 उदालगुड़ी
- 3 कामरुप मेट्रो

यह क्यों जीता

पीएमजीएसवाई के तहत जुड़े गांवों के प्रतिशत के लिहाज से यह जिला नं. 1 पायदान पर रहा। इस योजना के तहत जुड़े हुए गांवों की संख्या 2011-12 में 336 से बढ़कर 2017-18 में 942 हो गई, जो छह साल की अवधि के दौरान करीब 180 फीसद की बढ़ोतरी है। बिजली के कनेक्शन वाले घरों के प्रतिशत में 30 फीसद का इजाफा हुआ और इस मानदंड पर यह जिला नं. 2 पायदान पर आ गया

मापदंड बिजली कनेक्शन प्राप्त घरों का प्रतिशत, प्रति एक लाख की आबादी पर बस/ट्रेन स्टेशनों की संख्या और सड़कों की लंबाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जुड़े गांवों का प्रतिशत



✓ खेती आधार:
कर्बी आंगलांग जिले के
डोकमोका में धान की रोपाई

खेती-बाड़ी

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

कर्बी आंगलांग

कर्बी आंगलांग घने उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित असम का प्रमुख जिला है जहां अनेक आदिवासी और जातीय समूह वास करते हैं

शीर्ष 3

- 1 कर्बी आंगलांग
- 2 पश्चिम कर्बी आंगलांग
- 3 दीमा हसाव

यह क्यों जीता

कृषि में जिलों को रैंक देने के लिए सात मानदंडों का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर मानदंडों पर कर्बी आंगलांग ने शीर्ष तीन में जगह हासिल की—जिले के कुल जीडीपी में कृषि का योगदान (नं. 1), बुआई के कुल क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (नं. 2), प्रति व्यक्ति कृषि जीडीपी (नं. 3), कुल कृषि क्षेत्र में से फसल क्षेत्र (नं. 1) और कृषि में लगे श्रमिकों का प्रतिशत (नं. 2)



● सर्वाधिक सुधार वाला

नलबाड़ी

नलबाड़ी निचले असम के सबसे बड़े और सामाजिक-राजनैतिक तौर पर सबसे जीवंत जिलों में से एक है

शीर्ष 3

- 1 नलबाड़ी
- 2 डिब्रूगढ़
- 3 कर्बी आंगलांग

यह क्यों जीता

प्रति व्यक्ति कृषि जीडीपी 2011 में 11,848 रुपए से बढ़कर 2017 में 22,771 रुपए हो गई। नलबाड़ी में नकदी फसल उगाने वाला क्षेत्र 2011-12 से 2016-17 के बीच 190 गुना बढ़ा, जो तमाम जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी। कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों का प्रतिशत 2011 से 2017 के बीच छह सालों में 49 फीसद से बढ़कर 51 फीसद हो गया

मापदंड बिजली कनेक्शन प्राप्त घरों का प्रतिशत, जिले की कुल जीडीपी में कृषि का योगदान, अनाज (धान, गेहूं, मक्का) की पैदावार, कुल बुआई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का अनुपात, प्रति व्यक्ति कृषि जीडीपी, पैदावार-निश्चित क्षेत्र में पैदा फसल, खेती में रोजगार प्राप्त श्रमिकों का प्रतिशत, खेती के कुल क्षेत्र में नकदी फसलों का प्रतिशत

शिक्षा

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

धेमाजी

शिक्षा के मामले में जिलों के प्रदर्शन का एक वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए दस मापदंडों पर चयन किया गया था



शीर्ष 3

①

धेमाजी

②

बोंगाईगांव

③

माजुली

यह क्यों जीता

धेमाजी में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 1.02 (2016-17) रहा, जो सभी जिलों में सबसे अधिक था। धेमाजी में सभी प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील मुहैया करते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था है। खेल के मैदानों वाले स्कूलों के मामले में जिले को दूसरा स्थान मिला

● सर्वाधिक सुधार वाला

बक्स

यह 2003 में बोडोलैंड स्वायत्त जिला क्षेत्रों के गठन के बाद बने चार जिलों में से एक है

शीर्ष 3

①

बक्स

②

उदालगुड़ी

③

कामरूप मेट्रो

यह क्यों जीता

बक्स ने शिक्षा की श्रेणी के लगभग सभी मापदंडों पर समान सुधार दिखाया है। छात्र-शिक्षक अनुपात और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की घटी दर के मामले में यह जिला पहले स्थान पर था। छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या का अनुपात (प्राथमिक) 2011-12 में 0.99 से बढ़कर 2016-17 में 1.02 हो गया और इसे दूसरे स्थान की रैंकिंग मिली। पांच वर्षों में खेल के मैदान युक्त स्कूलों की संख्या 50.7 प्रतिशत से बढ़कर 62.3 प्रतिशत हो गई

मापदंड: छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राइमरी), प्रति हजार आबादी पर स्कूलों की संख्या, छात्र-छात्राओं का अनुपात (प्राइमरी), पढ़ाई छोड़ने की दर (कक्षा एक से पांच), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाने की दर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर दाखिले की दर, खेल के मैदान वाले स्कूलों का प्रतिशत, मिड डे मील देने वाले स्कूलों का प्रतिशत, बिजली की सुविधायुक्त स्कूलों का प्रतिशत, पीने के पानी की सुविधायुक्त स्कूलों का प्रतिशत



^ गढ़े जाते भविष्य:
धेमाजी का सेंट
फ्रांसिस डि सेल्स स्कूल

कानून-व्यवस्था

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

कामरूप मेट्रो

इस श्रेणी में मूल्यांकन कुल छह मानदंडों पर हुआ

शीर्ष 3

①

कामरूप मेट्रो

②

जोरहाट

③

बोंगाईगांव

यह क्यों जीता

कम अपराध दरों के साथ दो मानदंडों पर जिला अव्वल स्थान पर रहा। ये मापदंड थे: कुल संज्ञेय अपराधों में से अपहरण की घटनाएं और आइपीसी अपराधों में हत्या। बलात्कार की कम घटनाओं के लिहाज से इसका प्रदर्शन अच्छा रहा और यह तीसरे स्थान पर रहा। जिले में 20 पुलिस थाने हैं।



● सर्वाधिक सुधार वाला

बोंगाईगांव

बोंगाईगांव राज्य के पश्चिमी जिलों में से एक है और यह निचले असम में एक अग्रणी वाणिज्यिक केंद्र है

शीर्ष 3

①

बोंगाईगांव

②

दीमा हसाव

③

धुबरी

यह क्यों जीता

बोंगाईगांव कई वजहों से इस श्रेणी में पहले स्थान पर रहा—2011-12 में 110 दंगे हुए थे, 2017-18 में इनकी संख्या घटकर दो रह गई; कुल संज्ञेय आइपीसी अपराधों में से बलात्कार की संख्या 2011-12 में 5 प्रतिशत थी जो 2017-18 में घटकर 2 प्रतिशत रह गई और 2011-12 से 2017-18 के बीच आइपीसी के तहत कत्ल की घटनाओं में 25 प्रतिशत की कमी आई

मापदंड कुल संज्ञेय आइपीसी अपराधों में अपहरण और फिरोती के मामले, कुल आबादी के अनुपात में कुल संज्ञेय आइपीसी अपराध के मामले, कुल संज्ञेय आइपीसी अपराधों में कत्ल की संख्या, कुल संज्ञेय आइपीसी अपराधों में बलात्कार की संख्या, कुल संज्ञेय आइपीसी अपराधों में दंगों के मामले, प्रति लाख आबादी पर थानों की संख्या

स्वास्थ्य

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

नलबाड़ी



शीर्ष 3

1

नलबाड़ी

2

जोरहाट

3

माजुली

यह क्यों जीता

स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या (सार्वजनिक और सामुदायिक) 2017-18 में 53 थी जो दूसरी सबसे ज्यादा थी. घरों में होने वाले सभी प्रसवों में से 82 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से हुए. जिला प्रति लाख आबादी पर सरकारी चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है और सरकारी क्षेत्र में प्रति स्वास्थ्य संस्थान बिस्तरों की संख्या के लिहाज से छठे स्थान पर

● सर्वाधिक सुधार वाला

बारपेटा

यह निचले असम का एक प्रमुख जिला है. यह राज्य का सामाजिक धार्मिक केंद्र भी है

शीर्ष 3

1

बारपेटा

2

मोरीगांव

3

दरांग

यह क्यों जीता

कुल ज्ञात प्रसव में से संस्थागत प्रसव पांच वर्षों में 59.6 प्रतिशत से बढ़कर 75.1 प्रतिशत हो गया. प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों की संख्या 60 से बढ़कर 104 हो गई और जिले का रैंक पांचवा हो गया. एसबीए स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता से घर में होने वाले प्रसव की संख्या 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई

मापदंड शिशु मृत्यु दर, संज्ञान में आए प्रसव में इन्फुनाइज्ड शिशु, सरकारी क्षेत्र में प्रति अस्पताल बेड की संख्या, मातृ मृत्यु दर, संज्ञान में आए कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत, एसबीए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद से घर पर संपन्न प्रसव का प्रतिशत, प्रति लाख आबादी पर डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों की संख्या



शटरस्टॉक

साफ-सफाई

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

तिनसुकिया

यह राज्य के पूर्वी जिलों में से एक है और असम का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है

शीर्ष 3

1

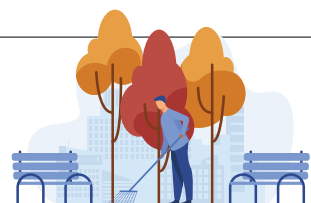
तिनसुकिया

2

डिब्रूगढ़

3

कामरूप मेट्रो



यह क्यों जीता

तिनसुकिया में 96.7 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में बालिका शौचालय उपलब्ध हैं और इस लिहाज से यह जिला राज्य में तीसरे पायदान पर है. इसी तरह 93 प्रतिशत घरों में स्वच्छता की बेहतर सुविधा है और 99 प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल के बेहतर स्रोत उपलब्ध हैं

● सर्वाधिक सुधार वाला

चिरांग

बोडोलैंड स्वायत्त जिला क्षेत्रों के गठन के बाद बने चार जिलों में से

शीर्ष 3

1

चिरांग

2

कोकराझार

3

धेमाजी

यह क्यों जीता

बालिका शौचालयों की सुविधा से युक्त स्कूलों की संख्या 48.9 प्रतिशत से बढ़कर 78.7 प्रतिशत हो गई. इस लिहाज से यह जिला राज्य में दूसरे स्थान पर रहा. 2011 और 2017 के बीच बेहतर स्वच्छता सुविधासंपन्न परिवारों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई. बेहतर पेयजल व्यवस्था वाले परिवारों की संख्या 2011 में 92 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 98 प्रतिशत हो गई

मापदंड बेहतर सफाई सुविधा से युक्त घर, साफ पेयजल सुविधासंपन्न घर, टैप वाटर को पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने वाले घर, बालिकाओं के लिए चालू हालत में शौचालय की सुविधायुक्त स्कूलों का प्रतिशत, ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त पेयजल की सुविधाप्राप्त बस्तियों का प्रतिशत



▲ लेडीज फर्स्ट, राज्य की कनकलता महिला सबलीकरण योजना का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री सोनोवाल

महिला सशक्तीकरण

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

बक्स

शीर्ष 3

1

बक्स

2

विश्वनाथ

3

शोणितपुर

यह क्यों जीता

2015-16 के राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण-4 के अनुसार, बक्स में लिंग अनुपात सभी जिलों में सबसे ज्यादा—1,000 पुरुषों पर 1,046 महिलाएं—है. 15-49 आयु समूह की 58 फीसद से ज्यादा महिलाओं ने 2015-16 में परिवार नियोजन के कम से कम एक तरीके का इस्तेमाल किया, जो तमाम जिलों में आठवां सबसे ज्यादा प्रतिशत है



● सर्वाधिक सुधार वाला

कोकराझार

पश्चिमी सरहदी जिला कोकराझार बोर्डोलैंड स्वायत्त भूभागीय जिला क्षेत्र का मुख्यालय है

शीर्ष 3

1

कोकराझार

2

गोलाघाट

3

धेमाजी

यह क्यों जीता

परिवार नियोजन के किसी न किसी एक उपाय का इस्तेमाल करने वाली 15-49 आयु समूह की महिलाओं का प्रतिशत 2002-04 में 35.4 फीसद से बढ़कर 2015-16 में 56.7 फीसद पर पहुंच गया. कोकराझार में लिंग अनुपात 2011 में 959 से बढ़कर 2015-16 में 1,009 हो गया

मापदंड 15-49 आयु वर्ग की, परिवार नियोजन का कोई न कोई उपाय अपनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत, स्त्री-पुरुष अनुपात



▲ हर रोज नया हुनर: ग्वालपाड़ा के पास घेंगामारी के एक फार्म पर स्वर शीट सुखाता कारीगर

कौशल विकास

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

ग्वालपाड़ा

ग्वालपाड़ा पश्चिम असम का सीमांत जिला है. कौशल विकास की यह श्रेणी इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से की गई पहलों का विश्लेषण करती है

शीर्ष 3

1

ग्वालपाड़ा

2

विश्वनाथ

3

शोणितपुर

यह क्यों जीता

जिला प्रशासन ने कामकाजी आबादी का प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान दिया, कौशल विकास कार्यक्रम जिसका अभिन्न अंग है. ग्वालपाड़ा ने 2017-18 में 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए, जबकि लक्ष्य 90 कार्यक्रमों का था

मापदंड राज्य पंचायत संस्थान और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिलेवार चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजकाज

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

बारपेटा

राजकाज की श्रेणी में दो बड़े मापदंडों पर विचार किया गया—ग्राम पंचायत स्तर पर साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) का कवरेज/स्थापना और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या

शीर्ष 3

- 1 बारपेटा
- 2 होजाई
- 3 दरांग

यह क्यों जीता

2017 में बारपेटा में सबसे ज्यादा साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) की शुरुआत की गई. जिले का लक्ष्य 158 स्व-सहायता समूह बनाना था जबकि बनाए गए 833



एएफपी

● सर्वाधिक सुधार वाला

दक्षिण सलमारा-मनकछार

पहले असम के पश्चिमी सीमांत के धुबरी जिले का हिस्सा रहा दक्षिण सलमारा-मनकछार 2016 में जिला बनाया गया

शीर्ष 3

- 1 दक्षिण सलमारा-मनकछार
- 2 होजाई
- 3 बारपेटा



यह क्यों जीता

2012 में केवल 52 साझा सेवा केंद्रों की शुरुआत हुई थी, जो 2017 में बढ़कर 114 हो गए. स्व-सहायता समूहों की संख्या 2011-12 में 121 से बढ़कर 2017-18 में 1,006 हो गई

मापदंड ग्राम पंचायत स्तर पर साझा सेवा केंद्रों की कवरेज/स्थापना, महिलाओं के कुल स्थापित स्वयं सहायता समूहों की संख्या

सामाजिक सुरक्षा

● सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

गोलाघाट

सामाजिक सुरक्षा का मूल्यांकन तमाम पेंशन योजनाओं, मनरेगा के जरिए रोजगार का सृजन और घर-परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुलभता के आधार पर किया गया



शीर्ष 3

- 1 गोलाघाट
- 2 लखीमपुर
- 3 डिब्रूगढ़

यह क्यों जीता

ऊपरी असम के प्रमुख जिलों में से एक गोलाघाट ने तमाम मापदंडों पर समान प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत यह शीर्ष पर पहुंचा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की उपलब्धियों के मामले में यह चौथे पायदान पर रहा

● सर्वाधिक सुधार वाला

दीमा हसाव

पहले उत्तरी कछार हिल्स के नाम से जाने जाने वाले इस जिले में आदिवासियों की कुल आबादी के 71 फीसद हैं

शीर्ष 3

- 1 दीमा हसाव
- 2 गोलाघाट
- 3 नलबाड़ी

यह क्यों जीता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के मामले में इस जिले ने 2011-12 और 2017-18 के बीच बेमिसाल प्रदर्शन किया. मनरेगा के जरिए दिए गए रोजगार के मामले में यह पहले पायदान पर रहा. स्वच्छ रसोई ईंधन वाले घर-परिवारों के लिहाज से यह जिला छठ सबसे अधिक सुधरा हुआ जिला था

● सर्वाधिक सुधार वाला

यह क्यों जीता

कौशल विकास पर निरंतरता के साथ ध्यान दिया गया है. असम के ग्वालपाड़ा में राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 2011-12 में 76 के मुकाबले 2017-18 में 130 हो गई, छह साल में 71 फीसदी की वृद्धि

शीर्ष 3

- 1 ग्वालपाड़ा
- 2 तिनसुकिया
- 3 दरांग



मापदंड मनरेगा के तहत लाभ पाने वालों की तादाद, स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने वाले घरों का प्रतिशत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की उपलब्धि

किताबें

दो लेखकों/पतियों की जीवनगाथा

देवेन्द्र राज अंकुर

लंबे लॉकडाउन के दौरान हिंदी के दो समकालीन साहित्यकारों की जीवन गाथा पढ़ने को मिली। एक का शीर्षक है *तिल भर जगह नहीं* और दूसरी का *अंदाज़-ए-बयां उर्फ रवि कथा*। दोनों में किस्सागोई की सहजता, रवानगी और साथ-साथ आत्मीयता भरी पड़ी है। दोनों में कई बातें समानांतर दिखीं। दोनों एक ही प्रकाशक के यहां से छप कर आई और लगभग एक साथ दोनों ही लेखक अब हमारे बीच नहीं रहे। दोनों जीवनियों को उनकी पत्नियों ने लिखा है, जो स्वयं भी बड़ी रचनाकार हैं। अवधनारायण मुद्गल की कथा चित्रा मुद्गल और रवींद्र कालिया की ममता कालिया ने प्रस्तुत की है।

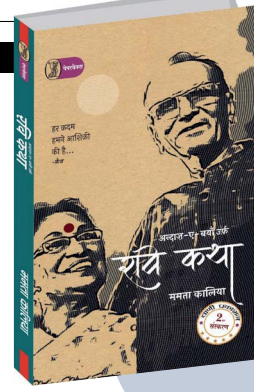
कुछ गहरी समानताएं भी हैं। पत्नी होने के बावजूद दोनों लेखिकाओं ने जितनी आत्मीयता के साथ लिखा है, उससे कहीं ज्यादा निष्पक्षता-तटस्थता को भी बरकरार रखा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी अपने अंतरंग प्रेमी और पति के बारे में इतनी बेवाकी और खुलेपन से किसी लेखिका ने लिखा हो। या तो हम उसे कठघरे में खड़ा कर देते हैं या देवता बना देते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों जीवनीकारों ने अपने-अपने विषय को संपूर्णता से रचने की कोशिश की है—अवधनारायण मुद्गल या रवींद्र कालिया की हर खूबी, कमजोरी, झगड़ा और प्यार के क्षण को पूरे मनोयोग से जीवंत किया गया है। दोनों जीवन गाथाएं अलग अलग होकर भी एक दूसरे में आवाजाही करती रहती हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि अवधनारायण मुद्गल की कहानी में रवींद्र कालिया और उनका परिवार जब चाहे चले आते हैं। ठीक ऐसा ही रवि कथा में होता है।

इसके बावजूद दोनों जीवन गाथाएं अपनी अलग-अलग पगडंडियों पर भी निकल पड़ती हैं। अवधनारायण मुद्गल की जीवनी का शीर्षक *तिल भर जगह नहीं* उन्हीं की एक कविता *नागयज्ञ और मैं* की कुछ पंक्तियों पर

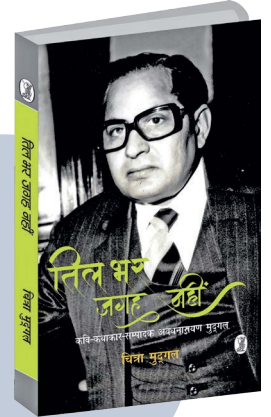
रखा गया है। यह किताब वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित 'अमृत लाल नगर सुजनपीठ' में आमंत्रित लेखकीय आवास के दौरान एक विनिबंध के रूप में लिखी गई थी। इसीलिए शुरू में कुछ औपचारिक लगती है लेकिन कब वह आत्मीयता में बदल जाती है, पता नहीं चलता। एक तरफ अवधनारायण मुद्गल के जीवन के छोटे-से छोटे ब्यौरे से हमारा परिचय होता चलता है तो साथ-साथ उनके कवि, कथाकार, अनुवादक और संपादक रूप से भी गहरे में साक्षात्कार होता है। जिस तरह से चित्रा जी ने अवधनारायण मुद्गल की एक-एक कहानी की समीक्षा की है उसे पढ़कर लगता है कि वे आलोचक के रूप में भी कम नहीं। जीवनी के सबसे मार्मिक और सशक्त प्रसंग वे हैं जब वे मुद्गल जी से जुड़े पारिवारिक प्रसंगों में जाती हैं—पहले उनके प्रणय प्रसंग और उसके बाद शामिल होता परिवार। विशेष रूप से छोटी बेटी, दामाद और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु की त्रासदी को चित्रा जी ने बहुत ही आत्मीयता में जाकर पकड़ा है। मुद्गल को रेसकोर्स जाने की लत पड़ गई थी। वे इस पूरे हादसे में कैसे बाहर निकले, उनके साथ लगातार स्थितियों को झेल रही पत्नी से बेहतर कौन शेयर कर सकता है।

ममता कालिया ने रवि कथा को एक विधिवत जीवनी लेखन का रूप नहीं दिया है। इसके कुछ हिस्से रवींद्र कालिया के जाने के बाद उन्होंने *तद्भव* के लिए लिखे थे। उनको

पत्नी होने के बावजूद चित्रा मुद्गल और ममता कालिया ने जितनी आत्मीयता से लिखा है, उससे कहीं ज्यादा निष्पक्षता और तटस्थता को भी बरकरार रखा है



**अंदाज़-ए-बयां
उर्फ रवि कथा**
ममता कालिया
वाणी प्रकाशन,
दिल्ली
कीमत: 299
रुपए



**तिल भर
जगह नहीं**
चित्रा मुद्गल
वाणी प्रकाशन,
दिल्ली
कीमत: 199
रुपए

मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर उन्होंने उसे एक पुस्तक रूप देने का मन बनाया होगा। पुस्तक एक क्रमवार जीवन गाथा न होकर रवींद्र कालिया और उनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं और संस्मरणों का एक कोलाज जैसी है। कथा का आरंभ वर्तमान में होता है और फिर कभी फ्लैशबैक और कभी फ्लैश फॉरवर्ड के माध्यम से अपने प्रेमप्रसंग, विवाह, परिवार और उससे जुड़ी लगभग सभी घटनाओं को अपने कथाजाल में समेटती चलती है। परिवार यहां भी है लेकिन अपने से ज्यादा कालिया जी का परिवार मौजूद है, विशेषरूप से उनकी मां। कभी खुशी कभी गम के बीच यहां भी एक ऐसा करुण प्रसंग मौजूद है जब वे गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या करने के इरादे से घर छोड़कर चल देती हैं। पूरा प्रसंग जिस सुखद अंत पर खत्म होता है, कालिया जी की प्रतिक्रिया देखते ही बनती है। पुस्तक के शीर्षक के अनुरूप ममता जी ने कहानी सुनाने के अंदाज को बनाए रखा है। ■



भारत की प्रतिनिधि फिल्में

दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक **बर्लिन फिल्म फेस्टिवल** में इस साल देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं दो प्रयोगात्मक फिल्में

दो अवां गार्द या पूरी तरह से अलग मिजाज वाली फिल्में हैं जो इस साल 71वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में देश को अपना चेहरा बचाने में मदद कर रही हैं। ये हैं दिल्ली के फोटोग्राफर-फिल्मकार सोहराब हुरा की 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म *द कोस्ट* और नईम मोहाईमन की फीचर फिल्म *जोले डूबे ना* (वे जो डूबते नहीं), जो जापान-स्वीडन-भारत के सहनिर्माण में बनी 64 मिनट की फिल्म है। दोनों फिल्में फेस्टिवल के प्रयोगात्मक फिल्मों वाले हिस्से 'फोरम एक्सपांडेड' में शामिल की गई हैं, जो दूसरी कलाओं के साथ सिनेमा के रिश्तों की पड़ताल करता है। कोविड के चलते बर्लिनाले को दो हिस्सों में बांटा गया है। फिल्मों का चयन 1 से 5 मार्च तक यूरोपीय फिल्म बाजार को ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, जबकि उत्सव स्थल यानी बर्लिन के सिनेमाघरों में यह फेस्टिवल 9 से 20 जून के बीच होगा।

द कोस्ट प्रयोगात्मक शॉर्ट फिल्म है जिसमें कोई संवाद नहीं है। प्रतिष्ठित फोटोग्राफर, फिल्मकार, लेखक और मैगनम फोटोज के सदस्य हुरा की यह फिल्म तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम का दशहरा देखती-दिखाती है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान जोड़े गए हैं, जिनमें से कुछ हिंसक उन्माद जगाने वाले हैं—एक आदमी अपने सिर पर नारियल फोड़ता है। तकरीबन सब कुछ दोहराव से भरा और स्लो मोशन में है, जिसमें यांत्रिक साउंड ट्रैक कुतूहल बढ़ा देता है। ढाका और लाहौर के रहने वाले माता-पिता की संतान हुरा कहते हैं, “तट जगह बदल रहा है, बिल्कुल कगार पर आ गया है। जमीन ठोस और स्थिर है, लेकिन समुद्र की लहरें आपको ठीक से खड़ा नहीं रहने देतीं, अपनी स्थिति बदलने को मजबूर कर देती हैं। आज मैं दुनिया में ऐसा ही महसूस करता हूँ।”

लंदन में जन्मे फिल्मकार-कलाकार-लेखक नईम मोहाईमन की जड़ें बांग्लादेश में हैं। वे न्यूयॉर्क और ढाका के बीच काम

स्वाब-सा

(बाएं) *जोले डूबे ना* के एक दृश्य में खेया चट्टोपाध्याय; *द कोस्ट* का एक दृश्य



करते हैं और दुनिया भर में अपने काम प्रदर्शित कर चुके हैं। बांग्ला में बनी उनकी फिल्म *जोले डूबे ना* बर्लिनाले में उनकी दूसरी फिल्म है। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म *अबू अमार इज कर्मिंग* 2016 के फेस्टिवल में दिखाई गई थी। दूसरों की देखभाल करने वालों की बाद की उनकी जिंदगी

को दिखाने वाली *जोले डूबे ना* योकाहामा त्रिनाले 2020 जापान ने कमीशन, रक्स मीडिया कलेक्टिव ने ब्यूरोट और बिल्डमुसीत स्वीडन ने को-कमीशन की थी।

कोलकाता के एक खाली अस्पताल की स्वप्निल दुनिया में रंजिशजदा युगल ज्योति (साग्निक मुखर्जी) और

सूफिया (खेया चट्टोपाध्याय) एक अनजान बीमारी के बाद हिचकिचाहट के साथ फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। ई-मेल के जरिए एक बातचीत में मोहाईमन बताते हैं, “सूफिया की जिंदगी के आखिरी दिनों में ज्योति इस तरह उसे दुलारना और उसकी देखभाल करना चाहता है जिस तरह दवाई नहीं कर सकती। सूफिया उसे बताती है कि प्लास्टिक-धातु के अवरोधों को हटा देना भी उसके लिए राहत हो सकती है; अपने साथी को भीषण अंतिम संस्कार से मुक्त करने की राहत।”

जोले डूबे ना दिल्ली में 3-10 मार्च को (एक्सपेरिमेंटर, बीकानेर हाउस) और कोलकाता में 19 मार्च (एक्सपेरिमेंटर, बॉलीगंज प्लेस) को दिखाई जाएगी।

—मीनाक्षी शेडे

भारत से चुनी गई दोनों फिल्में फेस्टिवल के प्रयोगात्मक फिल्मों वाले हिस्से फोरम एक्सपांडेड में शामिल की गई हैं

सवाल + जवाब हर हाल में जीने का फन

1962 के भारत-चीन युद्ध पर बनी नई सीरीज के अपने किरदार की तरह बेबाक बोलने वाले **अभय देओल** ने अपना करियर धारा के खिलाफ खड़े रहकर बनाया है

● युद्ध की कथाभूमि पर तो बहुत-सी फिल्मों/सीरीज बनीं लेकिन 1962 का भारत-चीन युद्ध इस लिहाज से लगभग अछूता ही रहा है... चीन के साथ हुए युद्ध में हम इसलिए नहीं झंकाया चाहते क्योंकि उसमें हार गए थे. हम जीते युद्धों का ही महिमागान करते हैं. देखिए, जमीन की जीत-हार भले होती हो पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध में कोई जीतता-हारता है. 1962: द वार इन द हिल्स में उस एक लड़ाई पर है जिसे हम जीते और जिसका जश्न मनाया.

● युद्ध पर बनी प्रस्तुतियों का कथानक अमूमन अतिराष्ट्रवाद की चाशनी में डूबा होता है. डिज्नी+हॉटस्टार की यह सीरीज उस पर क्या रुख अख्तियार करती है? महेश (मांजरेकर, निर्देशक) उस मामले में खासे संवेदनशील हैं. मैं युद्ध-विरोधी हूँ, उसके पक्ष में जाने वाला कोई भी काम मैं नहीं कर सकता. यह सीरीज सैनिकों के परिजनों और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले युद्ध के असर पर केंद्रित है. इसी मामले में यह बाकियों से अलग है. यह नायकों ही नहीं, दुश्मनों के प्रति भी समानुभूति रखती है.

● आपकी फिल्मों ने आपकी स्वतंत्र सोच वाली संवेदनाओं का इजहार किया है. ओटीटी पर उनका प्रसारण क्या आपके लिए कोई कारगर विकल्प है? शुरु-शुरु में मैंने डेब्यू डायरेक्टर्स और नए लेखकों के साथ जोखिम लिया लेकिन सिमटते सिनेमाघरों के साथ वह संभावना भी सिमटती गई. मुख्य धारा में न गिनी जाने वाली प्रस्तुतियों के लिए स्वस्थ स्पर्धा की जगह है ओटीटी. उसका कंटेंट बॉलीवुड से कहीं बेहतर और व्यवस्थित है.

● समाज-राजनीति पर अपने विचार आप खुलकर साझा करते हैं. उसके नतीजों की आपको परवाह नहीं होती? आज हर बात पर किसी न किसी की भावनाएं आहत हो जा रही हैं. अपने बयानों का नतीजा मैं भुगतता रहा हूँ लेकिन मैं सच साफ-साफ बोलता आया हूँ, पर यह भी सच है कि मैं अपेक्षाकृत सुरक्षित हूँ और पुरुष हूँ. मैं सबको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा. जान बचाए रखना भी अहम है.

—सुहानी सिंह



INDIA
TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY



DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON



IndiaContent

**SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE**

